सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

06 मार्च, 2020

षोडश विधान सभा | शुक्रवार, तिथि 06 मार्च, 2020 ई0
पंचदश सत्र | 16 फाल्गुन, 1941 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री ललित कुमार यादव । यह स्थगित है । स्वास्थ्य विभाग ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 9 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में हार्ट अटैक के रोगियों को सामान्य चिकित्सीय उपचार के माध्यम से स्टैब्लाईज कर उच्च संस्थानों में उपचार हेतु रेफर किया जाता है।

2. उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 30 जिलों में ई0सी0जी0 सुविधा मरीजों को दी जा रही है । शेष 8 जिलों में प्रशिक्षित कर्मी विशेषज्ञ की अनुपलब्धता के कारण ई0सी0जी0 जांच की सुविधा वर्तमान में अनुपलब्ध है ।

(व्यवधान)

सदर अस्पतालों के एक स्टाफ नर्स एवं एक सक्षम स्वास्थ्य कर्मी को ई0सी0जी0 मशीन पर प्रशिक्षित किये जाने हेतु कार्यालय पत्र सख्ंया 8778 दिनांक 27.02.2020 के द्वारा जिलों से नामांकन मांगा गया है ।

3- राज्य में हार्ट अटैक के रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने हेतु पी0पी0पी0 मोड में कैथ लैब के संस्थापन हेतु निविदा प्रकाशित की गयी है । इसके अंतर्गत 7 चिकित्सा महाविद्यालयों में कैथ लैब संस्थापित कर उन्हें हब के रूप में 33 जिला अस्पतालों में हार्ट अटैक के रोगियों के डायग्नोसिस एवं सामान्य उपचार हेतु स्पोक के रूप में विकसित किया जाना है । इसके अन्तर्गत चिन्हित चिकित्सा महाविद्यालयों में कैथ लैब संस्थापित कर उन्हें हब के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें 24 X 7 कार्डियिक इमरजेंसी सेवा एवं प्राईमरी एनजीओग्राफी एवं एनजिओप्लास्टिक की सुविधायें उपलब्ध रहेगी । साथ ही यहां

टर्न-01/कृष्ण/06.03.20

हृदय संबंधी रोगों के स्क्रीनिंग की जायेगी एवं आवश्यक उपचार किया जायेगा । यहां ई0सी0जी0, इको कार्डियोग्राफी, होल्टर एवं ट्रेड मिल मशीन टेस्ट जैसे सभी प्रकार के अत्याधुनिक जांच किये जायेंगे । राज्य के 33 जिलों में 5 जिलों -कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, नालन्दा एवं पश्चिम चम्पारण को छोड़कर के सदर अस्पताल को स्पोक के रूप में विकसित किया जाना है । पूर्व में ई0सी0जी0 सुविधा उपलब्ध 30 सदर अस्पतालों सहित इन 33 सदर अस्पतालों में ई0सी0जी0 की सुविधा उपलब्ध होगी । प्राप्त ई0सी0जी0 रिपोर्ट को 5 से 10 मिनट के अंदर ऑन लाईन हब को प्रेषित की जायेगी, जहां विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांचकर चिकित्सीय सलाह दी जायेगी । इन सदर अस्पतालों में चेस्ट पेन के रोगियों में स्क्रीनिंग भी की जायेगी, जिसके उपरांत उन्हें अर्ली डायग्नोसिस की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि ससमय उपचार हेतु उन्हें हब में भेजा जा सके । इसके अतिरिक्त निजी सेवा प्रदाता द्वारा सदर अस्पताल के चिकित्सकों को कार्डियिक इमरजेंसी के लिये क्षमता संवर्द्धन हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत लंबा-चौड़ा था। लेकिन हमलोग कहते हैं कि हार्ट के जो रोगी होते हैं, उसको दो घंटे के अंदर यदि निकटवर्त्ती हार्ट अस्पताल में नहीं पहुंचाया जाता है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है । खासकर के गरीब लोगों के साथ ऐसा होता है । जो पैसे वाले लोग हैं, वे कहीं प्राईवेट अस्पताल में चले जाते हैं । तो हमने कहा कि 38 जिलों में हार्ट अटैक कार्डियिक केयर यूनिट की घोषणा ये करें, जिससे गरीब लोगों को लाभ हो। बस यही मेरा पूरक है ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, मैंने उसके संबंध में माननीय सदस्य को जवाब में बताया कि सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 13 (श्री समीर कुमार महासेठ) ।

(व्यवधान)

श्रीमती रंजू गीता : अध्यक्ष महोदय, 08 मार्च,2020 को महिला दिवस है । मुझे बोलने का अवसर दिया जाय ।

(इस अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष की सभी महिला माननीया सदस्यागण वेल में आकर कुछ कहने लगीं ।)

अध्यक्ष : चलिये । आपकी आवाज सुन ली गयी । हो गया । माननीय सदस्या श्रीमती रंजू जी, अब अपने स्थान पर चले जाईये, स्वीटी सीमा जी, अब अपने स्थान पर चले जाईये ।

(इस अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष की सभी महिला माननीया सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चलीं गयीं ।)

माननीय सदस्यगण, आप सभी अवगत हैं कि परसों यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है । आज के बाद जो सदन स्थगित होगा तो हमलोग फिर 16 मार्च को ही मिल पायेंगे । इस बीच में इस सदन की माननीया महिला सदस्यों ने एक तो यह अच्छा किया कि पूरे सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया कि दो दिन बाद महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आनेवाला है तो महिलाओं की एकता का प्रदर्शन आज सदन में हो गया । इसलिये हम संपूर्ण सदन की तरफ से आप सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो तो आगामी 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसपर पूरे विश्व के साथ-साथ अपने देश एवं विशेष रूप से अपने प्रदेश की महिलाओं को शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जो एकता, उत्साह एवं उल्लास उन्होंने आज सदन में दिखाया है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ की महिला माननीया सदस्यों ने, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि महिलाओं का भविष्य अपने प्रदेश में उज्जवल है ।

श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप महिला सदस्य नहीं हैं जो बीच में खड़े हो गये । बैठिये । बीच में बोलने की इजाजत सिर्फ महिलाओं को हमने दी थी । आप क्यों बोलने लगे ? आप महिला नहीं हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ । स्वास्थ्य मंत्री ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 13 (श्री समीर कुमार महासेठ)</u>

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 20 (श्री ललित कुमार यादव)</u>

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में बी0एम0एस0सी0एल0 के स्तर से ई0डी0ल0 में निहित दर अनुबंधित औषधियों की आपूर्त्ति की जाती है । ई0डी0ल0 में निहित 351 प्रकार की दवाओं में से वर्तमान में बी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा 218 प्रकार की औषधियों का

दर उपबंध किया गया है और इनमें से वर्तमान में 183 प्रकार की औषधियों की आपूर्त्ति जिलों में की जा रही है । इसके अतिरिक्त दवा मद में सरकार द्वारा आवंटित कुल राशि की 20 प्रतिशत जिलों को सीधे आवंटित होती है, जिससे जिला स्तर पर अन्य आवश्यक दवायें, जो निगम के स्तर पर उपलब्ध नहीं है, का क्रय कर उपलब्ध कराया जाता है । राज्य के सरकारी अस्पतालों में ई0डी0ल0 में निहित आवश्यक औषधियों की औसतन उपलब्धता अलग-अलग अस्पतालों की मैं बता देता हूं - जिला अस्पताल में ई0डी0ल0 दवाओं की संख्या ओ0पी0डी0 में 72 है, उपलब्धता 55 की है ।

टर्न-2/अंजनी-अभिनीत/ 06.03.2020

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : (क्रमशः) : आई0पी0डी0 में 100 ई0डी0एल0 की लिस्ट में है, जिसमें से 68 की उपलब्धता है, सब डिवीजनल हॉस्पीटल में ओ0पी0डी0 में 59 दवाईयों की आवश्यकता है, जिसमें 45 उपलब्ध है । आई0पी0डी0 में 68 की आवश्कता है, जिसमें 46 उपलब्ध है । पी0एच0सी0 में 51 दवाईयों की आवश्यकता है ओ0पी0डी0 में, जिसमें से 38 उपलब्ध है और आई0पी0डी0 में 37 दवाईयों की आवश्यकता है, जिसमें से 28 उपलब्ध है । जिलों में औषधियों की आपूर्ति एवं वितरण की ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु ड्रग एण्ड वैक्सिन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्वचालित किया गया है । इस ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत जिलों द्वारा ऑनलाईन इन्डेन्ट भेजा जाता है और बी0एम0आई0सी0एल0 के स्तर से औषधियों की फिजिकली आपूर्ति के साथ-साथ आपूर्ति की ऑनलाईन प्रविष्टि डी0वी0डी0एम0एस0 में किया जाता है। इसी प्रकार जिलांतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में भी औषधियों की फिजिकली आपूर्ति एवं वितरण संबंधी जानकारी की प्रविष्टि डी0वी0डी0एम0एस0 के माध्यम से किया जाना है। डी0वी0डी0एम0एस0 में आपूर्ति संबंधी प्रविष्टि अद्यतन एवं नियमित रूप से करने का अनुश्रवण किया जा रहा है ताकि रियल टाईम डाटा उपलब्ध हो सके।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के अस्पताल का भ्रमण करते हैं, इसमें गरीब मरीज ही अस्पताल में आते हैं और माननीय मंत्री जी ने जो कहा और जो हमने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में आधी से अधिक दवा नहीं मिलती है। महोदय, हम कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी, आप किस स्तर से जांच कराये हैं, हमलोग जब भी क्षेत्र में जाते हैं, जब भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, प्राइमरी अस्पताल हो या रेफरल अस्पताल हो, उसमें 10 परसेंट से ज्यादे दवा नहीं मिलती है। लोग अस्पताल के बगल

के दुकान से खरीदकर दवा लाते हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि दवा व्यवस्था आपका फेल है तो गरीब मरीज जो अपना दवा खरीदते हैं, उसका आप भुगतान करने का व्यवस्था रखते हैं? आप कोई ऐसा उपाय कीजिए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यह सिस्टम फेल नहीं है, बहुत ही दुरूस्त है और पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं माननीय सदस्यों की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ और जो हमने आंकड़ा दिया है, अब कागज पर काम नहीं होता है, अब ऑनलाईन सिस्टम है और इसको माननीय सदस्य कहीं भी देख सकते हैं, साफ्टवेयर है - ई-औषधि, इसमें आप देख सकते हैं कि आज कितनी दवाईयों का रेट कंट्रेक्ट हमारे बी0एम0आई0सी0एल0 ने किया हुआ है और उसमें से कितने का हमने और्डर दिया है, तीन वेयर हाउस हमारा है, तीनों वेयर हाउस में कितनी दवाईयां उपलब्ध है, अस्पतालों को कितनी दवाईयों की आपूर्ति की जा रही है, यह सब ऑनलाईन कोई भी आदमी देख सकता है ई-औषधि सिस्टम पर.......

अध्यक्ष : आप सूचना दे दीजिए । अगला प्रश्न भी आपका ही है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि यह जो आंकड़ा दिया गया है, वह पूरी जानकारी सही करके दिया गया है और जहां उपलब्धता नहीं है, जहां संख्या कम है, उसको हमने माना है। जहां दवाईयां कम हैं, मैंने माना है, जहां दवाईयां कम हैं तो कम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शत्-प्रतिशत दवाईयां दे रहा हूँ । औसतन जो उपलब्धता है, 75 प्रतिशत दवाईयों की उपलब्धता है और ये दवाईयां नहीं रहती हैं तो 20 प्रतिशत की राशि अलग से जिलों को दी जाती है कि जो दवा की आपूर्ति बी0एम0आई0सी0एल0 नहीं कर पा रही है, उसको स्थानीय स्तर पर क्रय किया जाय और उसके अलावे रोगी कल्याण समिति का भी पैसा होता है तो अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा इस बात की चिंता की जाती है और यदा-कदा मुझे भी जब इस प्रकार की शिकायत मिलती है कि कहीं अस्पताल में दवा लाने के लिए जबर्दस्ती कहा गया, तुरंत उसकी जांच कराता हूँ ।

श्री ललित कुमार यादव, महादेय, हमने सीधे कहा कि जनता द्वारा खरीदी गयी दवा की प्रतिपूर्ति करने का विचार सरकार का है कि नहीं, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि टाडी प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, मनीगाछी स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल मनीगाछी, सदर अस्पताल दरभंगा, तीन जगह हमने जांच किया है...

अध्यक्ष : आप अपने एरिया का हालचाल बता रहे हैं, प्रश्न में तीन जिला लिखे हैं अररिया, अरवल और औरंगाबाद ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दरभंगा में अभी सदर अस्पताल है ही नहीं, तो वे जाकर कहां से देख लिए । सदर अस्पताल की स्वीकृति अभी हमने दी है, आप अभी बोले हैं । दरभंगा सदर अस्पताल बोले । उसकी स्वीकृति अभी हमने दी है, उसके लिए आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि सदर अस्पताल की स्वीकृति हमने दी है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सदर प्रखंड दरभंगा में है, सदर प्रखंड अस्पताल है । आप उसको सदर अस्पताल समझ रहे हैं । हम सदर प्रखंड में अस्पताल कह रहे हैं पी0एच0सी0 है । माननीय मंत्री जी, पूरे सदन के सदस्य अवगत हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में पी0एच0सी0 अस्पताल है और रेफरल अस्पताल है । अगर सदन संतुष्ट है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, यदि सदन संतुष्ट नहीं है तो आप भी किसी क्षेत्र से आते हैं, यदि आप भी संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । यदि आप और सदन संतुष्ट नहीं हैं तो सदन की समिति से इसकी जांच करा दीजिए । माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं और जो प्रश्नकर्त्ता सदस्य कह रहे हैं, दोनों के बीच में जो अन्तर हो रहा है, एक सदन की कमिटी बना दीजिए । हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 10 परसेंट से ज्यादे दवा सरकारी अस्पताल में नहीं है ।

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि सभी जिला अस्पताल में और सभी मेडिकल कॉलेज में दवायें उपलब्ध हैं, कहीं 68 परसेंट, 70 परसेंट उपलब्ध है तो माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया, उस संबंध में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पटना मेडिकल कॉलेज में, रांची में गया था अपने 1 पेसेंट को देखने के लिए, वहां स्थिति यह है कि आधा से अधिक दवा लोगों को खरीदकर लाना पड़ता है तो क्या प्रतिपूर्त्ति करने का माननीय मंत्री जी विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : प्रतिपूर्त्ति की तो कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, प्रतिपूर्त्ति की कोई व्यवस्था नहीं है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं.-21(श्री ललित कुमार यादव)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को राज्यांश के रूप में 8.84 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ है एवं साथ ही 55 करोड़ रूपये की राशि पुनः राज्यांश के रूप में निर्गत करने हेतु आवंटनादेश प्राप्त हो गया है । विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 138.83 करोड़ रूपया बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2019 तक

85.50 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है एवं माह फरवरी, 2020 तक 102.66 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री महोदय जी का जवाब मान लिया जाय तो यह कह रहे हैं कि वर्ष 2018-19 में 138.33 करोड़ रूपये बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध 2019 में पढ़े 85.50 । यदि इन्हीं का आंकड़ा मान लिया जाय तो बहुत कम है । फिर 2020 में कह रहे हैं कि 102.66 करोड़ रूपये का व्यय किये हैं तो इनको जो राशि मिली है और प्रश्न में राशि को देखा जाय, प्रश्न में राशि का जिक्र है, जो 3200 करोड़ रूपये कर दिया गया, यानी जो राशि मिली इनको, बहुत कम खर्च किये । दूसरा जो इनको राशि मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिली । ये कहते हैं कि डबल इंजिन की सरकार है तो बिहार की जनता इससे क्यों वंचित रहेगी ? एक तो राशि कम खर्च किये, दूसरा इनको जो राशि मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली, यह दोनों में क्या कारण है, इसका औचित्य हमलोग जानना चाहते हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि जो राशि उपलब्ध हुई है, जो आवश्यकता थी, मैं इस योजना के संबंध में पहले माननीय सदस्य को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इस योजना की शुरूआत 2018 के सितम्बर महीने में ही हुई है और यह राष्ट्रीय योजना थी, नयी योजना थी और नयी योजना जब शुरू होती है तो अचानक से पूरी गति में नहीं आती है, फिर भी दिसम्बर, 2019 तक 60 प्रतिशत से अधिक राशि हमलोगों ने खर्च की और फरवरी के महीने तक 75 प्रतिशत राशि खर्च हो गयी है । दूसरा, माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न किया जाता है तो सही तथ्यात्मक जानकारी के साथ किया जाय । ये जो पूरा आंकड़ा दिये हैं 6400 करोड़ मिला, 3200 करोड़ मिला, अगर इतना करोड़ रूपया मिल जाये तो बहुत बड़ी बात हो जायेगी । हमारा तो इतना बजट भी नहीं है ।

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी आंकड़ा है, यह अखबार से डाटा आया था, यदि उसमें गलत डाटा आया......

अध्यक्ष : ललित जी, इतना अच्छा तो हम वहीं समाप्त कर दे रहे थे । आप मेरी बात सुन लीजिए, अखबार के आंकड़े पर सवाल पूछने का तरीका तय है । अखबार के आंकड़ों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर लें, तब ही रखें । अब आप क्या पूछना चाहते हैं पूछिए ।

श्री ललित कुमार यादव : मैंने उसी आधार पर पूछा है ।

टर्न-3/राजेश-राहुल/6.3.20

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, हम यह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है ....

अध्यक्ष: अब लीजिये, डबल इंजन पर वे क्या जवाब देंगे ?

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा है, ये वहीं आंकड़ा दें..........

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री भोला यादव: महोदय, एक मिनट सर । माननीय मंत्री जी जवाब दिए हैं कि पहला साल है, सब जगह अभी लागू नहीं हुआ है, अभी विलंब हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बहुत से सरकारी अस्पताल से ले करके प्राईवेट अस्पताल तक आयुष्मान भारत योजना के कार्य पर कोई निगाह नहीं देता है क्या इसको सुनिश्चित करने के लिए मंत्री जी सरकारी स्तर पर आदेश निर्गत करेंगे ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, हमारे यहां कुल 780 अस्पताल अभी तक इस कार्यक्रम के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं, इसमें लगभग 230 अस्पताल प्राईवेट हैं बाकी सब सरकारी अस्पताल हैं और सबकी मॉनिटरिंग होती है, यदि माननीय सदस्य को किसी अस्पताल के बारे में ऐसी सूचना है कि वहां आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे जानकारी दीजिए ।

श्री भोला यादव: महोदय, आयुष्मान भारत योजना का लाभ आई0जी0आई0एम0एस0 में नहीं मिल रहा है, वहां बंद है ।

अध्यक्ष: आप देख लीजिएगा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, हम जरूर देखेंगे ।

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 1039 (श्री अचमित ऋषिदेव)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज भरगामा प्रखण्ड को पूर्व में फारबीसगंज ग्रिड से 33 के0वी0 लाईन से विद्युत आपूर्ति की जाती थी परन्तु बाद में लोड बढ़ने के उपरान्त एक नए 33 के0वी0 लाईन द्वारा फारबीसगंज ग्रिड से रानीगंज पी0एस0एस0 को जोड़कर भरगामा प्रखंड को विद्युत आपूर्ति की जा रही है । अररिया में नए ग्रिड से रानीगंज के लिए एक नई 33 के0वी0 लाईन बी0आर0जी0एफ0-टू के अन्तर्गत बनाया जा रहा है, जिसको 15 मार्च, 2020 तक चालू करने का लक्ष्य है, साथ ही पुरानी 33 के0वी0 लाईन को फारबीसगंज

जी0एस0एस0 से रानीगंज पी0एस0एस0 को भी राज्य योजना के अन्तर्गत आर0 एण्ड एम0 किया जायेगा जिसे, मई, 2020 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है इस प्रकार से रानीगंज एवं भरगामा प्रखण्ड को तीन स्त्रोतों से 33 के0वी0 लाइनों से विद्युत की आपूर्ति होगी । वर्तमान में इस क्षेत्र रानीगंज पी0एस0एस0 के अलावा भरगामा, काला बलुआ, गुणबन्ती एवं खजुरी पी0एस0एस0 से विद्युत आपूर्ति की जा रही है, तीन 33 के0वी0 फीडर से विद्युत आपूर्ति होने पर रानीगंज एवं भरगामा क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार आएगा । इसका लक्ष्य मई, 2020 है । वर्तमान में अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड में 132/33 के0वी0 लाईन की कोई योजना नहीं है ।

श्री अचमित ऋषिदेवः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दो-तीन बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं-

1. पिछले साल गर्मी 2019-20 में 18 मेगावाट का लोड रानीगंज ने लिया था, उस वक्त काला बलुआ शक्ति उप-केन्द्र चालू नहीं था, काला बलुआ के आसपास के इलाके में पूर्णिया से विद्युत सप्लाई होता थी, अब काला बलुआ शक्ति उप-केन्द्र का लोड रानीगंज से लेगा, जिससे गर्मी में लोड 20 मेगावाट से अधिक हो जाएगा ।

2. ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण के लिए आठ एकड़ जमीन चाहिए, जबकि रानीगंज में 12 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है, जिसमें विभाग को कोई कॉस्ट नहीं लगेगा ।

अध्यक्षः अचमित जी, इतना लंबा पूरक क्यों पूंछते हैं कि कोई अर्थ ही नहीं निकले, उन्होंने कहा है कि अभी कोई योजना नहीं है और आप चाहते हैं, तो उसके लिए तथ्य के साथ मंत्री जी को लिख कर दीजिएगा, बात कर लीजिएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1040 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्याः 1041 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आई0पी0डी0एस0 की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत मोतिहारी शहर में जर्जर तार एवं पोल के सुदृढ़ीकरण का कार्यादेश दिसम्बर, 2016 को दिया गया था । पी0एफ0सी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्य की अवधि मार्च, 2020 है । इस योजना के अन्तर्गत मोतिहारी शहर में 64 कि0मी0 जर्जर एल0टी0 तारों को एल0टी0ए0बी0 केबुल से बदलकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है । स्वीकृत योजना के अनुरूप शेष बचे कार्य को पूरा करने का लक्ष्य मार्च, 2020 है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, पहले भी दिनांक 5.12.2016 को आदेश हुआ था कि 17 दिसम्बर तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा, तो इन तीन साढ़े, तीन वर्षों, मात्र 127 किलोमीटर तार ही बदले जा चुके हैं, अभी भी लगभग 70 किलोमीटर तार बदले जाने शेष हैं तो आज 6 तारीख आ हो गई, तो क्या हम समझ पाएं कि 24 दिनों में ये तार

पूरे बदल दिए जाएंगे और तार बदलना है, तो किस कंपनी को इसकी ठीकेदारी दी गई है, कौन सी कंपनी इनको बदलेगी, यह आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री ने किस कंपनी को इसका ठीका दिया है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह ठीका पी0एफ0सी0 को दिया गया है और मार्च, 20 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है, तो इसको पूरा कर लिया जाएगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1042 (श्री विजय शंकर दूबे)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तााारांकित प्रश्न संख्या: 1043 (श्री विजय शंकर दूबे)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 19.07.2019 को मदन सिंह, पिता राजनारायण सिंह, ग्राम-पोस्ट बंगरा, थाना-दाउदपुर, जिला-सारण की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-254 सहपठित ज्ञापांक-195 दिनांक 18.02.2020 द्वारा मुआवजा राशि रू0 4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान चेक संख्या-235305 दिनांक 25.02.2020 द्वारा मृतक के आश्रित को कर दिया गया है ।

श्री विजय शंकर दूबे: महोदय, माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1044 (श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, बक्सर में मूर्छक एवं दो चिकित्सक जो स्पाईनल एनेस्थेसिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, सदर अस्पताल बक्सर में पदस्थापित थे । कर्त्तव्यहीनता के आरोप में वर्तमान में तीनों चिकित्सकों को विभाग द्वारा निलम्बित कर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है । सदर अस्पताल, बक्सर में मरीजों को सुचारू चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डा0 सुधीर कुमार, अनुमंडलीय अस्पताल, डुमरांव जो स्पाईनल एनेस्थेसिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, को सप्ताह में पांच दिन (मंगलवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार एवं शनिवार) प्रतिनियुक्ति कर कार्य लिया जाता रहा है । राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों की भारी कमी है, इस कमी को दूर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2425 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । आयोग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है । आयोग से

चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं लेकिन डॉ0 सुधीर कुमार जो डुमराव बैठते हैं, वे एक दिन भी जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में नहीं बैठते हैं और मरीजों को इससे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनको नियमित बक्सर जिला के अस्पताल में बैठाने की अनुमति प्रदान करे और ये यह कब करेंगे ये बता दें ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

टर्न-4/सत्येन्द्र-मुकुल/06-03-2020

तारांकित प्रश्न संख्या-1045(श्री सैयद अबु दौजाना)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल स्थित पुपरी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में एक अतिरिक्त 10 एम0वी0ए0 का पावर ट्रांसफर्मर लगाकर के समस्या का समाधान कर दिया गया है। वर्तमान में पुपरी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में कुल स्थापित क्षमता 10 एम0वी0ए0 का दो, 5 एम0वी0ए0 का 1, कुल 25 एम0वी0ए0 की क्षमता कर दी गयी है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1046 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव)

अध्यक्ष: यह स्थानांतरित हो गया है जल संसाधन विभाग को। स्थगित हुआ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1047 (श्री जीवेश कुमार)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि डॉ0 रामप्रीत राम चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाले को ब्लड बैंक डी0एम0सी0एच0 दरभंगा में ब्लड स्टोरेज संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा गया। डॉ0 राम द्वारा दिनांक 24.2.2020 से 01.03.2020 तक एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। रेफरल अस्पताल, जाले में ब्लड स्टोरेज यूनिट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए एक पक्ष में ब्लड स्टोरेज यूनिट प्रारंभ किया जा सकेगा।

श्री जीवेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कबतक होगा, एक बार और यहां ब्लड स्टोरेज प्रारंभ करने के लिए पिछली सरकार ने आर्डर किया था तो जो डॉ॰ स्पेशलिस्ट वहां गये थे, वे वी0आर0एस0 ले लिये । उसके बाद से वह योंही

पड़ा हुआ है । दरभंगा मुख्यालय से 45 कि0मी0 की दूरी पर वह अस्पताल है जहां महीने में 10 हजार से अधिक...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, मैंने एक पक्ष बोला माननीय सदस्य ने सुना नहीं, एक पक्ष बोला जीवेश जी धन्यवाद दीजिये कि हां एक पक्ष में कर देंगे इसके लिए।

श्री जीवेश कुमारः अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न संख्या 1048(श्री आबिदुर रहमान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, अररिया प्रखंड के प्रश्नाधीन पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं0-8 डीहा ग्राम में नये बसावटों की विद्युतीकरण का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2020 है।

श्री आबिदुर रहमानः शुक्रिया सर।

तारांकित प्रश्न संख्या-1049(श्री सुरेन्द्र कुमार)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटरा प्रखंड के जजुआर अस्पताल में चिकित्सकों का दो पथ स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध एक संविदा चिकित्सक डॉ0 सुमन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं। मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जाता है। भवन की मरम्मति आवश्यक है, इस हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को विभागीय पत्रांक-335(2), दिनांक-04.03.2020 द्वारा प्राक्कलन बनाने का निर्देश दिया गया है। निधि की उपलब्धता के अनुसार भवन की मरम्मति अगले वित्तीय वर्ष में करा दी जायेगी। राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने हेतु विभाग द्वारा 2425 विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं 4012 सामान्य चिकित्सकों कुल 6437 चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गयी है, जिसकी काउन्सिलिंग की कार्रवाई की जा रही है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना की जा सकेगी।

श्री सुरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदय, औराई विधान-सभा के कटरा प्रखंड के 14 पंचायत के मध्य एक जजुआर अस्पताल है। पहले वह फुलफ्लेज अस्पताल था लेकिन अभी वर्तमान में वह एकदम जर्जर हो चुका है। माननीय मंत्री महोदय जी साल भर पहले वहां गये थे तो मरम्मति का काम डेंटिंग-पेंटिंग हुआ था लेकिन अभी वस्तुस्थिति यही है कि जो डॉ0 वहां पर पदस्थापित हैं, वे भी वहां नहीं बैठते हैं और वहां से कटरा जो मुख्यालय है उसकी दूरी लगभग 10 कि0मी0 है और बीच में बागमती नदी है,

उसमें एक भी पुल नहीं है । इसलिए 14 पंचायत के लोगों को या तो दरभंगा जाना पड़ता है या तो उधर नानपुर पुपरी जाना पड़ता है या औराई भी दूरी पर है। इसलिए आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि प्राथमिकता के आधार पर वह जो जजुआर घनी आबादी है 14 पंचायत का और आप गये भी थे वहां, बहुत बुरी स्थिति है और जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं उनको इलाज कराने में काफी कठिनाई होती है इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह है कि भवन का निर्माण कराते हुए और एक परमानेंट डॉक्टर की पूरी जो टीम होती है अस्पताल का, वहां पर स्थापित करें, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: मैंने महोदय कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में इसको कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1050(श्री शम्भूनाथ यादव)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि चक्की प्रखंड में अपने जमीन पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया जा रहा था, परन्तु विवादित होने के कारण निर्माण कार्य अधूरा है। यह मामला न्यायालय में लम्बित है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चक्की पंचायत भवन में संचालित एवं कार्यरत है।

श्री शम्भूनाथ यादव: महोदय, जानकारी के अभाव में बी.डी.ओ., सी.ओ. के चलते वह विवादित में पड़ गया। महोदय, वह पहले से है, यह दूसरे की जमीन थी। यह दियारा इलाका है महोदय, इतनी कठिनाई हो रही है और मैं पूरे पांच साल इस क्वेश्चन को करता रहा हूं लेकिन इसका कोई आज तक हल नहीं निकला महोदय।

अध्यक्ष: ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1051 (श्री जयवर्धन यादव)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन के अनुसार दुल्हिनबाजार अंचल अंतर्गत सिही पंचायत के वर्ष 2019 में सुखाड़ से सम्बन्धित पंचायत की जांच विधिवत टीम गठित कराकर की गई थी जिसमें पंचायत सचिव के नेतृत्व में कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार एवं विकास मित्र शामिल थे। सुखाड़ प्रभावित परिवारों की सूची विधिवत जांचोपरांत सम्पूर्ति पोर्टल पर अंचल लिपिक दुल्हिनबाजार की देखरेख में प्रविष्टि कराई गई। प्रवृष्टि में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई। सिही पंचायत में कुल 1529 सुखाड़ प्रभावित परिवारों की सूची सम्पूर्ति पोर्टल पर प्रविष्टि कर राशि का हस्तातंरण किया गया।

2. दुल्हिनबाजार अंचल अन्तर्गत वर्ष 2019 में 1529 सुखाड़ प्रभावित परिवारों को विधिवत जांचोपरांत ही सम्पूर्ति पोर्टल पर प्रविष्टि की गई। सुखाड़ प्रभावित परिवारों की

सम्पूर्ति पोर्टल पर प्रविष्टि के समय सिही पंचायत के 1529 प्रभावित परिवारों के अलावे अन्य परिवारों के द्वारा उस समय राहत हेतु कोई दावा भी नहीं किया गया। सुखाड़ प्रभावित कोई भी परिवार को लाभ से वंचित नहीं रखा गया है।

3. उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री जयवर्धन यादव: महोदय, मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो मेरा प्रश्न है उसमें ये अगर मंत्री जी पुन: जांच करवा लेते हैं एक बार और, मेरा तो आरोप जो इन्होंने टीम गठित की थी उसके सदस्यों पर ही है। उन लोगों ने कई प्रभावशाली व्यक्तियों के यहां बैठकर के इस सूची को बना दिया है और कई लाभुक उस सूची में छूट गये हैं तो महोदय, मेरा पूरक प्रश्न होगा कि इसकी पुन: जांच करवा लें, उच्चस्तरीय जांच करा लें।

अध्यक्ष: आप इन सब बातों का एक विस्तृत विवरण लिखकर दे दीजिए, वे जांच करा देंगे।

श्री जयवर्धन यादव: जी महोदय, धन्यवाद।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: इस प्रश्न से ही जांच हो सकती है क्या, जब तक कोई स्पेशफिक सूचना नहीं मिलेगी। ललित जी, बात समझकर न पूरक पूछिये, प्रश्न में जो चीजें हैं, उसका जवाब तो सरकार ने दे ही दिया । अब वह कह रहे हैं अलग से कि कुछ लोगों को छोड़ा गया है तो वे वह सूचना देंगे, उसकी अलग से जांच करा दी जायेगी।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या: 1052 (श्री मुजाहिद आलम)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री: महोदय, अनुग्रह अनुदान से संबंधित है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज के प्रतिवेदन अनुसार मृतक मनवर आलम, पिता-अजीमुद्दीन, साकिन मिर्जाबाग को अनुग्रह अनुदान से संबंधित अभिलेख को स्वीकृत कर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

श्री मुजाहिद आलम: धन्यवाद, सर।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1053 (श्री महबूब आलम)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री: महोदय, जिला पदाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदन के अनुसार कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल अंतर्गत बलरामपुर अंचल में गत वर्ष जुलाई, 2019 फेज-1 में आई बाढ़ से प्रभावित 25,306 परिवारों को बाढ़ सहाय्य राशि 6000 रुपया प्रति परिवार की दर से 15 करोड़ 18 लाख 36 हजार रुपया पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। राज्य में प्रथम फेज की बाढ़ माह जुलाई, 2019 में आई थी । प्रभावित परिवारों को पूरे राज्य में समान्यतया दो से ढाई महीना के अंदर बाढ़ सहाय्य राशि का भुगतान किया जा चुका है।

...क्रमश:...

टर्न-5/मधुप-हेमंत/06.03.2020

...क्रमशः...

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : बाढ़ के इतने समय बीत जाने के पश्चात् अंचलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा 6963 परिवारों की सूची पुनः आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना जॉंच का विषय है तथा कर्त्तव्य के प्रति उनकी उदासीनता एवं घोर लापरवाही का द्योतक है । इस सन्दर्भ में अंचलाधिकारी, बलरामपुर के विरुद्ध प्रपत्र-क गठित करते हुए अपलोड की गई सूची की सत्यता की जॉंच अपने से स्तर से करते हुए अग्रेतर कार्रवाई का निर्देश जिला पदाधिकारी, कटिहार को दे दिया गया है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, अंचल पदाधिकारी ने जब 6963 प्रभावित परिवारों का प्रतिवेदन दे दिया और उस वक्त बाढ़ से घिरा हुआ बलरामपुर क्षेत्र है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी यहॉं सदन में बयान दिया कि बलरामपुर क्षेत्र का विशेष रूप से हवाई सर्वेक्षण किया है, ऐसी परिस्थिति में बलरामपुर से कटिहार आना कितना दुर्गम है महोदय, तो अंचल पदाधिकारी ने कितनी मेहनत कटिहार जिला में....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न । वह तो आप लिखे ही हैं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, रिपोर्ट देने के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट को स्वीकार क्यों नहीं किया गया और जिस पदाधिकारी ने आपदा प्रबंधन या आई0टी0 मैनेजर ने जो स्वीकार नहीं किया, उसपर कोई कार्रवाई करने का विचार माननीय मंत्री रखते हैं कि नहीं रखते हैं? प्रभावित परिवारों को अनुदान देने का विचार रखते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : वह तो बोल दिये हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं । बता दीजिए मंत्री जी, फिर से ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय...

श्री महबूब आलम : आप तो अंचल पदाधिकारी पर कार्रवाई कर रहे हैं ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, बाढ़ में जो सहायता दी जाती है, उसकी समय-सीमा होती है और समय-सीमा के अन्दर यदि नहीं किया गया तो निश्चित रूप से उसकी लापरवाही है, जॉंच होनी ही चाहिए । जो आप कह रहे हैं उसी आधार पर कार्रवाई की भी गयी है । यदि वह सही पाया गया तो...

श्री महबूब आलम : समय-सीमा की गड़बड़ी तो आपकी न है ? तो आपकी गड़बड़ी से प्रभावित परिवार क्यों वंचित हो ?

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : इसीलिये गड़बड़ी है कि इस देश में पहला बिहार राज्य है, जहॉं आपदा पीड़ितों को सात दिन के अन्दर राहत दी जा रही है....

श्री महबूब आलम : भाषण मत दीजिये ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : सुना जाय । महोदय, देश में यह पहला राज्य है....

श्री महबूब आलम : महोदय, ये भाषण दे रहे हैं ? महोदय, 6963 पीड़ित परिवारों को सहायता राशि मिलेगी या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी....

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण कर लीजिये । प्रश्नकाल में... (व्यवधान)

वीरेन्द्र जी, भाषण तो नहीं चलेगा लेकिन बैठे-बैठे बोलना चलेगा ! दोनों नहीं चलेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, यह हमारा अधिकार है ।

अध्यक्ष : बैठे-बैठे बोलने का ? बैठे-बैठे बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है ।

श्री भोला यादव : महोदय, आसन से आग्रह है कि जो सरकार में माननीय मंत्री लोग हैं, वह कम से कम अंगुली दिखाकर वार्त्ता नहीं करें...

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, अति पिछड़ा के मंत्री जब भी बोलते हैं तो इनलोगों को पता नहीं क्या हो जाता है ? वह जमाना चला गया जब अति पिछड़ा आपसे डरता था, वह जमाना चला गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए । आप बैठ जाइये न ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मेरा ध्यान अभी डॉ0 रवीन्द्र यादव जी की तरफ गया है, आपके कहने का असर हुआ है, टोपी बदल गयी है रवीन्द्र यादव जी की ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, कितना गम्भीर मामला है, बाढ़ पीड़ितों का सवाल है और यहाँ मजाक चल रहा है ? सरकार बाढ़ पीड़ितों के सवाल का.....

अध्यक्ष : आपको लगता है कि देर से समझ में आया कि गम्भीर मामला है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, ये लोग मजाक कर रहे हैं । जवाब नहीं आ रहा है, सरकार जवाब नहीं दे रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आप बैठिये न । महबूब जी, बैठिये । (व्यवधान)

रवीन्द्र जी, कम से कम आप टोपी बदलकर तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पहुंच गये । क्या कह रहे हैं ?

डॉ0 रवीन्द्र यादव : महोदय, ये आसन की तरफ अंगुली उठाकर बात करते हैं और बैठे-बैठे बोलते हैं। इनको सदन से निष्कासित कर दिया जाय, सर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अवधेश जी, क्या कहना है ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी जॉच जिला पदाधिकारी से करा रहे हैं, माननीय सदस्य ने स्पष्ट लिखा कि इस सूची को हमने जिला पदाधिकारी को दी, जिला पदाधिकारी ने सूची को अंचलाधिकारी के पास भेजा, अंचलाधिकारी ने इसकी जॉच की, एस0डी0ओ0 ने इसपर अनुशंसा की और आई0टी0 मैनेजर ने इसको रद्दी कागज में रख दिया । यह क्वेश्चन है ।

माननीय मंत्री जी से मेरा कहना यह है कि आपने कहा कि अंचलाधिकारी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जब आप कार्रवाई कर रहे हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं ? अनुमंडल पदाधिकारी ने अगर अनुशंसा की है तो इन लाभुकों को आप भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं ? यह बहुत स्पष्ट है, अध्यक्ष महोदय । इसमें गुमराह करने की जरूरत नहीं है ।

महोदय, माननीय मंत्री जी बड़े काबिल मंत्री हैं, पूरे देश में राज्य में पहली बार बॅटवा रहे हैं.....

अध्यक्ष : अब आप भी उधर ही जा रहे हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : नहीं, हम नहीं जा रहे हैं । सुन लीजिये । हम उधर नहीं जायेंगे ।

मेरा कहना है कि इस सूची को....

अध्यक्ष : अब आप बैठिये । आपको जो पूछना था, पूछ चुके । अब आप बैठ जाइये ।

माननीय मंत्री जी, एक बार फिर से बता दीजिये वस्तुस्थिति इसके बारे में जो लिखा है कि 6963 परिवारों की अनुशंसा या जॉच करके, जिस भी स्तर से हुई थी कि कितने को भुगतान हुआ, कितने को नहीं हुआ, क्या स्थिति है, एक बार फिर से स्थिर से बता दीजिये ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी को अपने स्तर से जॉच के लिए उनसे आग्रह किया गया है । जॉच रिपोर्ट आयेगी, उसके बाद अगर सत्यता पायी जायेगी तो शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : महबूब जी, अब सुन लीजिये । माननीय मंत्री जी का कहना यही है कि इस सारे मामले पर उन्होंने कलक्टर को खुद से जॉच करने के लिए कहा है और जिसकी भी संलिप्तता, गड़बड़ी में या जिसकी नेगलीजेंसी पायी जायेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी । 1054 - श्री संजय कुमार तिवारी ।

(व्यवधान)

आप कार्रवाई नहीं चाहते हैं ?

मंत्री जी, जो लाभुक हैं, जो suffer कर रहे हैं, उनके भुगतान की भी व्यवस्था की जाय ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : निश्चित । एक भी बाढ़ पीड़ित वंचित नहीं रहेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1054 (श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । सम्प्रति सदर अस्पताल, बक्सर में एक भी चिकित्सा पदाधिकारी 20 वर्ष से पदस्थापित नहीं है ।

वास्तविकता है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी ही सबको नियम सुनाते हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी की अतिशय कमी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : रवीन्द्र जी, आप भी कम नहीं हैं । केवल आप दोनों आदमी - भाई वीरेन्द्र जी और रवीन्द्र जी, यह सोच लीजिए कि अगर आपके जैसे 5-10 सदस्य भी हो जायं तो सदन चलेगा क्या ? ये लोग बैठे-बैठे बात करते रहेंगे ।

टर्न-6/आजाद:अंजली/06.03.2020

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, आप बैठे-बैठे बोलने की आदत छोड़ दीजिए । क्या ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, उनमें और हममें एक समान तुलना मत कीजिए ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, सुन लीजिए न । आप पहले बैठ जाईए । इस सदन के हर माननीय सदस्य का अपना अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी आभा है । किसी को किसी से मिलाया नहीं जा सकता है । सिर्फ बैठे-बैठे बोलने की आदत दोनों की मिलती है, वह नहीं होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

जो भी बोलते हैं, वे गलत बोलते हैं । श्री संजय कुमार तिवारी का जवाब दीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1054 (श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

सम्प्रति सदर अस्पताल, बक्सर में एक भी चिकित्सा पदाधिकारी 20 वर्ष से पदस्थापित नहीं हैं ।

वास्तविकता है कि राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी की अतिशय कमी है । इस स्थिति में लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से चिकित्सा पदाधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया, यह बिल्कुल वहां का लिखा और रटाया जवाब आया है और इसकी जॉच स्वयं मंत्री जी करा लें कि 20 से 25 वर्षों तक के डॉक्टर वहां पदस्थापित हैं, निजी क्लीनिक चलाते हैं और सदर अस्पताल में जो भी गरीब-गुरबे मरीज आते हैं, उनको चिट्ठी पर लिखकर दिया जाता है कि फलाने क्लिनिक पर आ जाईयेगा । वे अपनी मनमानी से वहां काम करते हैं और मैं माननीय मंत्री जी से आसन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसकी स्वयं जॉच करा लें और वहां पर जो 20-25 वर्षों से डॉक्टर पदस्थापित हैं, उनको वहां से हटाने का काम करें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : ऐसा कोई चिकित्सक माननीय सदस्य के ध्यान में है तो उसकी सूचना हमें दे दें, मैं अपने स्तर से इसकी जॉच कराकर कठोरतम कार्रवाई करेंगे ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : जी, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1055 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि शिमलापाड़ा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न होकर वहां स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसका भवन जर्जर है । इस भवन का जीर्णोद्धार/नये भवन निर्माण हेतु (BMSICL) से प्रतिवेदन की मांग की गयी है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भवन का जीर्णोद्धार/नये भवन निर्माण की कार्रवाई विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-1056 (श्री राज किशोर सिंह)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है क वैशाली प्रखंड अंतर्गत अबुल हसनपुर का भवन दिनांक 02.03.2020 को जमीन के दानकर्त्ता द्वारा स्वास्थ्य केंद्र भवन में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को हस्तगत करा दी गई है । एक सप्ताह के अन्दर संचालित कर दिया जाएगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1057 (श्री राजेन्द्र कुमार)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी के तुरकौलिया प्रखण्ड के जयसिंह पंचायत के रेतवा ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है तथा हरसिद्धि प्रखण्ड के घीवाढार पंचायत के दक्षिणी टोला में बांस-बल्ला द्वारा विद्युत का उपभोग किया जा रहा है । मार्च, 2020 तक लाईनों का सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य है।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहेंगे कि जो भी उत्तर दिये गये हैं, वह सत्य से परे हैं । वहां की हालत यह है कि तकरीबन दो वर्षों से लगातार आवेदन दिये जा रहे हैं, 2021 तक कहा जा रहा है । जहां सरकार दावा करती है कि हम शत-प्रतिशत बिजली उपलब्ध कर दिये हैं, वहां आज भी लोग अँधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं और जहां विद्युतीकरण हो गया है, अभी तक कई गांवों में तार जर्जर है, पोल जर्जर है, टूटकर गिरने से कई लोग घायल हो गये, कई लोग मौत के घाट उतर गये । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो जर्जर तार एवं पोल है, उसको बदलवाने एवं जो बाकी विद्युतीकरण है, उसको विद्युतीकरण कराने का विचार रखते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैंने कहा कि जो बचा हुआ काम है, वह मार्च तक हो जायेगा और माननीय सदस्य जो जर्जर तार की बात करते हैं, लिखकर उसका भेजवा दें, हम दिखवा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1058 (श्री नीरज कुमार सिंह)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि चरनैय स्वास्थ्य उपकेन्द्र जर्जर स्थिति में है, परन्तु उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में नियमित टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम पदस्थापित ए0एन0एम0 के द्वारा किया जा रहा है ।

इस भवन के नव निर्माण हेतु (BMSICL) से स्थल-निरीक्षण प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नये भवन निर्माण की कार्रवाई विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1059 (सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1060 (श्री विजय कुमार खेमका)</u>

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया में वर्तमान समय में 12 सत्र न्यायालय कार्यरत है, जिसके लिए 36 अपर लोक अभियोजक अनुमान्य है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । विधि विभागीय संकल्प सं0-8186/जे0, दिनांक-08.11.2012 के अनुपालन में अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति में कुल पद का 50 प्रतिशत अधिवक्ता वर्ग से एवं 50 प्रतिशत अभियोजन सेवा संवर्ग से नियुक्त किया जाना है । उक्त प्रावधान के अनुसार व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया में अधिवक्ता वर्ग से 11 अपर लोक अभियोजक कार्यरत है एवं अभियोजन सेवा संवर्ग के अभियोजन पदाधिकारी वर्ग से 4 अपर लोक अभियोजक कार्यरत है ।

पूर्णिया जिला के लिए अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से अनुशंसा सूची की मांग की गई है । अनुशंसा सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, आपके आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसको शीघ्रातिशीघ्र कर दें तो न्यायालय के कार्य में कठिनाई होगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1061 (श्री अशोक कुमार सिंह)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सढ़ैल वर्त्तमान में पुस्तकालय के भवन में चल रहा है । भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता संबंधी अभिलेख अप्राप्त है । भूमि उपलब्ध कराने हेतु समाहर्त्ता, औरंगाबाद से अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर विहित प्रक्रियानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अशोक कुमार सिंह : सर, वहां भूमि उपलब्ध है, भवन आधा बना है और आधा नहीं बन पाया है । भूमि है, इसलिए आधा निर्माण हो चुका है, जर्जर स्थिति में है, ढ़लाई वगैरह नहीं हुआ है, उसी पर उसको बनवा दीजिए ।

अध्यक्ष : जल्दी संतुष्ट हो जाईयेगा तो आपका अगला भी प्रश्न आ जायेगा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : इसकी जानकारी उपलब्ध करा दें माननीय सदस्य ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1062 (श्री अशोक कुमार सिंह)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण ICU के संचालन में कठिनाई हो रही है । इस कमी को दूर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2425 विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं 4012 सामान्य चिकित्सकों अर्थात् 6437 चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । आयोग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु Counselling की कार्रवाई की जा रही है ।

आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना सदर अस्पताल, औरंगाबाद में की जा सकेगी ताकि ICU का संचालन किया जा सके।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, लगभग 34-35 माह से आई0सी0यू0 बनकर तैयार है और प्राकृतिक आपदा से पिछले वर्ष लू से दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई थी और जी0टी0 रोड पर औरंगाबाद स्थित है एन0एच0-2 पर, दुर्घटनायें बहुत घटती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि समय सीमा के अन्दर, यह तो ऐसे ही लेट हो चुका है, 34-35 महीना से आई0सी0यू0 बन्द पड़ा है । इसलिए हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी आई0सी0यू0 वहां चालू हो जाता तो मरीजों का सही ढंग से इलाज हो पाता ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं ।

अब शून्य-काल ।

टर्न-7/शंभु-धीरेन्द्र/06.03.2020

शून्यकाल

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत बीज वितरण हेतु प्रत्येक प्रखंड में बी0आर0बी0एन0 का डीलर नियुक्त किया गया है, परन्तु जिला कृषि पदाधिकारी, गया के द्वारा मात्र दो ही डीलरों से बीज वितरण कराया जा रहा है । प्रत्येक प्रखंडों में बी0आर0बी0एन0 के द्वारा नियुक्त डीलरों से बीज वितरण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री सुधीर कुमार : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखंड के निम्न नवादा पंचायत के सुअरकोल और भगरार के बीच बुनबुनी नदी पर पुल का निर्माण कराने हेतु, सदन के माध्यम से सरकार को सूचना देता हूँ ।

श्री संजय कुमार तिवारी : बक्सर जिले के 465 मध्य विद्यालयों में से एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है जिससे विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था तथा शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । साथ ही कई मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हो गए हैं । मध्य विद्यालयों में पूर्ण कालिक प्रधानाध्यापक की प्रतिनियुक्ति हो ।

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत आरा नगर निगम के सिटी मैनेजर शहर के साफ-सफाई का स्थल निरीक्षण नहीं करते हैं, उनकी लापरवाही से शहर के मुख्य पथों पर कूड़ा एवं नालों का पानी बह रहा है । सरकार सिटी मैनेजर के विरूद्ध कारवाई एवं जॉच करे ।

श्री रामविलास पासवान : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव प्रखंड विक्रमशीला विश्वविद्यालय सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैया के चलते विकास एवं पर्यटक के रूप में विकसित नहीं हो पा रहा है, जिसमें ऐतिहासिक धरोहर परिणत के कगार पर है । अत: सरकार से विक्रमशीला विश्वविद्यालय का विकास करने का मॉग करता हूँ ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखंड के एन0एच0-2 से ग्राम-मोर के पूरब छवर होते हुए महादलित मुसहर टोला तक 2 कि0मी0 तक मार्ग संपर्क पथ विहीन है । सरकार उक्त सड़क का शीघ्र पक्कीकरण करावें ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, नदी जोड़ योजना से कोसी मेची लिंक सरकार की प्राथमिकता में रहने के बावजूद इसके कार्यान्वयन में विलंब से सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार के 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचाई लाभ से वंचित हैं । अत: मैं सरकार से उक्त योजना का शीघ्र कार्यान्वयन कराने की मांग करता हूँ ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड के नोनीमल चौक से इसमइला होते हुए धपहर सिमान तक पथ जो घना बसावट क्षेत्र होने के बावजूद कोर नेटवर्क में नहीं रहने से अबतक सड़क निर्माण नहीं हो पाया है । उस पथ को कोर-नेटवर्क में जोड़कर पक्कीकरण कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज विधानसभा के नगर परिषद अंतर्गत चॉंदनी चौक से अनुमण्डल मुख्यालय तक जानेवाली जर्जर पथ को बनाने की मैं मांग करती हूँ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला में चीनी मिलों में गन्ना किसानों के द्वारा दिये गये गन्ना की तौल में काफी अनियमितता बरता जा रहा है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है । अत: किसान हित में इसकी जांच कराकर अनियमितता पर शीघ्र सरकार रोक लगाये ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अध्यक्ष महोदय, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जाह्न्वी चौक-इस्माइलपुर तक 10.5 किलोमीटर गंगा कटाव से बचाव हेतु रिंग बान्ध का निर्माण फरवरी 2018 में प्रारम्भ हुआ था, लेकिन 4.5 किलोमीटर के निर्माण के बाद कार्य बंद है । अतएव दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर उक्त रिंग बान्ध का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कोरोना वायरस से बचाव के लिये ऐहतियाती उपाय यथा मास्क, हैण्डवॉश, टिसू-पेपर सहित अन्य आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सर्व-साधारण हेतु सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराने तथा आवश्यक जानकारी देने हेतु डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निदेशित करने का सरकार से मॉंग करता हूँ ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा चीनी मिल, गन्ना पेराई का 28.02. 2019 तक का ही भुगतान किया है । अभी भी 80 करोड़ रुपया बकाया है । किसान गन्ना पेराई राशि पर ही आश्रित है । भुगतान के अभाव में किसान परेशान हैं । किसान हित में बकाये राशि का भुगतान करावे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान सभा अंतर्गत पान्नापुर रंजीता पंचायत के मुख्य मार्ग में धनवति नदी पर पुराना पुल ध्वस्त हो गया है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, यह पुल दो प्रखण्डों को जोड़ती है । अत: जनहित में उक्त पुल अविलम्ब बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, पटना-सिटी के जल्ला से पानी निकासी वाले नहर पर लंबे समय से भूस्वामियों-दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है जिसके कारण जल्ला का पानी गंगा नदी में नहीं जा पाता, विगत दिनों पटना में भीषण जलजमाव का यह एक प्रमुख कारण था । नहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग करता हूँ ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. जगन्नाथ मिश्र जी का आदम कद प्रतिमा पटना में लगाया जाय और इनके जन्म तिथि 24 जून को सरकारी समारोह के तहत मनाया जाय ।

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के साढ़े चार लाख शिक्षक एवं शिक्षिका समान काम के समान वेतन के लिए हड़ताल पर हैं । जिसके कारण पठन-पाठन बंद है । इसलिए नियोजित शिक्षकों एवं शिक्षिका के सभी मांगों को पूरा करने की मांग करता हूँ।

डॉ0 शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखण्ड अन्तर्गत सिसवा गोखुला-सुन्दरपुर पथ में बूढ़ी गंडक नदी के उपर सुन्दरपुर घाट के समीप उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया जाये ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल कोर्ट परिसर में कोर्ट की सारी सुविधा उपलब्ध है, परन्तु कोर्ट में अभी तक एडिशनल जज एवं सब जज कोर्ट का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है । इस कोर्ट का निर्माण लगभग 15 वर्ष पहले हुआ है । तत्काल दोनों सुविधाा उपलब्ध करावें ।

डा0 फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के प्रखण्ड सिंहवाड़ा केवटी सहित अन्य प्रखंडों में आई आंधी-बारिश और आंशिक ओलावृष्टि से गेंहू, राई व दलहन की 30 प्रतिशत से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई । अतएव फसल क्षति का पूर्ण मुआवजा उपलब्ध कराया जाए ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद् फारबिसगंज के अधिकांश वार्डों एवं नगर पंचायत मोगवनी के शहरी वार्डों में जल जमाव की भयावह स्थिति बनी रहती है, जर्जर सड़क एवं नाले के गंदे पानी का निकास रैयती जमीन में करनी पड़ती है । मास्टर प्लान के तहत नाले एवं सड़क निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय कनेक्टीविटी और पर्यटन के विस्तार हेतु सारण और चम्पारण को जोड़ने वाले एन0एच0-101 छपरा-महम्मदपुर (गोपालगंज) - बरहीमा मोड़ - सलेमपुर घाट - गन्डक नदी - गोविन्दगंज (पूर्वी चम्पारण) अरेराज-मोतिहारी मुख्य मार्ग पर गन्डक नदी में सलेमपुर पुल का निर्माण शीघ्र करावे ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज प्रखंड के कटहरा पंचायत के पनसल्ला गांव में दिनांक 5 मार्च, 2020 को आजाद नगर प्राथमिक विद्यालय के शौचालय का छत एवं दीवार गिर जाने से एक बच्ची की मौत एवं तीन गंभीर रूप से घायल हो गये हैं । मृतक परिवार को सहायता राशि एवं घायलों का इलाज दोषी के विरूद्ध कार्रवाई सहित नया विद्यालय भवन निर्माण की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/06:03:2020/ज्योति-पुलकित

श्री जफर आलम : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के अनुमंडलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर में कार्यरत दो महिला चिकित्सक एवं शिशु रोग विशेषज्ञ को अकारण नियम के विरुद्ध

सदर अस्पताल, सहरसा में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है । अतएव जनहित में कार्यरत पूर्व चिकित्सक को पुन: अनुमंडलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर में नियुक्त किया जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, 13 फरवरी 2020 को भोजपुर जिला के तरारी प्रखंड के कुसुम्ही गांव के बटाईदार किसान देवलाल राम का खलिहान में रखा पॉच बिगहा धान का बोझा जल गया । उनका पूरा परिवार भूखमरी का सामना कर रहा है । किसान देवलाल राम को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत हसनगंज से चापी जीर्ण शीर्ण पथ आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । यह पथ दो प्रखण्डों एवं राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-131 'ए' पूर्णिया कटिहार को भी जोड़ता है । इस पथ पर पूर्व से उच्च स्तरीय पुल भी निर्मित है । अत: सरकार से आग्रह है कि पथ का सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण शीघ्र करावे ।

श्रीमती अमिता भूषण : महोदय, बेगूसराय जिले के रामदीरी-कसहा दियारा में किसानों की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन को एन.टी.पी.सी. द्वारा अवैध तरीके जबरन छाई डम्पिंग के लिए अधिकृत किया जा रहा है । जबकि किसान इसके लिए एन.टी.पी.सी. के पास ही बंजर जमीन देने को तैयार हैं । अत: जिला के किसानों के हित में इस अधिग्रहण को रोकने हेतु सरकार से मांग करती हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, विश्वव्यापी कोरोना वायरस से बचाव ही इलाज है। बचाव के लिए सबसे कारगर उपाय मास्क लगाना है परन्तु इस गरीब राज्य में सभी नागरिकों के पास इतनी क्रय शक्ति नहीं है कि अपने लिए मास्क खरीद सके । अत: राज्य के सभी नागरिकों के लिए मास्क की व्यवस्था नि:शुल्क करे।

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम अपनी सूचना पढ़ें ।

श्री महबूब आलम, सत्यदेव राम एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (समाज कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राज्य के विधवाओं एवं 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्धों को पहले हाथों-हाथ पेंशन की राशि मिला करती थी । वर्तमान में यह राशि ऑन-लाईन व्यवस्था के तहत लाभुकों को बैंक खाता के माध्यम से भुगतान होता है । पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण राज्य में हजारों की संख्या में विधवाएँ एवं वृद्धों की पेंशन राशि नहीं पहुंचने के कारण पेंशनधारी पेंशन से वंचित रह जाते हैं । अत: पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे वर्तमान में

वंचित लाभुकों का सर्वेक्षण कर उन्हें पेंशन राशि उपलब्ध करवाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री राम सेवक सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सामाजिक, सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों के विधवाओं एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों को पहले हाथों-हाथ पेंशन की राशि का भुगतान शिविर के माध्यम से किया जाता था । लेकिन इसमें वृद्धजनों को आने-जाने में तथा लम्बी-लम्बी कतारों में लगकर पेंशन प्राप्त करना होता था, जिसमें पेंशनधारियों को भी काफी कठिनाई होती थी और समय भी अधिक लगता था । इसके साथ इसमें बिचौलियों की भूमिका भी बहुत अधिक होती थी, इस समस्या को दूर करने के लिए तथा पेंशनधारियों की पेंशन की सुनिश्चिता के आलोक में पेंशन का भुगतान ऑन-लाइन व्यवस्था के तहत डी0बी0टी के माध्यम से बैंक खाते में ससमय किया जाता है । इस प्रकार अब उनको आवश्यक शिविर में आने एवं लम्बी कतार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं रह गई है और बैंक खाते में सीधा भुगतान राशि जाने से बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हो गई है । ज्ञातव्य है कि डी0बी0टी के माध्यम से भुगतान हेतु सभी पेंशनधारियों का बैंक खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी कोड सहित अनिवार्य है । बैंक खाता की अनिवार्यता के आलोक में सभी पेंशनधारियों का बैंक खाता संख्या ई-लाभार्थी पोर्टल पर एंट्री कराया जाता है एवं भुगतान के पूर्व सभी बैंक खाता का सत्यापन पी0एफ0एम0एस, पब्लिक फाइनेन्शियल मैंनेजमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है एवं पी0एफ0एम0एस सत्यापन उपरान्त पेंशनधारियों के बैंक खातों में भुगतान किया जाता है । इस व्यवस्था का एक ओर यह लाभ हुआ कि बड़ी संख्या में लगभग 7 लाख मृत नन ट्रेसेबुल अन्य पेंशनधारियों के पेंशन भुगतान पर रोक लगाई गई । वही दूसरी ओर, बड़ी संख्या में लगभग 5 लाख नए मामले में पेंशन का भुगतान प्रारंभ किया गया । जिन कुछ पेंशनधारियों की खाता संख्या में त्रुटि रह जाती है, किसी अन्य खाता संख्या के उपलब्ध कराने के कारण उनका भुगतान तत्काल नहीं हो पाता है, वैसे पेंशनधारियों की खाता संख्या इत्यादि के त्रुटिकरण हेतु प्रखंड स्तर पर कई बार विशेष अभियान का संचालन किया गया एवं उनका प्रचार-प्रसार टी.वी, रेडियो, जिंग्ल एवं समाचार-पत्रों के माध्यम से भी कराया गया । अधिकांश छूटे हुए पेंशनधारियों की खाता संख्या एवं अन्य त्रुटि का सुधार कर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इस संबंध में सभी जिला के नॉडल जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि आपके जिला में यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वैसे लाभुक जिन्हें पूर्व से पेंशन मिल रहा था किन्तु वर्तमान में पेंशन से वंचित है, वैसे लाभुकों का सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित और सत्यापित करते हुए उनकी सूची जिलापदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध मुख्यालय को

उपलब्ध कराया जाए ताकि उन पेंशनधारियों को ई–लाभार्थी पोर्टल पर एंट्री कर पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके । सतत प्रक्रिया के तहत जिले के ऐसे लाभुकों की सूची प्राप्त हो रही है एवं उनका ई–लाभार्थी पोर्टल पर एंट्री करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जाय ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम हजार की संख्या से ज्यादा ही लोग वंचित है । महोदय, 5 साल पहले उनको पेंशन मिलती थी और अब नहीं मिलती है, अब तो ये मंत्री जी बोल रहे है कि जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है तो वो जो निर्देश का आदेश का प्रति है, वो हम लोगों को उपलब्ध करवाया जाए । हम लोग जिलापदाधिकारी से बात करेंगे और तुरंत उन लोगों का भुगतान एरियर के साथ भुगतान करने का अनुरोध है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इस प्रदेश में जितने वंचित लोग है, क्या संख्या आंकड़ा उनके पास है कि कितने वंचित लोग है जो पेंशनधारी मिलता था और उसे वंचित किया गया है बताने की कृपा करें ।

श्री राम सेवक सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसका तो इसमें जिक्र नहीं है लेकिन हम सदन के माध्यम से जितने माननीय सदस्यों के माध्यम से ध्यानाकर्षण लाया गया या अन्य सभी माननीय सदस्यों से हम आग्रह करेंगे कि आपके क्षेत्र में जितने वंचित लोग है कृप्या सहयोग करके उनका मतलब वह खाता संख्या सहित अगर लिंक करा देते हैं तो जो वंचित लोग है उनका निश्चित रूप से अगर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी । अध्यक्ष महोदय, हम बाताना चाहेंगे सदन को कि डी0बी0टी के माध्यम से पेंशन भुगतान के संबंध में प्रथम प्यॉरटी दिंनाक– 07/10/2016 को सफलतापूर्वक जहानाबाद जिले में किया गया, जिससे 27 अक्टूबर 2016 में राज्य में लागू किया गया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी एक–एक मिनट रूकिये, आप डी0बी0टी से जो करते हैं ट्रान्सफर, उसमें किसी माननीय सदस्य को एतराज नहीं है, ना ध्यानाकर्षण में उस बात का जिक्र सिर्फ इतनी ही बात है कि जिन लोगों को पहले मिलता था यानी जिसकी स्वीकृति पहले दी जा चुकी है उनको मिलने में जो कठिनाई हो रही है जो बैंक उनका अकांउट टैगिंग है या डी0बी0टी के लिए जो आवश्यक औपचारिकताएँ हैं, फॉर्मलटिज हैं जो गरीब लोग करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उसमें जो परेशानी हो रही है ये उसकी तरफ ध्यान दिलाए हैं, आपका और उसमें जैसा कि आपने कहा कलक्टर को निर्देश दिया गया है और उसमें कैम्प लगवा के इसको जरूर करवाया जाए क्योंकि सब जगह परेशानी हो रही है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हम केवल आपसे जानना चाहते हैं कि जितने पेंशनधारी थे, आपके पास आंकड़ा होगा । कितने पेंशनधारियों को पेंशन मिलता है और कितने वंचित हैं, उसकी संख्या तो बतायें ।

अध्यक्ष : अभी संख्या नहीं है, वो तो बतायें, अभी संख्या नहीं होगी । उसमें एक ओर जो संज्ञान में बात आई है मंत्री जी आजकल बैंकिग व्यवस्था में संयोग से माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं कि ये जो सी0एस0पी वाला जो कॉन्सप्ट है, कन्ज्यूमर सर्विस प्वाइंट सब जो बैंक के लोग जो देहात में किसी एक आदमी को फेन्चाइजी के जैसे उसको चलाने के लिए दे देते हैं । बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उन लोगों का अकाउंट वहाँ से चलता था और वहाँ से टैगिंग की बात आई है तो कई सारे मामले ऐसे भी आए हैं कि जो सी.एस.पी संचालक थे उनका और बैंक का रिश्ता खराब हो गया और गड़बड़ी किस की रही, उसी की रही होगी और वो सारा कागज पत्र के लेकर भी गायब हो गया । वैसी हालत में उन लोगों को जिनका अकाउंट जिन गरीब लोगों का अकाउंट सी.एस.पी के थ्रू खुलवाया गया था और उसमें पेंशन की रकम आती थी वो सी.एस.पी के गायब हो जाने से कठिनाई इसलिए बढ़ गई है कि उनका दोबारा अकाउंट खुलने में भी दिक्कत करता है । इसलिए उसको भी दिखवा लीजिए ।

श्री राम सेवक सिंह, मंत्री : जी, ठीक है ।

टर्न-09/कृष्ण/06.03.2020

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सर्वेक्षण करवा लें, पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण करवा लें और एक समय-सीमा निर्धारित कर दें ताकि जिनलोगों को मिलना चाहिए और उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनको पेंशन मिलने लगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि सरकार के पास जो भी तरीका हो, जिस तरह से चाहे जांच करायें, डी0एम0 से करायें, जिनसे कराना है, करायें । हमको माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना है कि जिनलोगों को पेंशन मिल रहा था, जो आज उनको नहीं मिल रहा है, चाहे जिन कारणों से नहीं मिल रहा है, बचे हुये जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, क्या उनलोगों को पेंशन दिलाने की गारंटी करते हैं, अगर करते हैं तो कबतक, एक समय-सीमा निर्धारित कर दें ।

अध्यक्ष : सर्वश्री फराज फातमी, लालबाबू राम एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना । श्री फराज फातमी, सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री फराज फातमी, लालबाबू राम एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, बिहार के दरभंगा जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में फरवरी के अंतिम सप्ताह में बेमौसम आई आंधी-बारिश और आंशिक ओलावृष्टि से गेहूं, राई व दलहन की फसल को भारी नुकसान हुआ है । हजारों एकड़ में तैयार गेहूं की खड़ी फसल आंधी-बारिश में गिर गई, उससे गेहूं की पैदावार में चौथाई से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है । प्रकृति की इस मार से किसान त्रस्त हो गये हैं, लागत वापसी में भी अड़चनें आ रही है । अकेले सिंहवाड़ा प्रखंड में 7455 हेक्टेयर में आच्छादन का लक्ष्य था, लेकिन उपलब्धि 6710 हेक्टेयर रही और वो भी अब 30 प्रतिशत से ज्यादा बर्बाद हो गया ।

अत: किसानों के क्षति का पूर्ण मुआवजा देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब । कृषि विभाग । यह आपदा प्रबंधन विभाग और कृषि विभाग दोनों से संबंधित है ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि फरवरी, 2020 के अंतिम सप्ताह में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से राज्य में फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त होने के उपरांत क्षति की भरपाई हेतु प्रभावित फसल रकबा का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया था । उक्त निर्देश के आलोक में विभिन्न जिलों से जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 11 जिले यथा-पटना, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, समस्तीपुर एवं भागलपुर में 33 परसेंट से अधिक फसल क्षति प्रतिवेदित किया गया है, जिसका कुल रकबा 31,929 हेक्टेयर है ।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिले में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित रकबा 2068.02 हेक्टेयर है, जिसमें 33 परसेंट से अधिक फसल क्षति का रकबा शून्य प्रतिवेदित किया गया है । सिंहवाड़ा प्रखंड के प्रभावित रकबा एवं 33 परसेंट से अधिक फसल क्षति का रकबा शून्य प्रतिवेदित किया गया है ।

आपदा प्रबंधन विभाग के मापदंडों के अनुसार 33 परसेंट या उससे अधिक फसल क्षति होने की स्थिति में ही फसल क्षतिपूर्त्ति देने का प्रावधान है । संबंधित जिलों से प्रभावित किसानों के बीच कृषि इनपुट अनुदान वितरण कराने हेतु कृषि विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग से 60 करोड़ रूपये की अधियाचना की गयी थी,

प्राप्त हो चुका है । महोदय, हमलोगों ने तय किया है कि 9 मार्च से ऑनलाईन आवेदन लेंगे और 25 दिनों के अंदर किसानों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि चली जायेगी ।

श्री फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, बिहार में हर साल या तो सूखा हो या बाढ़ हो या फिर ओलावृष्टि, ये दो साल पहले भी दरभंगा जिला के अंदर ऐसे ही ओलावृष्टि हुई थी । बस, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस बात को सुना । लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि दो साल पहले भी ऐसी ही ओलावृष्टि हुई थी, अभी तो दिसंबर के माह में गेहूं की जो ऊपज हुई थी, उसमें एक तिहाई बर्बाद हो गया था, रब्बी की फसल भी डैमेज हो गयी मतलब कुछ बचा नहीं । जो किसानों ने लगाया, वह भी किसानों को आने की उम्मीद नहीं है और दो साल पहले भी यही हादसा हुआ, यही मामला हुआ । बस, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो बर्बादी हो गयी, उसका आप मुआवजा दे रहे हैं । क्या सरकार ने इन दो सालों के अंदर कोई ऐसा प्लानिंग या कोई ऐसी प्लानिंग की है कि आने वाले दिनों में बचाया जा सके कि ऐसी कोई हादसा नहीं हो, तो तैयारी क्या की सरकार ने ? साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने भी किसान हैं, उनका सर्वे कराया है, जिनकी फसल डैमेज हुई है, ये 9 मार्च की बात कर रहे, सही सर्वे हुआ है कि नहीं, किनके द्वारा सर्वे कराया गया है कितना फसल बर्बाद हुआ है, कितना पैसा उनको मिल पायेगा ?

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, हमारी सरकार संवेदनशील है जब-जब राज्य में सूखा पड़ा है,बाढ़ आई है, असामयिक वर्षा हुई है या ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, महोदय, पिछली बार 2018 में सुखाड़ पड़ गया था और राज्य के 25 जिले के 180 प्रखंडों में सुखाड़ पड़ गया था और हमलोगों ने 15 दिनों में जांच करवाया था, खरीफ का मौसम था, हथिया नक्षत्र में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो पायी थी और 934 करोड़ हमलोगों ने साढ़े 14 हजार किसानों के खाते में भेजने का काम किया । 2019 में बाढ़ आ गयी उत्तर बिहार के 13-14 जिलों में, सुखाड़ 14 जिलों में आ गया और महोदय, हाल में जो असामयिक वर्षा जो हुई, बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है तो राज्य सरकार लगातर ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में, सरकार की सोच है कि प्राकृतिक आपदाओं में खजाने पर पहला अधिकार उनका है, जो राज्य के अंदर प्रभावित आपदा से होते हैं, उनका पहला अधिकार होता है । महोदय, हम बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद से व्यवस्था की जो मानक है, पहले 50 परसेंट था लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 33 परसेंट कर दिया । पहले 50 परसेंट फसल की क्षति होती थी, उस पर मुआवजा मिलता था, लेकिन हमारे केन्द्र की

सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों की पीड़ा को समझा, आजादी के 70 साल के बाद पहली सरकार केन्द्र में आयी, जिन्होंने 33 परसेंट करने का काम किया और अभी तक हमलोगों ने 3000 करोड़ नुकसान जो हुआ है ।

(व्यवधान)

हम कह रहे हैं कि जो व्यवस्था पहले नहीं थी, आजादी के बाद 70वर्षों में।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अमेरिका इंगलैंड भेजिये न भारत से ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : आ रहा है वह समय । सुन लीजिये । अभी हम दूध भेज रहे हैं, मछली भेज रहे हैं इंडिया से, आनेवाले समय में ..

(व्यवधान)

निश्चित तौर पर । डिमांड हो रहा है खाड़ी के देशों से फल, शाही लीची, मगही पान, जर्दालु आम ....

अध्यक्ष : आप सिद्दिकी साहब के पूरक को दरकिनार करके इसको जल्दी से पेमेंट करा दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, मैं कह कर हा हूं कि जो भी घटनायें घट रही है हम एक सप्ताह के अंदर जांच करा करके और एक महीने के अंदर डी0बी0टी0 के माध्यम से खाते में राशि भेजने का काम कर रहे हैं । महोदय, कैबिनेट से स्वीकृत हो गया है । राशि जिलों में चली गयी है । 09 से आवेदन ऑनलाईन आवेदन ले रहे हैं और आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच करके हमलोग निश्चित तौर पर 25 दिनों के अंदर डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि भेजने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : अब सभा कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/अंजनी-अभिनीत/06.03.2020

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । वित्तीय-कार्य ।

वित्तीय-कार्य

माननीय सदस्यगण, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 60 मिनट
जनता दल (यू0)	- 51 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 40 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 19 मिनट
सी0पी0आई(एम0एल0)	- 02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 01 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	- 01 मिनट
निर्दलीय	- 04 मिनट

अब माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 72,13,71,54,000/-(बहत्तर अरब तेरह करोड़ इकहत्तर लाख चौवन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री रामदेव राय, श्री मो0 नेमातुल्लाह एवं श्री कुमार सर्वजीत से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से की राशि घटाई जाय ।"

मेरी पार्टी की ओर से नवाज आलम साहेब बोलेंगे ।

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं नगर विकास एवं आवास विभाग के वर्ष 2020-21 के अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं इसलिए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हूं कि वर्ष 2020-21 में स्कीम के मद में 343418.00 करोड़ रूपये दिए गये, वर्ष 2019-20 में दिए गये 307500 करोड़ रूपये। स्थापना व्यय में वर्ष 2020-21 में 3795.72 करोड़ रूपये दिए गये और वर्ष 2019 में 2083.79 करोड़ दिए गये। इससे वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल प्राक्कलन में 7213.72 करोड़ रूपये दिए गये और 2019-20 में 5158.79 करोड़, लगभग 2054.93 करोड़ अधिक रूपये दिए गये। महोदय, मैं नगर विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं इसलिए कि जो वित्तीय प्रबंधन है और जो इनके खर्च करने का लेखा-जोखा है, वह निश्चित रूप से कहीं-न-कहीं हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से ठीक हमने एक शीर्षक है महोदय कि बढ़ती आबादी नाले के पानी में डूबता हुआ स्मार्ट सिटी। महोदय, इसलिए मैंने इस शीर्षक को रखने का काम किया कि हाल के दिनों में जिस तरह से पटना में जल-जमाव हुआ और जल-जमाव ऐसा ही नहीं, जिस सूबे में बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सी0एम0 अपने घर से अपने पड़ोसी को छोड़कर भागते हुए, हाफ पैंट पहनकर पूरे पदाधिकारियों के साथ जिस तरह से निकले, उससे पूरी दुनिया में, पूरे हिन्दुस्तान में बिहार का नाम कहीं-न-कहीं शर्मशार हुआ। इसका एक ही कारण मुझे नजर आता है कि आपने जो वित्तीय प्रबंधन किया था, आपने जो कार्य योजना बनाई थी, उसको आपने सही तरीके से धरातल पर लाने का काम नहीं किया । आपने निश्चित रूप से, मैं इसलिए इस बात को रखना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ विकास का ढ़ोल पीटने का काम किया है । विकास के ढ़ोल को जिस तरह से पीटने का काम किया, यहां माननीय पूर्व मंत्री भी बैठे हुए हैं, कई ऐसी समीक्षात्मक बैठकें हुईं, उस बैठक में हमलोगों को भी जाने का मौका मिला ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री मो0 नेमातुल्लाह ने आसन ग्रहण किया)

कल जो सदन में हंगामा चल रहा था कि प्रमंडलीय आयुक्त को कहीं-न-कहीं इसमें दोषी माना जाय लेकिन मेरा मानना है कि इस घोटाले में और इस तरह के वित्तीय प्रबंधन में जो लीपापोती हुई है, वह निश्चित रूप से बुडको के माध्यम से

जिस तरह से तमाम् नगर निगम को बुडको में डालने का काम किया गया और बुडको के द्वारा जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन को जोड़तोड़ करके, गुणा-भाग करके जो लूटने की योजना बनायी गयी, आप अमरेन्द्र बाबू, जब एम0डी0 को अगर निलंबित करते हैं तो प्रधान सचिव चैतन्य कुमार को भी निलंबित होना चाहिए था । महोदय, हमलोग लगातार इस विभाग को देख रहे हैं, जब से मैं चार-पांच वर्षों से इस विभाग में आया, हमलोग तमाम योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में लगातार सवाल उठाते रहे हैं । माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री के समक्ष सवालों को उठाते रहें हैं, उनके संज्ञान में और सदन में लाने का काम किया हमलोगों ने । महोदय, ये कहते हैं कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे । इस संबंध में सभापति महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि यंत्र और गाड़ी की खरीद में, हम सिर्फ आरा का डाटा देते हैं, पांच करोड़ की खरीद हुई और उस खरीद का नतीजा हुआ कि वह तमाम् यंत्र इसी तरह कुआं में फेंका हुआ है । महोदय, आपका जो वित्तीय प्रबंधन है, आपके काम का जो तरीका है, वह ठीक नहीं है । 167 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट नाला के लिए, नार्थ फॉल नाला का लगातार हमलोग, माननीय सदस्य चिल्लाते रहे, आपके बीच में गुहार लगाते रहे लेकिन फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का जो मामला था, उसके संबंध में हमेशा मंत्री जी कहते रहें कि हमारे पास निधि उपलब्ध होगी तो काम लगेगा लेकिन हम जानना चाहते है, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से लूट बुडको के द्वारा करने का काम किया, अगर बुडको की जांच करायी जाय तो निश्चित रूप से हम बुडको के मामले में बताना चाहते हैं कि कई ऐसे जिले का जो मुझे संज्ञान में आया है, आप जो हैं बुडको के माध्यम से एक रैली कंपनी है, जो गया में लगभग 100 करोड़ की लूट मचायी है और इस तरह से नहीं महोदय कागजी लूट हुई है। हम तो चाहते हैं कि निश्चित रूप से सदन के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिये। बुडको के जो एम0डी0 बनते हैं, जो प्रधान सचिव बनते हैं, जो सचिव बनते हैं, कहीं-न-कहीं हमें लगता है कि अणे मार्ग हो, चाहे डिप्टी सी0एम0 हो, तमाम लोगों की इसमें संलिप्तता पायी जायेगी। अगर जांच किया जाय तो 100 करोड़ की जो लूट हुई है उसका निश्चित रूप से सी0बी0आई0 के माध्यम से जांच होनी चाहिये। इसी तरह से हम सफाई के मामले में कहना चाहते हैं।

क्रमशः

श्री संजय सरावगी: सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ । सभापति महोदय, ये सीधे-सीधे बोल रहे हैं कि 100 करोड़ की लूट हुई है तो इन्हें बताना चाहिए सीधे गलत आरोप, मिथ्या आरोप सदन में नहीं लगा सकते, इनको बताना चाहिए, मैं इन्हें चुनौती देता हूँ ।

श्री मो0 नवाज आलम: महोदय,सदन की कमिटी बनाकर इसकी जांच करा दिया जाय, जांच कर लिया जाय ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): आपको जब समय मिलेगा, तब आप भी बोलियेगा ।

श्री मो0 नवाज आलम: महोदय, 100 करोड़ की लूट हुई है । महोदय सफाई के नाम पर सफााई का पैसा लगभग 40 लाख, मैं सिर्फ आरा शहर की बात करता हूँ, माननीय मंत्री जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ..........

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मंत्री बेचारे है, विभाग को तो प्रधान सचिव चलाते है,ऑफिसर चलाते हैं, मंत्री तो यूं ही खड़े रहते हैं, हम जानते हैं इस बात को, इसलिए हम आपके बीच में कहना चाहते है कि सफााई के नाम पर लूट होती है........

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, कोई भी आरोप तथ्यात्मक होनी चाहिए और तथ्य से पूर्ण आरोप होनी चाहिए,अगर तथ्य इनके पास नहीं है, तो ऐसी बातें प्रोसिडिंग में नहीं जानी चाहिए, इसको हटाने का निदेश आना चाहिए ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): तथ्य के आधार पर आरोप होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री मो0 नवाज आलम: सभापति महोदय, इसकी जांच करा लिया जाये सी0बी0आई0 से ।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत: सभापति महोदय, अगर तथ्य नहीं है, तो इसकी जांच करा लिया जाय ।

श्री मो0 नवाज आलम: महोदय, इसी तरह से सफाई के मामले में एक जिले में एक शहर में 40 लाख रुपये गये है, सफाई के नाम पर तमाम जगहों पर सिर्फ खानापूरी हो रही है, अगर सफाई होती, स्वच्छता अभियान चलता तो निश्चित रूप से पटना जल जमाव नहीं होता । महोदय, आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री नली-गली योजना में कहीं भी कोई काम नहीं हुए हैं, नाली को तोड़ दिया गया है लोग परेशान हैं, उसमें कोई निदान नहीं किया गया है । मुख्यमंत्री पेयजल योजना की धरातल पर क्या स्थिति है तमाम लोग जानते हैं, माननीय सदस्य भी जानते हैं पेयजल योजना को, नली-गली योजना के माध्यम से आप जमीन पर ले जाना चाहते हैं वह कहीं न कहीं आप पर है । उस

मामले को देखने का समय है । महोदय, बुडको द्वारा जारी नमामि गंगे के माध्यम से तमाम जगह लूट मची हुई है................

(व्यवधान)

महोदय, जिस तरह से तमाम जगहों पर लूट मची हुई है और हमारे यहां बुडको के माध्यम से जो संज्ञान में आया है आज तमाम 30 योजनाएं चल रही हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अटल शहरी नवीकरण योजना कहीं भी जमीं पर नहीं उतर रही है । पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, हम जानना चाहते हैं कि आप पटना को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं । 2019-20 में भी 620 करोड़ रूपया देने का काम किया है और आप 620 करोड़ का हिसाब नहीं देते हैं । इसी तरह से महोदय आपके सामने कहना चाहते हैं, आपने कहा था कि सबको आवास देने का 'हाउस फॉर ऑल' की बात करते और अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ते, गरीब और मलीन बस्तियों को उजाड़ने का काम करते और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने जिन लोगों को बसाने का काम किया है, गरीबों को बसाने का काम किया । अम्बेडकर कॉलोनी बनाने का काम किया, जिन मलिन बस्तियों की आप सफाई करने में लगे हैं । इसलिए आप गरीब विरोधी हैं इसलिए साथियों आपने बस स्टेंड का जो मामला उठाया है बस स्टेंड बनाने में कहीं भी, आपका बस स्टेंड जहां भी बन रहा है महोदय, आरा की सरजमीं पर बस स्टेंड बन रहा है । माननीय मंत्री जी, इसकी जरूर उच्च स्तरीय जांच करवाकर देखें कहीं न कहीं इस्टीमेट घोटाला मिलेगा । महोदय, इसी तरह से आप तमाम जगहों पर चाहे आप रेलवे लाईन के किनारे हो, तमाम जगहों पर आपने मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम किया है, आपका कोई विजन नहीं है । महोदय, वेन्डिंग जोन के मामले में जो फुटकर व्यापारी हैं, सब्जी बेचने वाले हैं तमाम लोग जो हैं कहीं न कहीं अतिक्रमण होता, अतिक्रमण के नाम पर उनका दमन होता आपका वेन्डिंग जोन कहीं भी किसी जगह, आप बनाने का काम नहीं करते आपका कौन सा विजन है ? हर शहर में सार्वजनिक स्थान पर पेयजल होना चाहिए लेकिन पेयजल की व्यवस्था नहीं होती और तमाम जगहों पर जिस तरह से ऐरिगेशन डिपार्टमेंट है, आपका पी0डब्ल्यू0डी0 डिपार्टमेंट है, उसका गेस्ट हाउस होता लेकिन नगर विकास का कहीं भी गेस्ट हाउस नहीं, कहीं भी ठहरने की विशेष व्यवस्था नहीं है । इसलिए हम चाहते हैं सदन के माध्यम से कि आपको ऐसी भी व्यवस्था करने का काम करना चाहिए । वार्ड कमिश्नर को और तमाम जनप्रतिनिधियों को जो मानदेय देते थे 2500/- रूपया देते हैं । आज वार्ड कमिश्नर जीतता है निश्चित रूप से वहां करप्शन होते हैं अगर उनको संतुष्ट करने का कम से कम 10,000/- रूपया मानदेय देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को मान और सम्मान मिलेगा महोदय । इसी

तरह से जनप्रतिनिधि भी जो हैं आप देखे होंगे कि सिटी मैनेजर हो चाहे नगर आयुक्त हो तमाम लोगों को आप गाड़ी देते हैं, गाड़ी का पैट्रोल देते हैं लेकिन कोई मेयर जीतकर आता है, डिप्टी मेयर जीत कर आता है तो उनकी तमाम चीजों को आपने बंद कर रखा है । इसमें कहीं न कहीं आपको सुधार करने की जरूरत है । महोदय इसी तरह से आपने जो हाई लाईट मॉस्क लगाए हैं करोड़ों रूपये की चीजें लग गई लेकिन हाई मॉस्क कहीं भी लगाने की व्यवस्था नहीं है । महोदय सिटी मैनेजर कहीं कहीं मिलते और जिसका मुख्य दायित्व होता है सिटी मैनेजर का सफाई का उन कामों में सिटी मैनेजर कहीं भी लिप्त नहीं होते इसलिए महोदय आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि प्यास ऐसी है कि पी जाओ समुंद्र सारे नसीब ऐसा है कि मौजूदा जहां तक नहीं इसलिए आपको हम इस बात से कहना चाहते हैं कि ये सरकार निश्चित रूप से गरीब विरोधी है और कहीं न कहीं आज सफाई की व्यवस्था के नाम पर हर जगह लूट मची हुई है । जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से आज जो तमाम जनप्रतिनिधि शहर से आते हैं उनको किसी भी योजना में आज लूट का एक ही कारण है कि जनप्रतिनिधि की सहभागिता उसमें कहीं नहीं रहती, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं होता जिसके कारण वह योजना नीचे से जिस तरह से जल-नल योजना की लूट मची है उसी तरह यह योजना भी विधायकों को कम से कम मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचती है और जिस तरह से महोदय आज तमाम ग्रामीण सड़क बनाने का काम जो करते हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में कहीं भी कोई यह आपकी योजना नहीं चलती है । आप उस तरह से शहरी विकास के नाम पर कोई योजना का निर्धारण करें कि माननीय विधायक भी कहीं अनुशंसा करके अपने कामों को करा सके यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से इस पर गिलोटिन है महोदय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पी0एच0डी0 डिपार्टमेंट जो है श्रवण बाबू आप लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हैं । हमारे यहां क्षेत्र में तीन चार जगहों पर लगातार पानी बह रहा है करीब साल भर से लगातार एक्सक्यूटिव इंजीनियर से कहते, तमाम पदाधिकारियों को कहते लेकिन वहां तो जो है जल-नल योजना में लूट लगी हुई है । महोदय, इसलिए उस लूट से बचना अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं भी कोई भी इंजीनियर नहीं है नगर-निगम में पी0एच0डी0 में इंजीनियर नहीं है, कहीं कर्मचारी नहीं है, आप कैसे विकास की कल्पना कर सकते हैं ? मेरा मानना है कि आपका विकास का ढिंढोरा झूठ है, ढोंग है और आपने कहीं न कहीं समाज को दिग्भ्रमित करके जिस तरह से आपने वोट लेने का काम किया है आने वाले समय में समाज आपको सिखाने का काम करेगा । आदरणीय नेता गरीबों के मान और सम्मान लालू यादव ने जिस तरह से गरीबों को बसाने का काम किया था, जिस तरह से झुग्गी

झोपड़ी में रहने वाले को मान और सम्मान दिया था, आपने अतिक्रमण के नाम पर कहीं न कहीं दमन करने का काम किया है । इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

टर्न-12/सत्येन्द्र-मुकुल/06-03-2020

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): जनता दल (यूनाइटेड) के श्री सुबोध राय जी।

श्री सुबोध राय: सभापति महोदय, मैं अभी नगर विकास एवं आवास विकास विभाग की मांग पर कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, ये सभी जानते हैं कि बिहार कहां खड़ा था और आज बिहार कहां पहुंचा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि लोग हकीकत को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं इसलिए उनके बारे में कहा गया है कि अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो लेकिन ये भी देखते हैं कि कोई देखता तो नहीं, आज हालत यही हो गई। आपको बताना चाहिए कि आज नगर विकास क्या वही है, जो पहले था 15 सालों में, कुछ नहीं बदला। आज जो है, चारों तरफ आप चले जाइये, बिहार के किसी शहर में चले जाइये, सड़कों की स्थिति, सफाई की स्थिति, बड़े-बड़े महलों की स्थिति, नागरिक सुविधाओं की स्थिति उसमें काफी वृद्धि हुई है और ये वृद्धि ये बिहार की जनता के आशीर्वाद से माननीय नेता नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में हुई है, एन.डी.ए. सरकार के नेतृत्व में हुई है। ये आज हकीकत है और इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे नगर विकास मंत्री भी इस योगदान में कभी पीछे नहीं रहे हैं। जब से उन्होंने इस विभाग को संभालने का काम किया है उसमें इजाफा हुआ है और इसीलिए आज 72 अरब 13 करोड़ 71 लाख 54 हजार रुपये की जो यह बजट बनी है ये बिहार की 12 करोड़ जनता के जीवन को सुधारने के लिए, नागरिक सुविधाओं को देने के लिए, नगरवासियों की हर सुख-सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसके उत्थान और उसके उन्नयन के लिए काम किया जा रहा है। हम यह मानते हैं कि कहीं कुछ लापरवाही हमसे हो सकती है, कुछ कमियां हमसे हो सकती हैं। पटना के लोगों को परेशानी हुई पिछले बरसात के समय में, जब परेशानी हुई तो उस परेशानी को दूर करने के लिए कौन आगे आया, किसने जो है वह परेशानी दूर की ? पटना की जनता को बचाने का काम, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम, जो जल-जमाव था उसकी निकासी का काम, वह किसने किया, ये श्रेय किसको जाता है? आप सिर्फ आलोचनाओं से किसी को सुधार नहीं सकते हैं और आलोचनाओं में भी अगर वे सकारात्मक होती हैं, प्रेरणादायी होती हैं महोदय तो उस आलोचना से ताकत

मिलती है सरकार को, उस आलोचना से हमारे जो आलोचक होते हैं उनका भी एक इमेज बनता है लेकिन बेमतलब की आलोचनाएं, एक ही बात दिन-रात रटते रहना लूट-लूट-लूट। अरे भाई, यह संस्कार लूट का कहां से आया, कहां से आया, किसने लाया, कहां से लाया ? जहां से ये संस्कार आया तो जब आप सामने आये आपके बारे में बात हुई तो क्या हुआ ? उस वक्त जो है आपने कहा कि मईया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। जब लूट उजागर हुआ तो आपने स्वीकार नहीं किया लेकिन बिहार की जनता ने इसको देखा है, इसको झेला है और आज इसलिए नगरों की दशा सुधारने के लिए जो सरकार का प्रयास हो रहा है, सरकार ने जो काम किया है आज सभी जगहों पर यह जाहिर हो रहा है। पटना में मैट्रो रेल की बात आपने सुना था, कल्पना करते थे, स्वप्न देखते थे, आज साकार करने का काम कौन कर रहा है ? इसमें हमारी राज्य सरकार श्री नीतीश कुमार जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, एन.डी.ए. की सरकार हमारे नगर विकास मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये सारी बातें हो रही हैं। आज शहरों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। आज नगर-निकायों की जो ताकत बढ़ाने की बात हो रही है, उसको ज्यादा-से-ज्यादा साधन सम्पन्न बनाने की बात हो रही है, उसके ज्यादा-से-ज्यादा सदस्यों को ज्यादा-से-ज्यादा अधिकार सम्पन्न बनाने की बात हो रही है, कमी कहां है ? कमी को देखने की जरूरत है तो उन कमियों को बताइये, हमारी सरकार ने कभी नहीं दावा किया है कि हम सब कुछ कर दिये हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी कभी अतिरंजित बयानबाजी में यकीन नहीं करते हैं, कभी हमारे नेता कोई भी अतिरंजित बयानबाजी की बात नहीं करते हैं इसलिए उन्होंने कहा है कि हम तो मार्क्स, लेनिन को मानने वाले लोग, जानने वाले लोग भी हैं, हम जानते हैं कि सोशलिज्म का क्या सिद्धांत है - From each according to his ability, to each according to his work ये जानते हैं। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के मुताबिक काम और उसके काम के मुताबिक दाम, ईनाम। नीतीश कुमार जी तो बराबर यही कहते हैं कि हमने जो काम किया है, हमने जो आपकी सेवा की है, हमने जो आपको लाभ पहुंचाया है हमको सिर्फ उतना ही भर दीजिए, हम सिर्फ यही कहते हैं। इसलिए बड़ी-बड़ी बातें करना हमारी आदत नहीं है। हम उसके शिकार नहीं हैं।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब 2 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री सुबोध राय: हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे सुलतानगंज विधान सभा में हमारा एक नगर परिषद् सुलतानगंज है। वहां जलापूर्ति की समस्याओं को मुस्तैदी से और गंभीरता से देखने की जरूरत है। जो जलमीनार है वह बहुत पुराना हो गया है और जलापूर्ति की समस्या खास तौर से यह ग्रीष्मकाल में ज्यादा गंभीर हो जाती है। वह हमारा श्रावणी

मेला का विश्व विख्यात केन्द्र स्थल है। उसमें लाखों लोगों का वहां आगमन होता है। उनकी समस्याओं के लिए सुलतानगंज नगर परिषद् को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल और अधिकार सम्पन्न, साधन संपन्न बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ सुलतानगंज में लगातार हर रोज घाटों पर काफी जो हैं लोग उमड़ते हैं। उन घाटों को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। वहां हर दिन एक सौ, डेढ़ सौ, दो सौ लाशों का दाह-संस्कार होता है, उत्तरवाहिनी गंगा है और इसलिए उसकी पवित्रता और मोक्ष पाने का इरादा रखने वाले हिन्दू समुदाय के लोग वहां बहुत दूर दूर से आते हैं इसलिए उनके लिए विद्युत शवदाह-गृह बनाने की जरूरत है ताकि गंगा की सफाई ज्यादा से ज्यादा हो सके । घाटों का सुदृढ़ीकरण नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वहां रिवर-फ्रंट का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाना है और साथ ही साथ मैं भागलपुर नगर-निगम की समस्याओं से भी अवगत कराना चाहूंगा। जलापूर्ति की समस्या वहां भी गंभीर है।

..क्रमशः..

टर्न-13/मधुप-हेमंत/06.03.2020 ...क्रमशः...

श्री सुबोध राय : वहां सम्राट अशोक हॉल का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है इसलिए उसको देखने की जरूरत है । जल-जीवन-हरियाली के तहत आप सारे सरकारी भवनों पर वॉटर हार्वेस्टिंग स्कीम का कार्यान्वयन करवा रहे हैं । मेरा प्रस्ताव है कि सुल्तानगंज में इस पर विशेष ध्यान दिया जाय । नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत और सभी विद्यालयों में भी वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए काम कराया जाय और इस तरह से जो हमारा सपना है नये बिहार का, विकसित बिहार का उसको साकार करने में ज्यादा से ज्यादा कम समय में हम सक्षम हो सकें । इसके लिए मैं मंत्री जी आपसे अपना निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं । आप ध्यान देंगे कि सुल्तानगंज नगर वासियों की समस्या, वहां तब तक संभव नहीं है, हमारे सारे पी.एच.ई.डी के लोग बैठे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग बैठे हैं, वह भी विभाग है, आपदा प्रबंधन की ओर से मैं मांग करना चाहता हूं, वहां हर बार अनेकों लोगों के डूबने की घटनाएँ होती हैं । एस.डी.आर.एफ. की टीम भागलपुर में रहती है जो डूबने वाले होते हैं उनको बचाने के लिए, उनको लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है । इसलिए एस.डी.आर.एफ. का स्थायी निवास सुल्तानगंज में होना चाहिए ताकि जैसे ही घाटों पर डूबने की घटना हो तो तत्काल उनको बचाने का काम करें ।

महोदय, आप जानते हैं कि सुल्तानगंज किस बात के लिए मशहूर है । लाखों लोग जब आते हैं और सैलाब बाबा अजगैबी नाथ धाम सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम तक लगता है, सभी तरह के लोग - बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है,

बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है । इस उत्साह और उमंग के साथ बाबा की शरण में जाते हैं । इसके महत्व को आप भूलिये नहीं । (व्यवधान) आप भी वहां जाते हैं, आपने भी वहां डुबकी लगायी है, आप भी जल भर कर जाने वालों में हैं । इसलिए वह ऐसी जगह है उसकी अनदेखी करने का कोई सवाल नहीं है । सुल्तानगंज के लोगों ने बराबर आपको सहयोग किया है, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है उन कांवड़िया श्रद्धालुओं की सेवा करके और आज भी हम करना चाहते हैं । इसलिए आपकी ओर से विशेष मदद, विशेष पैकेज और नगर परिषद को विशेष अधिकार देना आपके लिए लाजिमी है । आपको बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं तो लाल बत्ती जलने के पहले ही अपनी बात खत्म करने वाला हूं बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : धन्यवाद । मैंने तो लाल बत्ती अभी जलायी नहीं । मंत्री जी ने आपका समय बढ़ा दिया था । धन्यवाद आपने ससमय समाप्त किया ।

अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, सरकार द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए जो बजट आया है, उस पर विपक्ष ने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है, उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं, यद्यपि हमारे साथी कह रहे थे बैठे-बैठे ही बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए सबसे पहले पटना में जो जल-जमाव से पिछली बरसात में पूरा पटना जल ग्रसित था और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 वर्ष का रिकॉर्ड ब्रेक करके यह पानी बरसा था, यह भी उतना ही सत्य है और चूंकि आप ध्यान में रखे होंगे तो सितम्बर का अंत और अक्टूबर की शुरुआत, इसी समय यह पानी . .....(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अरूण बाबू को बोलने दीजिये ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : जो आदमी बहादुर होता है, सच्ची बात यह है, जो कुछ मोरलफुल लोग होते हैं, पिछला आप देखियेगा 2-3 साल का रिकार्ड तो पानी बरसा नहीं, इन सभी कारणों को एक साथ मिलाकर, त्रुटि हुई है और बड़ी बात यह है कि सरकार ने बड़ी कड़ाई से इस पर एक्शन लेते हुए लगातार गम्भीरता से न केवल बैठक बुलाई है, बल्कि अगली बार से यह नौबत नहीं आये, इसके लिए जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसपर वह काम चल रहा है।

आपको इसी कम में, चूंकि यह सबसे प्रमुख बात आपने उठायी और मैं बताता चलूं कि मैंने भी कुछ इसके लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन सुझाव दिये हैं और सरकार ने उसको गम्भीरता से लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगर विकास मंत्री जी को और साथ-ही-साथ नगर विकास

विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, सबने मिलकर और उनलोगों ने बड़ी गम्भीरता से इसको लेकर, आश्वासन ही नहीं दिया है बल्कि काम चल रहा है ।

महोदय, मैं बताता चलूं... (व्यवधान) जरा सुन लीजिए । क्या-क्या उसका निदान कैसे हो सकता है, उसपर जरा विचार कर लीजिए, फिर आपकी-हमारी बात होगी। हमने कहा कि अल्पकालीन जो सुझाव हैं, 85 एच0पी0 का 10 डीजल पम्प, 38 एच0पी0 का 10 डीजल पम्प, 22 एच0पी0 का 15 डीजल पम्प, 10 एच0पी0 का 20 डीजल पम्प, पर्याप्त मात्रा में सक्शन एवं डिस्चार्ज पाईप हो, सभी आर0सी0सी0 भूगर्भ नाला, खुला नाला, चेम्बर की साल में तीन बार सफाई हो, सभी सम्प-हाउस की क्षमता बरसात से पहले बढ़ायी जाय, बरसात से पहले संबंधित जन-प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठक हो और सम्प नाला, इन सारी चीजों का निरीक्षण हो । यह अल्पकालीन जो सुझाव थे, मैंने इनको दिया है और दीर्घकालीन योजना, जो करने लायक बात है - 1. न्यू बाइपास के उत्तरी किनारे मीठापुर से भूतनाथ रोड नन्दलाल छपरा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण जो अधूरा है, उसे पूरा कराया जाय ताकि मीठापुर के पश्चिमी इलाके का पानी इस नाले से निकल सके और निचले इलाके में पानी नहीं फैले । 2. उपरोक्त नाले के मीठापुर से भूतनाथ रोड नन्दलाल छपरा तक है, इसके उत्तरी किनारे पर समानांतर दूसरा ज्यादा गहरा नाला बनाया जाय ताकि नाला में कंकड़बाग के ड्रेनेज से स्वत: पानी चला आये । 3. जगनपुरा के पास न्यू बाईपास के नीचे कल्वर्ट नाला से बादशाही नाला तक स्लुइस गेट के साथ नाला निर्माण कराया जाय ताकि बादशाही नाला में पानी जा सके । 4. (a) कंकड़बाग ड्रेनेज प्रोजेक्ट जो एन0बी0सी0सी0 की तर्ज पर मीठापुर बस स्टैण्ड रोड से अशोक नगर तक के सभी मोहल्लों में आर0सी0सी0 नाला एवं सम्प निर्माण । (b) हनुमान नगर से भूतनाथ रोड कुम्हरार होते हुए धनुकी तक सभी मोहल्लों में आर0सी0सी0 नाला एवं सम्प निर्माण । (c) कदमकुआँ चौराहे से भॅंवर पोखर, राजेन्द्र नगर, मछुआ टोली, लोहानीपुर, नन्द नगर कॉलोनी, रामपुर रोड तक सभी मोहल्लों में आर0सी0सी0 नाला एवं सम्प का निर्माण । ...क्रमश:...

टर्न-14/आजाद:अंजली/06.03.2020

..... क्रमश: .....

श्री अरूण कुमार सिन्हा : (d) बाजार समिति से शिवशक्ति नगर संदलपुर गांव, जय महावीर कॉलोनी, वाचस्पति कॉलोनी, अलका कॉलोनी, न्यू अजीमाबाद कॉलोनी सभी मुहल्लों में

आर0सी0सी0 नाला एवं सम्प निर्माण कराने का ताकि मुहल्लों का पानी 8 घंटे में निकल जाय, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

5. योगीपुर से होते हुए पहाड़ी तक बनाये गये नाले में पहाड़ी के पास कुछ दूरी तक निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, उसे पूर्ण कराया जाय ।

6. सैदपुर नाला का पुनः निर्माण कराया जाय ।

7. पुनपुन नदी के पास पटना के पानी निकासी हेतु बड़ा सा सम्प हाऊस लगाया जाय एवं न्यू बाईपास के दक्षिण मुहल्ले के पानी निकासी हेतु बादशाही नाला के पास 2 सम्प हाऊस खेमनीचक एवं रामकृष्णा नगर में लगाया जाय ।

महोदय, यह सुझाव मैंने सभी संबंधित लोगों को एवं सभी महानुभावों को दिया है एवं आपके माध्यम से यह सुझाव दे रहे हैं ताकि दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजना को किया जाय तो इससे इसका निराकरण निकाल सकेंगे ।

महोदय, एक बात और मुझे कहनी है आपके माध्यम से कि जो मुख्यमंत्री नली-गली एवं राज्य योजना के मद में बन रहे हैं, सड़क योजना का दोहरीकरण रोकने एवं शिलापट्ट पर विधायक का नाम भी दर्ज कराने हेतु मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूँ । मुख्यमंत्री नली-गली योजना राज्य योजना के तहत पटना नगर निगम के द्वारा बड़े पैमाने पर नाला, सड़क का निर्माण किया जा रहा है और उसमें मुख्यमंत्री नली-गली योजना चयन में नगर निगम/बोर्ड में विधायक सदस्य होते हैं एवं योजना का पैसा राज्य योजना मद से मिलता है । इसलिए प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय विधायक का शिलापट्ट पर नाम अंकित होना चाहिए एवं शिलान्यास/उद्घाटन कराने के लिए दिशा निर्देश दिया जाय । साथ ही साथ नगर निगम अन्तर्गत जो स्वीकृत राशि से 5 गुना अधिक राशि की निविदा कर दी गई, पैसा मिला 90 करोड़ और 340 करोड़ का टेंडर निकल गया, इस तरह की योजना इसमें बहुत गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए इसपर जरा ध्यान देने की बात है ।

साथ ही साथ नगर निगम मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत दोहरीकरण रोकने हेतु एन0ओ0सी0 देने के बाद भी तुरंत नगर निगम द्वारा योजना का कार्य कर दिया जाता है, जिससे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन होने में परेशानी आ रही है । महोदय, इन बातों पर विशेष ध्यान मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री महोदय को दिलाना चाहता हूँ । अब जरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपलोग, हमारे साथियों ने बताया है ......

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : श्री अरूण बाबू, आपने अपना समय सिर्फ 8 मिनट ही रखा है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : हमको श्रवण बाबू समय देंगे, तब हम इतनी बात कह रहे हैं । हमको 5 मिनट और समय दिया जाय । श्रवण बाबू बोले हैं, हमारे में तो समय नहीं है ।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि एक समय था, आप देख लीजिए 2005 के पहले, यह जो नगर विकास विभाग का मेरे समझ से उस समय कोई बजट वगैरह नहीं होती थी, कोई विषय पर डिसकसन नहीं होता था, हम धन्यवाद देते हैं कि बिहार सरकार को कि उसने हर साल अपने बजट में बढ़ोत्तरी की है, यह बतलाता है कि नगर विकास के प्रति सरकार कितनी सचेत है और कितनी गंभीर है । मैं बताना चाहता हूँ कि 2019-20 में यह राशि 5158 करोड़ और अभी जो है, जिसे बढ़ाते हुए 7214 करोड़ के लगभग इसका बजट आया है । हम देख रहे हैं कि हर साल हम अपने खर्चे को बढ़ाते जा रहे हैं । सिर्फ खर्चा नहीं बढ़ रहा है, काम भी दिख रहा है । मैं पढ़ा न ....

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अरूण जी, आप इधर होकर बोलिए ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, एक समय था, जब कोई चीज का विकास या ह्रास की बात करते हैं । महोदय, जरा सुना जाय, जब ह्रास और विकास की बात करते हैं तो उसका कोई जीरो प्वायंट होता है । एक समय काल होता है । उससे कितना हम आगे बढ़े और उससे हम कितना पीछे बढ़े । मैं यह समय लेता हूँ 1990 से 2005 को लेता हूँ, जो इनका राजकाज चलता था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी धर्म-पत्नी राबड़ी देवी जी, बिहार के ही मुख्यमंत्री थी । वह समय देखा, उस समय कि स्थिति यह थी कि विकास की बात छोड़ दीजिए, अपहरण उस समय खूब पटना में होता था और जिस सुशील मोदी के विषय में महोदय, जिस सुशील मोदी के विषय में ये लोग अनाप-शनाप बोलते हैं, वह कमर भर पानी के साथ हमारे साथ घूमते थे, वो आमरण अनशन पर बैठे थे और एन0बी0सी0सी0 उन्हीं की देन है महोदय ।

(व्यवधान)

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पुराना बिहार जो है, वह वैभव वाला बिहार था, शान-शौकत से भरा हुआ बिहार था । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां मां सीता का जन्म स्थान और राम-लक्ष्मण जहां पर प्रशिक्षण पाए, गुरू गोविंद सिंह, वैज्ञानिक आर्यभट्ट जिसने जीरो दुनिया को बताया , यहां दानवीर कर्ण, चन्द्रगुप्त, गुप्तवंश जिससे स्वर्ण युग आया, बाबू कुंवर सिंह राष्ट्र के ऐसे महान और बाद में यहां के विभूति जो मुख्यमंत्री बने चाहे वो श्रीकृष्ण बाबू हों, महामाया बाबू हों, कर्पूरी ठाकुर सहित अन्य जो मुख्यमंत्री हैं ....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : राजेन्द्र बाबू का नाम नहीं ले रहे हैं ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, मैंने सब को कह दिया, समय कम था और विकास की गति, देश बीच में परतंत्र भी हुआ लेकिन उस समय में भी वो स्थिति नहीं बनी थी जो 1990 से लेकर 2005 की स्थिति बनी थी, लोग पलायन कर रहे थे हुजूर,

(व्यवधान)

यहां से भाग रहे थे, छल और बागी भी थे कोई विकास का काम नहीं था अपराधी उस तरह से घूमते थे हुजूर, जो हमलोग कभी घर में बाल-बच्चे अगर घर से आधा घंटा भी लेट हो जाए तो और विकास का कहीं कोई नाम नहीं था । महोदय, मैं आपको बताता हूं कि ये जो सरकार आयी है 2005 से लेकर और 2020 का, इसमें पुनर्निर्माण का दो-चार उदाहरण देकर पटना का सुन लीजिए और अभी आपके उदाहरण स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो बिहार का म्यूजिम है उसमें चले जाइए तो वह इन लोगों के मुंह से भी हमने देखा है कि बुद्धा पार्क, सम्राट अशोक कन्वेंशन के अंतर्गत ज्ञान-भवन, बापू सभागार, सभ्यता द्वारा एक अनोखा चीज बना हुआ है । खेल के लिए पाटलीपुत्र स्टेडियम का निर्माण किया, विज्ञान का ऊर्जा स्टेडियम दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माण कराकर ऐसे बस स्टैंड जो एक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड, यही नहीं अब पटना को हम कहेंगे तो फूलों का शहर कहेंगे, पटना को कहेंगे तो पार्कों का शहर कहेंगे, पटना को कहेंगे तो सुंदर घाटों का शहर कहेंगे, पटना को कहेंगे तो जो पथ है, उसका कितना सुंदर गंगा के किनारे चले जाइए मेरीन-ड्राइव पर लोग, आदरणीय अश्विनी चौबे जी नहीं हैं, वे जब कहते थे कि कहां गया मेरीन-ड्राइव, मेरीन-ड्राइव बन रहा है महोदय ये देख ले आकर और प्रत्येक गलियों में सड़कों का जाल, लगातार बिजली, 24 घंटा बिजली और गंगा परियोजना की तरह गंगा ....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिए, अब आपका समय समाप्त हो गया अरूण बाबू । हो गया, इन्होंने समय दे दिया, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं अंत में -

यहां कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है प्यारे,
नजर को न दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-15/शंभु-धीरेन्द्र/06.03.2020

श्री अजीत शर्मा : सभापति महोदय, आज 72 अरब का बजट पेश हुआ है, उससे उपर का पहले मंत्री महोदय को बधाई देते हैं, लेकिन 2019 में प्रस्ताव कटौती पर तो बोल ही रहे हैं, सर । 51 अरब से भी अधिक उस समय था बजट तो आपने 20 अरब से भी अधिक का बढ़ाया है लेकिन क्या आपने पिछले बजट में जो कार्य योजना हर शहर में दिया था क्या वो काम हुआ है । मैं आपको भागलपुर का पूरा बखान दूंगा, आप भी पिछले 7-8 महीना पहले भागलपुर गए थे तो वहॉं की स्थिति देखे थें, वहॉं लोग लूट-खसोट की बात कर रहे थे कि डाटा दीजिए, डाटा भी मेरे पास है । सरावगी जी, बोले थे डाटा, डाटा है किस-किस कंपनी को दिया गया है और क्या काम हुआ है । डाटा सब के पास है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोग अभी कहें कि स्मार्ट सिटी में भागलपुर हो गया । स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है ? स्मार्ट सिटी का मतलब है जनता को हर सुविधा, चाहे सड़क चकाचक होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम पूरे प्लान्ड-वे में होना चाहिए, जल-जमाव नहीं होना चाहिए, डेंगू बीमारी न फैले, स्कूल की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, जाम नहीं लगना चाहिए और पूरा शहर सी0सी0टी0वी0 कैमरे से सुसज्जित हो ताकि वहॉं क्राईम जब भी हो तो आप उस अपराधी को पकड़ सकें और सजा दिलवा सकें । क्या ऐसा स्थिति, जो स्मार्ट सिटी में होना था वो हुआ है ? मैं आपको बताऊँ, वहॉं कुछ भी नहीं हुआ है आपकी एक परियोजना भागलपुर में जल-आपूर्ति योजना पिछले, जो 2 अक्टूबर, 2014 में शुरू हुआ 2019 तक में उस काम को खत्म करना था, क्या-क्या किया ? 460 कि0मी0 पाईप बिछाना था, बिछा 175 कि0मी0 । 68,182 हाउस में कनेक्शन देना था दिया गया 11515 हाउस कनेक्शन । यह पिछले बजट की बात है इस बजट की नहीं । 63 डीप बोरिंग जो पहले था, उसमें सारे में बालू आ रहा है और जहॉं वो 20-25 एच0पी का मोटर लगा करता था, वहॉं अब 7.5 से 15 एच0पी का मोटर चलता है, इसका मतलब जो प्रेसर से पानी पहले घरों में जाता था उससे भी कम अब पानी की निकासी हो रही है, ताकि पानी घरों में पहुँच नहीं पा रहा है । जो आपने पाईप-लाईन बिछाया, जो कनेक्शन से 11,800 घरों में दिया, उसमें भी पानी नहीं जाता है । इसलिए पानी घर में जाने की बात तो बिल्कुल बकवास है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बाद में इस काम की देरी को देखते हुए 19 डीप बोरिंग बड़ा फिर से सरकार ने दिया, जिसमें मात्र 2 वर्षों में 5 ही डीप बोरिंग बन पाया है, आज तक वह भी नहीं बन पाया । इस आने वाले गर्मी में, वहॉं त्राहिमाम पानी के लिए होगा । आप ये देखिये, 19 जल मिनार जो बनाना था आपको, उसमें भी आपका 5 ही बना है और जो पाईप-लाईन बिछा है वह सड़क को काट कर, आज तक वो सड़क भी रिपेयर नहीं हुआ है । शहर तो ऐसा है

जिसमें गंदगी का भरमार पड़ा है । आप खुद मंत्री महोदय, उसका सर्वे किए हैं और सबसे बड़ी बात की जाम आखिर लगता है तो प्लानिंग होनी चाहिए कि फलाई-ऑवर बनाने का । वो फ्लाई-ऑवर बनने का कोई प्लानिंग नहीं हुआ और क्या किया गया नगर निगम के द्वारा होर्डिंग्स पूरा सात फीट इनक्रोच किया गया जमीन को, पोल लगा कर मोटा-मोटा होर्डिंग्स लगा दिया गया, जो और भी जाम से निजात मिलता, वह भी बंद हो गया है । मैं आपसे आग्रह करूंगा मंत्री महोदय, कम से कम होर्डिंग्स की कोई जरूरत नहीं है जहाँ सारे बीच सड़कों से होर्डिंग्स हटाने की जरूरत है क्यों लगाया गया, वो समझ से बाहर है । आपको बताना चाहेंगे, डम्पिंग ग्राउंड, जो कूड़ा उठाया जाता है शहर से । सरकार ने नगर निगम को जमीन दे दिया, मगर आज तक वो डम्पिंग ग्राउंड 4 वर्षों से शुरू नहीं होता है । कूड़े को सड़क के किनारे जा कर फेंकता है और उससे बीमारी फैल रहा है । बिलकुल जो विकास की बात करते हैं तो जहाँ काम हुआ है वो जाकर देखिए । दूसरी बात है कि क्वालीटि ऑफ एजूकेशन, तो शिक्षक ही नहीं हैं । मैंने वहाँ कुछ स्कूलों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा रिकॉर्डिंग वाला लगाया, ताकि शिक्षक क्या पढाते हैं और बच्चे भी एलर्ट रहते हैं कि सी0सी0टी0वी0 कैमरा चल रहा है तो ध्यान से पढ़ते हैं । इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत सारे स्कूलों में सी0सी0टी0वी कैमरा विथ रिकॉर्डिंग लगे और प्रिंसिपल उसको देखें कि शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए । ताकि वो शिक्षा में गुणवत्ता आये । स्मार्ट सिटी कैसा हो, मेडिकल और स्वास्थ में इलाज, अभी कोई अश्विनी चौबे जी, माननीय मंत्री का नाम ले रहे थे । 20 वर्ष वहाँ विधायक रहे भागलपुर शहर में, आज भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि वे स्वास्थ्य मंत्री हैं । आप चले जाईये मेडिकल कॉलेज भागलपुर में, अभी भी जमीन पर इलाज होता है और स्लाइन पानी चढ़ाए जाते हैं । उनको चाहिए था कि एम्स का दर्जा दिलाया जाए, चूंकि 20 वर्ष वहां की जनता ने उनको सम्मानित किया है और वे कोई हॉस्पीटल पर ध्यान नहीं देते हैं । स्मार्ट सिटी का मतलब, स्वास्थ्य की अच्छी तरह से देख-रेख होनी चाहिए, वह भी वहाँ नहीं है । 20 वर्षों से, भोलानाथपुर आर0ओ0बी0, माननीय मंत्री जी देखे है कि पानी के समय में नीचे इतना पानी आता है । आर0ओ0बी0 सब रेलवे का ऑब्जेक्शन खत्म हो गया, लेकिन कोई पहल करने वाला नहीं है हम लोग, यहाँ पर बात उठाते हैं दौड़ते हैं पथ निर्माण से विकास मंत्री बैठते है वो चले गए, वही योजना विभाग से । वहाँ पर 3 महीना से पड़ा हुआ है डी0पी0आर0 कोई उसको देखने वाला नहीं है । शहर स्मार्ट कैसे बनेगा, स्मार्ट तब बनेगा जबकि सभी सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध होंगी । शहर में फ्लाईऑवर, स्मार्ट सिटी में लोगों ने कैलकुलेट किया, बहुत लड़ाई हुई । फ्लाईऑवर बननी चाहिए, मगर उस समय के नगर आयुक्त ने कहा

कि फ्लाईऑवर हम नहीं बनायेंगे । मंत्री महोदय इस पर ध्यान दीजिए, स्मार्ट सिटी तभी कहलाएगा जबकि आप हर सुविधा वहाॅ पर उपलब्ध होनी चाहिए । चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, जाम से निजात का मामला हो, इलाज करने में जो हॉस्पीटल जाते है वहाॅ अच्छी सुविधा हो, सारे चीज का जब सुविधा होगा तब ही स्मार्ट माना जाएगा । अभी तक वहाॅ का ड्रेनेज सिस्टम प्लैन्ड नहीं हुआ है कि कैसे आपको बनाना है आप उस बार मिटिंग में कह कर आये थे कि गंगा में आपको गंदगी पानी नहीं फेंकना है सब गंगा में जा रहा है । उस समय बात हुई थी कि सारा प्लानिंग कर के तब ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा । मुझे पता है कि अभी तक कोई प्लान नहीं आई, जिस पर अभी तक कोई काम की शुरूआत नहीं हुई है । स्मार्ट सिटी के अंदर पैसे जो बाॅटे गए हैं, पूरा उसका डाटा है कि आप वाई-फाई में किस कंपनी को पैसे दिए गए, इसको मैं वहां ले करूॅगा चूंकि बहुत लंबा है । इन्होंने बोला है इसलिए एकाध बता देते हैं । वाइफाई इन्टरनेट कनेक्शन के नाम पर इनफेरीटी टेक्नोलॉजी को 16.66 लाख रूपये, अमोर इन्ट्रो को 16.20 लाख रूपये का भुगतान किया गया है जिसके लिए मात्र कोटेशन का इस्तेमाल किया गया जबकि 5 लाख से अधिक की योजना के लिए निविदा की प्रक्रिया आवश्यक है । इसका वैसे ही कोटेशन पर काम कराया गया है इसकी आप जाॅच कराइये तब पता चलेगा । काम तो कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ पेमेन्ट हुआ और घोटाले हुए हैं । टाउन हॉल भालगपुर में स्मार्ट सिटी के लिए सेमिनार भवन के साज-सज्जा के नाम पर प्रतिभा नामक एजेंसी को 2 लाख 14 हजार रूपये का भुगतान किया गया जबकि उक्त कार्य को करने हेतु सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं है । यह सब छोटी-मोटी बात इसमें लिखी हुई है । दूसरी बात है कि नगर निगम कैसे सुधरेगा- नगर निगम में जो वार्ड पार्षद् जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं उनके पास कोई कोष नहीं होता, उनको मानदेय भी बहुत कम मिलता है । हम आग्रह करेंगे जैसे कि दिल्ली में, मुम्बई में सभी पार्षदों को उनके फण्ड होते हैं, बॉम्बे में तो 2-2 करोड़ है । आप कम से कम नगर निगम में सभी पार्षद्ों को क्या होता है कि जनता जब उनको काम कहती है तो वे नगर आयुक्त को जाकर हाथ जोड़ते हैं कि सर मेरा ये काम है । एक प्रतिनिधि की यह हालत है वहां तो वह काम क्या करेगा ? मेयर का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए, पब्लिक से ताकि वह जो कुर्सी बचाने में दो-ढाई साल बिता देता है वह बंद हो जायेगा, तभी आपको वहां विकास दिखने में आयेगा कि नगम निगम में क्या काम होता है । हरेक पार्षद् को 50-50 लाख रूपया इस बजट में और बढ़ाकर देते वही पैसा जो आप सरकार के द्वारा लगाते हैं इनके माध्यम से भी मिलेगा, जैसे कि हम विधायक लोग बैठे है । जो हमलोग अपनी निधि से काम करते हैं वह काम आपको नहीं करना पड़ता है ।

इसलिए पार्षद्ों के माध्यम से करना चाहिए ताकि आपका विकास हो सके । अभी हमारे सुबोध भाई बोल रहे थे सुल्तानगंज के बारे में काम की बहुत तारीफ किये, लेकिन जहां से जाते हैं भागलपुर में चम्पानगर, नाथनगर में पानी की क्या समस्या है वे आप देखे होंगे । वहां घरों में पानी बिलकुल नहीं जाता है ।

(व्यवधान)

नहीं-नहीं मजबूरी की बात नहीं है । देखिए जनता हमलोगों को यहां भेजती है उनकी आवाज बनकर बता रहे हैं कि वहां क्या काम की जरूरत है । वह सरकार को सुनना और करना है । यहॉं तो विपक्ष का 1990 में क्या हुआ, आज क्या कर रहे हैं उसपर बात होनी चाहिए पीछे क्या हुआ, पीछे मेरे पिता जी क्या किये, मेरे दादा जी क्या किये उससे कोई फायदा नहीं होनेवाला है । महोदय, जनता सबको देख रही है, चुनाव सामने आनेवाला है । हमलोग कैसे काम करें जनता की सुविधा के लिए आवाज उठाते रहें, इन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए न कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए- हमलोग सभी एक हैं और सभी को चुनाव में जाना है ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : अब दो मिनट में समाप्त कीजिए अजीत बाबू ।

श्री अजीत शर्मा : एक तो मेरे राजेश भाई का है बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर 4 एच0-50/51 में नाली का जल जमाव है । उस जमाव की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । यह तो बहुत छोटी बात है लेकिन पटना में भी जो हालात था, इस बार ड्रेनेज का था वह कभी नहीं रहा होगा जो लोग पटना में रहते हैं, हमलोग तो बच्चे से पटना आते जाते रहते थे, चूंकि लोग अच्छे इलाज के लिए पटना ही आते थे या फिर दिल्ली जाते थे । यहां पर सबलोग जो पिछला बरसात में देखे हैं ड्रेनेज सिस्टम कोलेप्स होने का- मेरा मानना है कि मुख्य कारण जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसका जो बालू है, छड़ी है जिसको रोड पर गिराया जाता है वह नाली में जाकर जाम करता है । पहले भी बहुत बारिश होती थी, ऐसा नहीं है कि इसी बार बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन पहले यह हालत नहीं होती थी ।

क्रमशः

टर्न-16/06:03:2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री अजीत शर्मा : अभी क्या है, कोई कंट्रोल नहीं है । बजट तो मंत्री महोदय आप बना देते है लेकिन आपका ग्रीप होना चाहिए । पदाधिकारी क्या काम करते हैं ? उसकी जॉंच होनी चाहिए, यहाँ जो रोड पर जो छर्री, बालू गिराता है, चूंकि सारे नाले में ढक्कन नहीं है । आज जितने भी नगर निगम के नाले हैं, सारे ढक्कन पर कवर होना

चाहिए नहीं तो यह बालू, छर्री हमेशा नाला जाम करेगा । ऐसा होने पर आप जल जमाव से निजात नहीं पा पायेंगे, इसी तरह लोग पानी में घूमेंगे । बहुत-बहुत, धन्यवाद, आपको चूँकि मेरे बाद अवधेश बाबू को बोलना है, आपने मौका दिया । यहॉ पर मैं केवल एक ही आग्रह करुंगा कि विपक्ष और सत्ता में आरोप लगाना हम लोग आपस में बंद करें और विकास कैसे हो और सरकार का नाम कैसे हो, विपक्षी दल का नाम कैसे हो और हम सब मिलजुल कर काम करें । धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, निश्चित तौर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए प्रस्तुत माँगों पर लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, किसी भी राज्य के लिए नगरीय सुविधायें उपलब्ध होना उसकी प्रगति का प्रतीक है । किसी शहर के लिए उसकी बसावट, उसकी कॉलोनियॉ, उससे मिलने वाली सुविधाएँ, आधुनिक संचार के साधन, शैक्षिणक मनोरंजन के साधन, स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगार का हब, सुप्रभावी सूचना तंत्र और स्वच्छ वातावरण आवश्यक है । महोदय, आज माननीय मंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मैं मतदान कर सकता था, जो आदरणीय सदस्य कह रहे हैं हम इन्हीं के पक्ष में रहते लेकिन अगर ये सारी सुविधायें यहॉ रहती, परन्तु हम लोगों का दुर्भाग्य हैं कि आज तक राजधानी पटना का कारगर मास्टर प्लॉन नहीं बन पाया है । अन्य जगहों की बात तो अलग है । आप उठा लीजिये, पटना के किसी कॉलोनी को, वह बसी कॉलोनी नहीं है बल्कि बेतरतीब ढंग से मकान पहले से खड़े कर लिए जाते हैं फिर उसकी आधारभूत संरचना के लिए वहॉ के निवासी इधर उधर दौड़ लगाते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं । कभी बॉस पर बिजली ले जाना, कभी ईंट के टुकड़े से निजी तौर पर बनायी गयी सड़कें ही उनकी नीयति हैं । हम तो इनके पक्ष की बात करते लेकिन जिसतरह से इन्होंने टोका-टोकी करने का काम किया तो मेरे भी कहीं-न-कहीं जमीर को धक्का लगा है कि जहॉ हम हमेशा कहते रहें, जहॉ आप अच्छा काम करें हम आपकी तारीफ करें जहॉ आप गलत करें, वहॉ आप एक्सपेट करिये । आपका किताब जो आज हमने देखा है काश ! आप इसमें जो आपने अपने फोटोग्राफ्स डालें । सारे फोटोग्राफ्स डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें से एक फोटोग्राफ्स घट गया है । काश, आदरणीय सुशील मोदी जब बाढ़ के टाईम में थे एक फोटो वह भी लटका देते तो शायद सारी चीज स्पष्ट हो जाती कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और लेसन आपको खुद ही लेना है । जो करता है वही गलती करता है, हमारे पूर्वज कहा करते थे, कांग्रेस से लड़े और अंग्रेज को घुटना

टेक कर मार कर उसको ठीक करते थे लेकिन मनुवादी व्यवस्था में जब हमलोग आए तो अपने ही मुंह से दबे और कुचले कहलाए चाहे कितने पैसे से समृद्ध हों लेकिन हमेशा कहा जाता था कि बैकवर्ड हैं और आज इसी सदन में एक मंत्री जी कहते हैं कि हम एनेक्सर-वन से आते हैं तो यह दुर्भाग्य है कि 15 साल बनाम 15 साल आप करते रहे । 15 साल तो आप ही के नहीं हमेशा जदयू के साथ रहे और बी.जे.पी वाले अपने इस नगर का विकास आप ही के पास था । हम भगवान से हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप नगर विकास की चीजों को खुद समझे चूँकि दर्द आपका सबसे ज्यादा है । सबसे ज्यादा एम.एल.ए. आपके हैं लेकिन जिले के सभी लोग जदयू हो या आर.जे.डी. हो सभी लोग उन्हीं जिलों में बसते हैं । कष्ट दरभंगा का नहीं है, कष्ट समस्तीपुर का नहीं है, कष्ट पटना का नहीं है, कष्ट मधुबनी का नहीं है, कष्ट जिलों के वासी का हैं । इसको एक मान कर चलना चाहिए और दर्द जब अगर बयान करने लगे तो आप कुछ भी कह लीजिये । हम तो कहते हैं इस डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव पॉंच साल नगर विकास में उनका कहीं स्थानान्तरण नहीं करना चाहिए वहीं रखना चाहिए । ये कौन सी बात करते हैं पटना की । एक बार पानी आता है अगले बार कि नहीं पी.आर.डी.ए. हुआ करता था नाम है ना, नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को हटा दिया जाता है । हमेशा आप लोग यही करते हैं आज पटना के बुडको के एम.डी. को हटा दिया गया यह कौन सी बात है । अरे, सम्प आपका नहीं चालू हुआ खुद हमारे माननीय विधायक की एक सौ वर्ष में नहीं पहली बार बारिश हुयी है क्यों झूठ बोलते हैं । भगवान को झूठ-मुठ बोलकर कहते हैं, पटना को कहते थे कि हमें, यहॉं का मत सोचिये पूरे देश आधार पर मत सोचिए । इन्हीं के मंत्री कहा करते थे कि हम सिंगापुर पटना को बना देंगे । कौन-सा सिंगापुर बन गया आज हमारे मंत्री बतायें ? हम आपको चुनौती देते हैं कि आप निश्चित तौर पर वे बातें करे जिस बात को आधारभूत संरचना के साथ आप स्थापित करने का काम करें । आप कौन सी बात करते हैं । आप जिसको देखते हैं उस अर्हता के हिसाब से आप तो देते नहीं है आप और हम बात करे पूरे बिहार की हम नगर विकास की बात करें तो हमको लगता है कि जब-जब मधुबनी हमारा है । एक भी सड़क जो दस विधानसभा की है दो मंत्री है, चार-चार मंत्री है शहर की एक सड़क आपकी सही नहीं है जो चल पाइएगी । तब अंत में हम कह सकते हैं कि अगर नगर विकास की कोई सड़कें नहीं हैं सब पी.डब्लू.डी में कनर्वट हो गया । क्या बात करेंगे अगर हम लोग को अगर ये कहा जाए कि बनावट के हिसाब को अपने-अपने शहर का सारा चीज उनको दे दिया जाए, सारा डिपार्टमेंट उस में निहित हो जाए तो कैसे हाईकोर्ट चलता है । हाईकोर्ट में कोई भी जज अगर

मान लीजिए कोई तकलीफ होता है तो अपने स्टॉफ में बोलते है। सब डिपार्टमेंट मिलकर के एक तरह का काम करते हैं पूरे नगर विकास को पूरी तरह सम्मिलित करके उनके बसावट में बसने वाली सभी चीज उनकी ना हो । आप बात करते हैं इलेक्शन करा दिये, पर हॉर्स ट्रेडिंग को रोक ही नहीं पा रहे हैं । आप कानून बनाते हैं कि हरेक दो साल में की नहीं आपको पैसा नहीं देते है और महंगाई भत्ता नहीं देते हैं कहते है सुशील मोदी जी खजाना खाली है और दूसरी तरफ लूट जारी है । क्या कर रहे हैं? ये प्लानिंग में कहीं ना कहीं बड़ा दोष है । मैं नहीं बोलना चाहता था मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर रहता । लेकिन दर्द यही कहता है कि हम बार-बार चाहते हैं कि आप क्या हम अपॉजिशन में है इसलिए आप हमको दर्द दे रहे हैं । मत पूछिये पूरे बिहार के लोग शहरवासी एक ही तरह के होते है और शहर के मतलब होते है । टोटल विधान सभा का हेडक्वार्टर । आप अपनी प्लानिंग को दुरूस्त करिइये । पटना केवल हाउस के सही नहीं रहने के कारण इतना बड़ा लोक की नहीं। हमारे सैकड़ों रिलेशन कोई देखने वाला नहीं था । तब हम लोगों ने महसूस किया, देखा और उसके हिसाब से उसको दूर करने का प्रयास किया । नंद किशोर बाबू सामने में है माननीय मंत्री रहकर के भी इन्होंने 5 साल में क्या किया? कम से कम अपने जियो का प्लानिंग ऐड सही ढंग से करते तो आज ये देखने को नहीं मिलता । नगर विकास अगर इस राज्य में हुआ होता तो सारे लोग का केन्द्र बिन्दु राजधानी पटना ही नहीं रहता । राज्य का कोई ऐसा शहर नहीं है जो पटना के समकक्ष हो । एक ही जगह है आपका पटना । हमारे अगल-बगल के राज्यों में चले जाए जितने भी शहर बने है राजधानी के समकक्ष बने हुए हैं । आप बगल के यू.पी को उठा ले राजधानी लखनऊ है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, मेरठ है, कानपुर है, आगरा है, कम से कम दर्जनों हैं । लेकिन बिहार में क्या है केवल पटना ? तो शहर के बाद जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व विभाजित हो जाता है और राजधानी स्तरीय में लोग बसावट करते हैं लेकिन हमारे शहर की नीयती है कि आज सारे लोग का केन्द्रबिन्दु केवल राजधानी पटना और वो भी ऐसी पटना जहां कचरा प्रोससिंग प्लांट तक नहीं लगा है । नतीजा यह होता है कि कचरा यहां से उठाकर वहां फेंका जाता है बवाल वहां होने लगता है । महोदय, पटना में ही है आप मानकर चलिए बार-बार ये 2003 पर, 15 साल हो गया । बार-बार हम लोग कहते रहें कि कम से कम इस तरह से क्यों नहीं श्रेणीबद्ध करते हैं कि नगर-निगम को 25 एकड़ जमीन खरीद कर दे दीजिए । नगर परिषद् में 15 एकड़ दे दीजिये, नीचे का है तो 10 एकड़ दे दीजिये । जमीन तो दे दीजिये, उपलब्ध करा दीजिये । कचरा निस्तारण का पैसा देते हैं । केवल मैं नहीं कहता । आप उसके तह में

जाकर देखिये कि कारण क्या है ? किस कारण से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, जब उन चीजों को देखेंगे तब इन चीजों को कर पायेंगे । जब हम जलवायु नियंत्रण इत्यादि की बात कर रहे हैं लेकिन वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कचरा है । राज्य में इस कचरे से भी बड़ा खतरा मेडिकल कॉलेज के कचरा का है । सब जगह देख लीजिये । सारे लोग पर्यावरण के केस में पड़े हुए हैं । जितने आपके हॉस्पिटल है, सारे लोग परेशान हैं ।

क्रमशः

टर्न-17/कृष्ण-संगीता/06.03.2020

श्री समीर कुमार महासेठ (क्रमशः) : अगर सब परेशान हैं तो कहीं प्रिसिंपल परेशान हैं, कहीं सुपरीटेंडेंट परेशान हैं, परपस है कि आपको देखना है कि परेशानी का कारण क्या है ? इन्डीविजुअल केस होता है ।

(व्यवधान)

हमारे माननीय मंत्री जी सामने हैं ही बड़े भाई महेश्वर हजारी जी, कोई चीज इनसे छिपा हुआ नहीं है । हमेशा चाहते रहें लेकिन पता नहीं, क्या कारण है, आप एक बार प्लान कीजिये, 50 साल के आगे की प्लानिंग कीजिये, कौन-सा पटना है ? आज प्लान बनाते हैं 50 साल का, जितने पुल हैं, सब छोटे हो गये, यह किसकी गलती है ? कहता है पुल निर्माण निगम, फलां-फलां । आप कहां-कहां से इन्जीनियर्स लाये ? फिर से उसका रीस्ट्रक्चरिंग करा रहे हैं । कारण तो आपको समझना है । मैं नहीं कह सकता । मैं यह कह सकता हूं कि जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं करेंगे, बार-बार आप करायेंगे । आप जो भी लायेंगे, आप खुद फेल होंगे। अगर प्लानिंग ढंग से नहीं करेंगे, एक्जेक्यूशन सही ढंग से नहीं होगा । मेरा आग्रह है कि हम गलती करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें खुद पता चलना चाहिए कि मैं यह गलती कर रहा हूं । मुझे खुद को सुधारने की नियति है । सुधार कर लूंगा । लेकिन अगर सरकार इससे बचना चाहती है तो बच जाय लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि 42 तरह के घोटाले इस राज्य में हुये हैं, इसका निरीक्षण करना आपका काम है। आप तो 15 साल बनाम 15 साल करते रहे, आप करते रहिये, आगे कोई न कोई सरकार बनेगी । आपका अगर प्लानिंग सही होगा तो उसको एक्जेक्यूट करानेवाला आगे होगा, आपके दिशा-निर्देश पर चलेगा, नाम आप ही का होगा, आप आगे क्या करेंगे ? आप जानिये लेकिन लोग तबाह हैं पटना को देख करके । महोदय, केवल बिहार ही

नहीं तबाह है, पूरे देश में उस समय रहनेवाले, सब अपना-अपना टेलिफोन करके यही कहे कि हमारा पटना कितना सुंदर था, हम गांव से पटना आये थे, आज पटना का यह हाल हो गया तो आगे क्या होगा ? चूंकि आगे तो सब भगवान भरोसे है । केदार बाबा को पकड़े तो जान बची । अब कौन बाबा को पकड़ने जाईयेगा । आप ही समझिये, हमको कुछ नहीं कहना है । हम क्यों बोलने जाय ?

(व्यवधान)

जो भी हालात हैं । इस विषय के साथ-साथ हम आपका ध्यान मधुबनी ले जाय, जो आप ही का विषय है, इतने दिनों से वहां है एक बस स्टैंड का अभाव है, कम से कम कुछ तो करावें । जो खराब स्थिति है, चारो मंत्री मधुबनी के ही हैं । अगर 25 - 25 परसेंट बांट लें तो पूरा हो जायेगा ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य इधर मुखातिब होकर बोलिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : निश्चित तौर पर हम चाहेंगे जो जातिगत सर्वेक्षण हुये थे 2011 में, हुजूर, 2021 की बात हो रही है । उस समय पूरे सदन के द्वारा यह बातें होनी चाहिए थी, 2011 का सर्वेक्षण हुआ, जातिगत क्यों नहीं, उसको पब्लिश नहीं किया गया, 11 दिनों की जो सरकार थी, उस समय की द देन सरकार उसको रोक कर रखी, पहले हमको उसका अधिकार मिलना चाहिए

(व्यवधान)

वह तो हैं ही । जो हमारा 26 प्रतिशत आबादी है, 56 उपजाति है, मेरा आग्रह होगा कि आगे इस सर्वेक्षण में मारवाड़ी मारवाड़ी वैश्य लिखें, सुढ़ी सुढ़ी वैश्य लिखें, तेली तेली वैश्य लिखें, कानू कानू वैश्य लिखें, रोनियार रोनियार वैश्य लिखें, जायसवाल जायसवाल वैश्य लिखें तब जाकर आगे की बात होगी ।

इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रत्येक पांच साल में सरकार यह निर्णय करे, एक बार जहां अविश्वास प्रस्ताव लग गया है, दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगे, तब हम समझेंगे कि हौर्स ट्रेडिंग को आप रोकना चाहते हैं । चैलेंज है आपको, बी0पी0एस0सी0 से आपने एक्जेक्यूटिव ऑफिसर की बहाली तो कर दी, साथ ही आपने नगर प्रबंधक की बहाली कर दी लेकिन उसने ट्रेनिंग लिया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि वह क्या काम करेगा । केवल वह पैसा कमाने वाला काम कर रहा है । उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिला है । तो सरकार क्या चाहती है ? टॉप टू बॉटम संलिप्त है किसमें, वह बताने का काम करें । आप बिना ट्रेनिंग दिये हुये उनको भेज रहे हैं और इस सदन में बार-बार यह मैटर आ रहा है । अगर चैयरमैन का, वाईस चेयरमैन का और कौंसिलर का डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाय तो आनेवाला भविष्य भी आपका सुधर सकता है । निश्चित तौर पर हमें अपेक्षा है कि आप इसको

आगे बढ़ करके करें । कम से कम जिस तरह से सारे निकाय हैं, आप कम से कम जमीन खरीद करके उसको प्लानिंग के हिसाब से उन्हें दे दें ताकि आगे कचरा निस्तारण में मदद करे । अभी जो एल0ई0डी0 लगा है पूरे बिहार में, कम से कम उसका तो सही निर्णय करा लें । हुजूर, 50 परसेंट ही लगा है और 50 परसेंट लगना बाकी है । पता नहीं पेमेंट मिला कि नहीं मिला । इसका मुझे नहीं पता । आप इसकी जांच करा लें । मैं चाहता हूं कि धरातल पर वह उतर जाय । मैं बुडको को धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहां 115 करोड़ से नाले का निर्माण करा रहे हैं । लेकिन उसको मोबलाईजेशन फंड दिये हैं 2.5 करोड़ और ढाई महीने के बाद बरसात आ जायेगा, पटना का जो हाल हुआ था, वही हाल मधुबनी का होगा और उस समय हम चारो मंत्री जी को कहेंगे, हे, मंत्री जी कम से कम आप माननीय मंत्री जी से पैसा दिलवा दीजिये ताकि काम का प्रोग्रेस और उसके हिसाब से एग्रीमेंट हो और काम का प्रोगेस हो तब जाकर होगा अन्यथा हम यही कह सकते हैं कि जो दरभंगा का जो मदारपुर का बच्चों का महत्वपूर्ण संस्थान है, चारो सड़क जर्जर है, अल्ली पट्टी से मदारपुर, मारवाड़ी कॉलज से मदारपुर, होली क्रॉस से जानेवाली सड़कें । शायद हम चाहेंगे कि इसको भी पी0डब्ल्यू0डी0 में कंवर्ट करा लें, मंत्री जी बैठे हुये हैं, इससे भी इनका पिंड छूट जायेगा।

महोदय, हम यही चाहते हैं कि आनेवाले समय में निश्चित तौर पर हम आपको इस सरकार में कम से कम अध्यक्ष की कुर्सी पर हम देखना चाहते थे, इस सरकार में तो हमलोग उपाध्यक्ष की कुर्सी हमलोग मांगते रहे लेकिन आज तक हमलोगों को यह मौका नहीं मिला कि हमारी पार्टी को भी उपाध्यक्ष का पोस्ट मिले। यह पहली बार हो रहा है ।

(व्यवधान)

आजादी के बाद यह पहला विधान मंडल होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका सिनेट का सदस्य नहीं बना । यह आपके लिये कलंकित होगा । आप चाहे तो अभी भी सुधार सकते हैं । अब हम और क्या कहेंगे, आगे के हिसाब से, अपनी बनावट खुद ही बना लें । आपलोग इधर आनेवाले हैं । हमलोग उधर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग होगी । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह) : भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री सत्य नारायण सिंह ।

श्री सत्य नारायण सिंह : सभापति महोदय, विपक्ष द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग के विरोध में जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसके विरोध में और सरकार के द्वारा जो इतना बेस्ट बजट लाया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ ।

सभापति महोदय, सारे विपक्ष के साथियों की बातों को मैं सुन रहा था लेकिन जब तक पैसा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा तो उसमें जब सरकार अच्छा काम कर रही है, उसमें कटौती लाने की कहां से बात है, आपको तो कहना चाहिए कि जैसी मांग कर रहे हैं, यह काम हो, वह काम हो, वह काम हो तो कहना चाहिए कि और काम हो । जैसे नगर विकास में पूर्व में हम अपने शहर डिहरी ऑन सोन या दाउनगर से लेते हैं और सरकार की सोच देखिए कि कम पैसे में ज्यादा काम, जैसे एल0ई0डी0 लाईट की बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी सोच है, आप जाएं कहीं भी नगर परिषद में पूरा वार्ड, रोड चकचक है, लाईट से जगमग है और बिजली का खर्च भी कम है। यही सोच देखिए । नेता का काम है अग्रसोची । कितनी अच्छी सोच है कि बिजली कम लगे और लाईट भी जले ।

क्रमश :

टर्न-18/अंजनी-अभिनीत/दि0 06.03.2020

श्री सत्यनारायण सिंह (क्रमशः) : यही सोच देखिए । नेता का काम है, आगे की सोचिए तो कितनी अच्छी सोच है कि बिजली का बिल भी कम लगे और लाईट भी जले । बहुत से साथी अभी चर्चा कर रहे थे, हमने सोचा नहीं था। अब आप पटना को देखिए, पटना में जहां हम रहते हैं, वहां उस नाले को देखें जिसमें गंदा पानी के कारण गंध-दुर्गंध आता था, लेकिन अब आप एम0एल0ए0 कॉलोनी से लेकर के जायें तो नाला पाटकर जो रोड बना है, लगता है कि अब हमलोग दिल्ली आ गये हैं। आप वहां से आयें बगल में, हम देखा करते थे, विधान सभा के बगल में जो अभी पार्क देख रहे हैं इको पार्क, जहां गंदगी का साम्राज्य था । आप पटना नगर निगम के किसी भी वार्ड में चले जायें, हर वार्ड में आपको पार्क मिलेगा। पटना में आप कहीं भी चले जायें, आज पटना को पार्कों का नगर कहा जा रहा है । खास कर के जहां डेहरी ऑन सोन की बात हम करते हैं, दाउद नगर की बात हम करते हैं, जहां आप रहते हैं, वहां से आप तुलना करें तो देखेंगे कि पूर्व की अपेक्षा, साथी लोग चर्चा करते थे कि डेहरी वो शहर था जहां 15 वर्ष पूर्व एक जज साहब जा रहे थे और मेन रोड में उनकी गाड़ी अटक गयी और जबकि 15 साल पूर्व पथ निर्माण मंत्री के क्षेत्र में जज साहब की गाड़ी अटक जाती है, इसलिए साथियों गाड़ी अटके नहीं, लाईट चकचक रहे तो उसके लिए आपको दिल खोलकर कहना चाहिए, नहीं कटौती नहीं और जो काम करता है उसको तो ज्यादा ईनाम मिलता है और दाम मिलता है तो आपलोगों को कटौती प्रस्ताव खास कर के एनडीए की जो सरकार माननीय नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, किसी भी क्षेत्र में अभी साथी हमारे चर्चा कर रहे थे और हमारे पथ निर्माण मंत्री भी यहां हैं, जब हमलोग 15 साल पूर्व आते थे मात्र एक सड़क था जो

पटना नहर से होकर हमलोग आते थे और आठ घंटा लगता था, लेकिन आज जो डबल इंजिन की बात करते हैं पटना आने के लिए, साथ-साथ एक पुल था गेमन पुल, आज चार-चार है दाउद नगर के सामने, अरवल के सामने कई एक पुलों का जाल है । किसी भी विभाग में आप जायें, जो जर्जर सिंचाई विभाग का जो रोड था आज यहां नहर पकड़ें और चले जायेंगे मात्र ढ़ाई से तीन घंटे में। साथियों, कहने का मतलब यहां कटौती नहीं आपको दिल खोल कर कहना चाहिये कि सरकार अच्छा काम कर रही है, बल्कि और पैसा दिलवाने का काम करिए और बड़ा बजट लाइये, पूर्व में जो बजट हुआ करता था आज डेहरी ऑनसोन में नगर विकास के द्वारा, पहले तो सोचा नहीं करते थे आज मॉल बन रहा है, आज लाइब्रेरी और खास कर के पटना में तो हम देख रहे हैं कि पुलों का जाल बिछा है, पहले हम देखें थे एक्सलेटर वाला सीढ़ी दिल्ली में लेकिन अभी बापू सभागार में सभापति महोदय, जब हमलोग सामने गये तो एक्सलेटर चालू था तो मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज दिल्ली में नहीं है, वह चीज बिहार में है ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) : आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री सत्यनारायण सिंह : महोदय, हमारे डेहरी नगर में बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन हमारे मंत्री जी, प्रधान सचिव भी ध्यान देंगे कि आज वहां पार्क के लिए जमीन एलॉट हो गया है, डी0पी0आर0 बुडको के द्वारा आ गया है बल्कि प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी होती है, उसे सैंक्सन करा दें, प्रधान सचिव ने विमर्श लिखा है, इसको निष्पादित कराया जाय । साधन की कोई कमी नहीं है, नगर परिषद में हमारे यहां 100 करोड़ रूपया है, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति आप कर दें, सवा दो करोड़ का जमीन हमने एलॉट करा दिया है, अपने नेता नीतीश कुमार, मोदी जी से आग्रह करके । 6 एकड़ जमीन है, पार्क बन जायेगा तो बहुत अच्छा हो जायेगा। एक स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का भी डी0पी0आर0 आया है, उसको भी आप स्वीकृत करा दें तो नाली की भी समस्या सोल्व हो जायेगा । एक आग्रह हम और करेंगे कि वहां डालमियां फैक्ट्री की जमीन थी और लिक्विडेटर से बात हुई है, जो वहां की कमिटी है, जो चेयरमेन हैं, जो एक्ज्युकेटिव है, उनको कहा है, पार्क के लिए जमीन दिये हैं, फिल्ड दिया है, उसकी नापी कराकर यथाशीघ्र डेट भी शायद परसों था, उसको आप करा दें तो डालमियानगर आपको फिल्ड के लिए, पार्क के लिए और नाला के लिए सब दे देगा...

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री सत्यनारायण सिंह : एक मिनट सर । हमारे क्षेत्र का है, डालमियानगर फैक्ट्री आज 1984 से बंद है, उसका रोड स्टेशन से जाकर पी0डब्लू0डी0 में मिलता है, उसका भी प्रस्ताव

वहां से आयेगा, उसको सैंक्सन कराने का काम करेंगे । इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) : माननीय सदस्या, श्रीमती अनिता देवी, राष्ट्रीय जनता दल, आपका समय पांच मिनट है ।

श्रीमती अनिता देवी : सभापति महोदय, आज मैं सरकार द्वारा लाये गये नगर विकास एवं अन्य विभागों पर लाये गये मांग के विरोध में एवं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । महोदय, आपको भी धन्यवाद देती हूं कि मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया । माननीय श्री लालू प्रसाद, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी तथा माननीय तेजस्वी यादव जी को भी मैं तहेदिल से धन्यवाद देती हूं और हम जिस समाज से आते हैं अति पिछड़ा उस समाज को भी मैं तहेदिल से धन्यवाद देती हूं। नगर विकास में जो माननीय लालू प्रसाद, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल में जो कार्य हुआ है उनकी चर्चा देश में ही नहीं विदेश में भी हो रही है। जिस तरह माननीय लालू प्रसाद जी ने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए भी शहर में नगर विकास के द्वारा जो मकान बनाये गये थे, रैन-बसेरा बनाये गये थे, रिक्शा पड़ाव बनाया गया था, मछली घर बनाया गया था, सब्जी मार्केट बनाया गया था और जो गरीब के लिए आवास बनाया गया था, न आज-तक उसका रंग-रोगन हुआ और न मरम्मत हुआ। लोग कहते हैं कि 15 साल में क्या हुआ, आपलोग बताइये कि 15 साल में जो लालू जी किये उनका आजतक न मरम्मत हुआ और न रंग-पोतायी हुआ। जब अति पिछड़ा, दलित इस लायक हुए तो मनुवादी लोगों को पेट में दर्द होने लगा कि आज गरीब-गुरबा लोग, जनता जाग गयी है और अपने हक के लिए लड़ रहा है, इसलिए मैं अब नगर विकास और पी0एच0ई0डी0 के बारे में मैं दावे के साथ कहती हूं, और मेरे क्षेत्र की समस्या है कि नगर पंचायत नोखाकाली स्थान से लेकर पश्चिमपति तक न रोड है और ना नाली है । बरसात में पता चलता है कि रोड नली है कि नली रोड है पता ही नहीं चलता है।

(क्रमशः)

टर्न-19/राजेश-राहुल/6.3.20

श्रीमती अनिता देवी, क्रमशः पता ही नहीं चलता है, वहॉ पर 2016 में बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ था, आज तीसरा साल होने जा रहा है लेकिन आज तक उस पर एक ईट भी नहीं लगा है माननीय सभापति महोदय, नोखा में पियरा बांध है, जो आजादी के 72 साल हो गए और एक धोमा टोला है, आज भी वहां रोड़ नहीं है, आज भी महिलाओं

को जब प्रसव होता है, तो बरसात के दिनों में लोग उसको खाट पर बिठाकर लेकर जाते हैं, क्या यहीं है सबका साथ सबका विकास ? नोखा के लोग आज भी 70-72 साल के बाद भी बरसात के दिनों में हाथ में चप्पल लेकर जाने को मजबूर हो जाते हैं और महिलाओ की तो बात ही छोड़िये, प्रसव के समय लोग खाट पर बिठाकर ही ले जाते हैं और नासरीगंज में तीन साल से जो बस स्टैंड बनकर पड़ा हुआ है, वह ढ़ेड करोड़ की लागत से बना है और अभी तक वह हैन्डओवर नहीं हुआ है, न जाने कितने ही ऐसे नगर विकास के काम जो अभी अधूरे हैं, जो अभी बजट आया है, आपको 72 अरब 71 लाख 54 हजार का जो बजट है, ये बजट बहुत बड़ा है लेकिन केवल शहर में ही काम हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो माननीय मुख्यमंत्री की जो स्मार्ट सिटी बनाने की पहल थी, वह पहल तो बहुत अच्छी थी कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यहां 6-7 स्मार्ट सिटी शहर को ले लिया गया है और जगह को तो छोड़िये, अपने बगल के पटना को देख लीजिए, जो बरसात में आए दिन में देखने को मिला है, जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ, यह सब विकास के साथ जो काम हो रहा है, वह सबका पोल खोल कर रख दिया है कि इस नगर में क्या हो रहा है माननीय सभापति महोदय, आप नगर विकास के माध्यम से सिटी स्मार्ट योजना, अटल नवीकरण योजना और नगरीय-शहरी आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया है और पी0एच0ई0डी0 भी है, मैं दावे के साथ कहती हूं कि जब अप्रैल के बाद सारे चापाकल सूख जाते हैं, तो हम लोग फोन भी करते हैं और वहां पी0एच0ई0डी0 के जितने भी अधिकारी है, कहते हैं मैडम, आज मिस्त्री जायेगा, कल जायेगा, कहते-कहते पूरे गर्मी के दिन भी बीत जाते हैं लेकिन एक भी अधिकारी वह चापाकल बनाने के लिए नहीं आता है और जो शहरी आवास हैं, नोखा पिछड़ा और अति पिछड़ा है बगल में जब बहुत सारे लोग सर्वे करके देते हैं लेकिन उन्हीं लोगों का शहरी आवास योजना में घर बनाया जाता है, जिसके पास पहले से ही घर है, यदि माननीय मंत्री जी को विश्वास न हो, तो हमारे साथ चलिए और देखिए कि नोखा, नासरीगंज की स्थिति क्या है, बद से बदतर है और रोड नली जो नोखा का है, पियरावाल का है, मैं माननीय मंत्री जी से एक बार नहीं दस बार भी कही हूं दो-चार पत्राचार भी किए हैं लेकिन हम लोग हैं राजद के तो काम कहां से होगा.........

(व्यवधान)

लेकिन महोदय सहयोगी सरकार द्वारा गरीबों के आवास जो नगर विकास द्वारा बनाए गए हैं उसकी किसी भी मरम्मती का पैसा नहीं आ रहा है न और कुछ आ रहा है महोदय इस बजट में भी केवल ऐसे गरीब, दलित, शोषित को बाहर किया गया है जिसका न घर है, न खेत है, न खलिहान है, न जमीन है, ये सरकार जो है, केवल

पूंजीपति की सरकार है, अमीर की सरकार है, जिसके पास पैसा है, उसी का पी0एच0ई0डी0 का काम हो रहा है या कोई भी आवास योजना हो, चाहे गरीब का एक भी काम नहीं हो रहा है यह सरकार गरीब विरोधी है, पूंजीपति की सरकार है इनके राज में अमीर को अमीर और गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है ताकि ये गरीब-गरीब रहें और अमीर अमीर रहें और बात रही यहां पर नगर विकास की जब विधायक लोगों का आवास ही सुरक्षित नहीं है, मेरा आवास हो या समता जी का आवास हो हमारे आवास में पानी टप-टप चू रहा है, न सही से दरवाजा है, न खिड़की है, जब माननीय विधायक लोगों का यह हाल है, तो आम जनता का क्या हाल होगा और आपका सिटी मैनेजर हो, चाहे ई0ओ0 हो, सब बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं और जो शहरी आवास विकास है आप लोग जान ही रहे हैं कि पूरा कमीशन खुलेआम तौर पर बंधा हुआ है जो जितना पहले देगा उसका ही काम होगा, इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करती हूं महोदय कि जो............

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब अपने क्षेत्र की बात हो तो आप बोल दीजिए ।

श्रीमती अनिता देवी: महोदय, मैं क्षेत्र की ही बात बोल रही हूं पहले भी मैं क्षेत्र पर ही बोल रही थी जो नगर पंचायत नोखा मुख्य शहर से काली मन्दिर पश्चिमी पट्टी तक काफी खराब है, चलने लायक नहीं है और उसमें अभी तक न ही कोई सही से नाली, ड्रेनेज का कोई उपाय नहीं हुआ है नगर पंचायत में बस स्टैंड का चार साल पहले ही शिलान्यास कर दिया गया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है और टियराबाल जब आजादी के 72 साल हो गए लेकिन आज भी उसे मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है आज भी सड़क कच्ची है और डोमा टोला में भीउसी तरह है, अब नासरीगंज में भी नगर पंचायत में ढेर सारी ऐसी सड़के हैं, जिनको अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है । महोदय इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): बहुत-बहुत धन्यवाद । अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार सिंह ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: सभापति महोदय, आज सदन में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई हमारे सुबोध भाई जी को मैं जानता हूं और वे हमको भी जानते हैं कि किसी जमाने में लेनिन को मानने वाले आज देवों में देव महादेव का नारा लगा रहे थे, बड़ा सकुन मिला कि किसी जमाने में लेनिन को मानने वाले आज भोले नाथ का नाम ले रहे हैं । सभापति महोदय, आज हम खड़े हुए हैं कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए और पक्ष-विपक्ष होते हैं और जो अच्छी बाते होती हैं उन्हें सरकार और सरकार के पदाधिकारी को अध्ययन

करना चाहिए हम कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म बिहार की धरती पर हुआ, भगवान बुद्ध की धरती पर पैदा हुए और मेरा दुर्भाग्य क्या है, ये आपको समझने की आवश्यकता है सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों आप तिरूपति जाते हो, आप सांई के दर्शन करने महाराष्ट्र जाते हों और आप भुवनेश्वर में दर्शन करने जाते हो, सारी जगह वहां की सरकारें वहां के नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था की गई है कि इस हिन्दुस्तान की धरती पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं और वह धरती है बोधगया, वह धरती है भगवान विष्णु की नगरी जहां लाखों लाख लोग आते हैं आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, आप प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी बनाओ, मगर हम तो उस सिटी से आते हैं जहां सत्यनारायण बाबू के पूवर्जों की आत्मा की शांति भी वहीं मिलेगी गया की धरती पर, तो हम नगर विकास के मंत्री और नगर विकास के प्रधान सचिव को यह कहना चाहते हैं ऐसा गया ने कौन सा गुनाह किया ? गया ने कौन सा गुनाह किया, जो गया को इसकी धूरी से बहा दिया आप ईमानदारी से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हम किसी पर आलोचना नहीं करना चाहते, हम गया शहर के वासी हैं उस नाते आप बुद्धिजीवी हो, आप सरकार के लोग हैं हम आपसे पूछना चाहते हैं ।

क्रमशः

टर्न-20/ मुकुल-सत्येन्द्र/06-03-2020

श्री अवधेश कुमार सिंह:(क्रमशः) हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बोध गया में विदेशी पर्यटक आते हैं और जब वहां बोध गया से राजगृह जाते हैं तो क्या आपके लिए इमेज लेकर जाते हैं। ये दायित्व किसका है, पिछले 15 साल या ये 15 साल, यह फैसला आप सभा गृह में बैठे हैं आप सोचिये कि आपने गया को किस अंदाज में लिया । आज पूरे चीज को मैं देखा हूँ, इसमें गया के बारे में क्या लिखा गया है । हमको सिर्फ माननीय मंत्री जी बता दें । हम यह जानना चाहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया जो गया में पैदा लिया । अरे हम तो भाग्यशाली हैं कि हम भगवान विष्णु की नगरी जहां चरण है, जहां पर पूरा देश उनका दर्शन करता है। हम लॉर्ड बुद्धा जिससे ज्ञान की प्राप्ति श्रवण कुमार जी को मिलता है, हमारे बुद्धा के नाम पर आप ज्ञान प्राप्त करते हो और बुद्धिज्म को आप नकारते हो, हम कौन सा ऐसा गुनाह कर रहे हैं, यही गुनाह है मेरा कि हम विपक्ष के विधायक हैं। हम जानना चाहते हैं कि नगर-निगम, गया के द्वारा कौन सी ऐसी कार्रवाई की गयी कि हमारे विदेशी पर्यटक हमारे देश के जो तीर्थयात्री आते हैं वे गया से एक अच्छा इमेज लेकर जायें और बिहार सरकार को कहें कि क्या सरकार है। सुबोध बाबू, आप बताओ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज गया नगर-निगम के द्वारा बुडको से आपने मंगाया है

डी.पी.आर. विधायक का काम है, चाहे सत्तापक्ष के विधायक हों, विपक्ष के विधायक हों। सत्तापक्ष सरकार की उपलब्धियां गिनाती हैं और अंतिम में जैसे मोर जंगल कानन में, जंगल में जैसे नाचता है सुबोध बाबू आप नाचे पूरा और अंतिम में अपना पैर देखकर आप मुरझा जाते हैं और बाद में कहने लगते हैं ये नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। अरे भाई, जो ईमानदारी की बात है सत्यता बताई जाती है। आज हम कहते हैं कि जो सलेमपुर पईन की बात की गई, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सभागार में जिसमें प्रधान-सचिव भी बैठे थे, कहें कि फल्गू नदी में नाली का जल नहीं गिरेगा। एक तरफ नमामि गंगे में प्रधानमंत्री बोलते हैं, उस पर आप कागज पर लिख रहे हैं और एक तरफ बिहार के सूबे का किंग-राजा बोलता है और उसके बाद भी कोई जिक्र नहीं करते हो, वाह ! क्या नगर-निगम है, ये भाजपा निगम है या आपका निगम है, आप फैसला करो कि एन.डी.ए. की सरकार में हैं, प्रधानमंत्री के नमामि गंगे लिख रहे हैं और फल्गू नदी के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा बाजाब्ता लोगों के बीच में कि फल्गू नदी में नाली का पानी नहीं गिरेगा और हमने मानपुर को 47 वार्ड से 53 वार्ड का डी.पी.आर. बनाकर दिया, नगर-निगम के द्वारा पास किया गया, बुडको के द्वारा पास किया गया। अभी नगर-निगम दोबारा पत्र दिया, हम प्रधान सचिव से भी व्यक्तिगत रूप से मिले हैं बिहार के सूबे मालिक मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया। मुख्यमंत्री जी का दो-दो पत्र मेरे हाथ में है और बिहार के मुख्य-सचिव से भी हमने बात की, प्रधान-सचिव को मुख्य-सचिव ने कहा- कहां अटका हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है यह हम जानना चाहते हैं। अगर वह नाला का निर्माण कर दीजिए, उस नाले पर रोड बन जाए आशियाना नगर में आप नाला बनायें, बधाई हो, यह नगर विकास की उपलब्धि है, बिहार के मुख्यमंत्री की उपलब्धि है मगर जहां नहीं बनाये हैं वहां तो लोग कहेंगे । हम देखे हैं पटना को, हमने भी अपनी बहन की वेदना को देखा है जब पटना डूबा था, अरुण सिंहा जब बोल रहे थे तो उस जमाने में हमने इनके शक्ल को देखा था, हमने देखा है हमको खुशी होती कि नगर विकास, अगर इसमें मोदी जी का जो शक्ल दिये हैं अगर वह हाफ पैंट वाला शक्ल इस पोस्टर में लगाते तो बड़ी प्रसन्नता होती। अतीत को पहचानो, तभी आगे आप बढ़ोगे । एक दूसरे के खिलाफ बोलने से और करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपसे आग्रह है हमने मंत्री जी से कहा मंत्री जी गये थे । एक नाले का इनसे शिलान्यास कराया था। लखीबाग का रोड आपने बना दिया और जो समाजवादियों का रोड जो श्रवण कुमार जी का रोड है जिस रोड में दस बार गये हैं, जनकपुर रोड की जर्जर हालत है, एक तरफ उपेन्द्र वर्मा जी को राजकीय सम्मान दे रहे हैं और उनके घर के आगे रोड नहीं बना रहे हैं ऐसा कौन सम्मान आप दे रहे हो, भाई आप हमको बतलायें, उस 50 साल में उस रोड को मैंने बनवाया नंद किशोर बाबू, लेकिन 15 साल में आप उसको नहीं बनवा पायें। दिया है महेश्वर जी, अजित शर्मा जी ने भी दिया

है और शैलेश जी भी जो हमारे छोटे भाई हैं इन्होंने भी दिया है। हम कहां इंकार कर रहे हैं लेकिन जो नहीं दिया है उसके लिए आपको उलाहना दे रहे हैं । आपको आज भी हम कह रहे हैं कि सरकार का काम है पक्ष को भी और विपक्ष को भी देखने का..

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: हमारे मुख्यमंत्री जी बार-बार कहते हैं । पता नहीं है कि अगली बार आप विपक्ष में रहने वाले हैं या पक्ष में रहने वाले हैं । किसके टिकट पर चुनाव लड़ियेगा, इधर वाले के न, कि उधर वाले के टिकट पर, यही नहीं अभी आपका तय है..

श्री अवधेश कुमार सिंह: नंद किशोर बाबू, समय होत बलवान, वही अर्जून वही बाण । महागठबंधन को बिहार में सत्ता मिली थी नीतीश कुमार के हाथ में जनता ने बागडोर दिया था लेकिन भाजपा आर0एस0एस0 के लोग, सुबोध बाबू जैसे लोग बिक गये और सरकार आपकी बन गयी । हम सत्ता में होते हुए विपक्ष में आ गये और आप कहां ? मैं नंद किशोर बाबू, वर्ष 1980 से कांग्रेस का विधायक हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ूंगा, चाहे कांग्रेस का जो हाल हो, कांग्रेस का झंडा उठाकर रहेंगे, कभी भी आर0एस0एस0 और भाजपा के झंडे पर नहीं जायेंगे । हम कहना चाहते हैं सभापति महोदय, सुबोध बाबू आपने भी लगाया लेकिन आप पत्थर को पत्थर न समझकर, गुलाब की चमन में जाकर उन पत्थरों को भूलने का काम किया। सभापति महोदय, हमारे इलाके में हम चाहेंगे, नगर विकास विभाग के जो प्रधान सचिव हैं अच्छे हैं गरीब तबके के परिवार से आते हैं, उनसे आशा और उम्मीद है, जब आप नगर विकास में आये हैं तो गरीब की बात सुनेंगे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में नंद किशोर बाबू या अन्य जो नगर निगम के लोग हैं, वे ईमानदारी से अपने कलेजे पर हाथ रखकर बतलायें कि कोई गरीब का घर बना है क्या ? आप सिर्फ अपने कैडर के लोगों का घर बनाये हैं, भाजपा आर0एस0एस0 के लोगों का घर बनाये हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम लेते हैं । मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री नहीं कर सकते हैं चूंकि ये भाजपा के नेता हैं और सरकार में बैठे लोग हैं लेकिन पदाधिकारी किसी दल का नहीं होता है, मैं कहता हूँ कि आप 10 ही, पूरे राज्य के हर जिले में 10 से 20 घर की जांच करा लें, आप उसमें क्या पाओगे कि वह गरीब का घर बना या सम्मान पाने वाले लोगों का घर बना। अगर फैसला आपको करना है हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज हमारे यहां बस स्टैंड की चर्चा हुई। बस स्टैंड आप बना रहे हैं, कब चालू कीजियेगा, वर्ष 2020 के बाद या वर्ष 2020 में, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, दो मिनट सभापति महोदय और हम आपसे आग्रह करेंगे कि गया को सौतेलापन की नजर से न देखें । मुजफ्फरपुर स्वयं मंत्री जी देख रहे हैं, नालंदा माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, पटना को बिहार के उपमुख्यमंत्री जी और हमारे लोक निर्माण मंत्री जी देख रहे हैं मगर गया को देखने के लिए जो हमारे प्रेम कुमार जी हैं जिनको ये लोग दोनों मिलकर दाब कर रखते हैं इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि

गया को नगर विकास विभाग स्वयं देखे। गया की धरती भगवान बुद्ध जहां से बिहार सरकार को..

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: सभापति महोदय, जब ये बिहार सरकार में मंत्री थे तब इनको कौन दाब कर रखा था उसकी भी चर्चा इनको करनी चाहिए।

श्री अवधेश कुमार सिंह: जब हम बिहार सरकार में मंत्री थे तो हमें कोई दाब कर नहीं रख सकता था चूंकि मेरे बगल में श्रवण कुमार जी बैठते थे और मैं जानता था कि श्रवण कुमार कितने ताकतवर आदमी हैं।

..क्रमश:..

टर्न-21/मधुप-हेमंत/06.03.2020

...क्रमश:..

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि गया नगर निगम में बहुत-सी कमियां हैं, आज समय कम है, एक-आध मिनट समय दे दीजिये ।

महोदय, हम आग्रह करेंगे कि जो बोधगया से राजगीर विदेशी जाते हैं, बड़ा कष्ट है इसलिए सलेमपुर पईन जो ड्रेनेज के ऊपर नाला है उसको बनाने की कार्रवाई करें। माननीय मंत्री जिस रोड को देखकर आये हैं उस जमाने में, हम तो 15 साल - 15 साल के बीच में फंस जाते हैं, लेकिन हम जिस जमाने में मंत्री थे हम भी 1983 में मंत्री थे माननीय सभापति महोदय, हम लोग जिस सड़क को देखते थे और कमिट करते थे जनता से, उसको बनाने का काम करते थे । इसलिए नगर विकास मंत्री जी, जनकपुर सड़क, जो समाजवादी सड़क है, श्रवण कुमार जी की सड़क है उस सड़क का निर्माण कराने का काम करें । इसके साथ ही हम सिर्फ...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब समाप्त करें ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : एक सेकेंड, महोदय । सिर्फ नगर विकास में हमारे अजीत बाबू ने बहुत बढ़िया दोहा लिखा है, उस गीत को मैंने थोड़ा सिविलाइज किया है, सुरेश बाबू ने जो किया है, उसको मैं बताना चाहता हूं नगर विकास के लोगों को और सत्ता पक्ष के लोगों को कि- कश्ती चलाने वाले पतवार को ही पटना की गलियों-नलियों में डुबा दिया और सुशासन बाबू के चेहरे पर कालिख पुतवा दिया, कालिख पुतवा दिया । धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अब निर्दलीय माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी जी ।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, नगर विकास विभाग पर प्रस्तुत बजट पर जो बोलने के लिए मुझे समय दिया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं । बजट पर लाये गये कटौती प्रस्ताव का मैं विरोध करती हूं ।

महोदय, यह जो बजट है बहुत ही प्रशंसनीय है और सराहनीय है । वर्ष 2020-21 में नगर विकास एवं आवास विभाग की स्कीम मद में 3,418 करोड़ रु0 तथा स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय 3,795 करोड़ रु0 यानी कुल प्राक्कलन 7,213 करोड़ रु0 लगभग है । इसके माध्यम से शहरों का बहुत ही विकास हुआ है । हमारे एक जन-प्रतिनिधि बोल रहे थे, निश्चित रूप से बिहार के शहरों की तस्वीर बदली है, चाहे वह पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, बिहारशरीफ हो, हाजीपुर हो, दरभंगा हो । महोदय, बुडको द्वारा वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 6,145 करोड़ रु0, अमृत मिशन अंतर्गत 2,657 करोड़ रु0, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत 1,122 करोड़ रु0 एवं राज्य योजना अंतर्गत 762 करोड़ रु0 यानी कुल 10,687 करोड़ रु0 की विभिन्न योजनाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है। महोदय, मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना नगर विकास द्वारा चलायी जा रही है। इस योजना के तहत शहर की गली-गली में नाली और सड़क का प्रावधान किया गया है । इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर को पक्की सड़क और नाला से जोड़ा जाना है । महोदय, आज राज्य के किसी शहर में चले जाइये, आपको कोई भी गली कच्ची शायद नहीं मिलेगी । महोदय, मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज में घाट संबंधी योजनाओं को दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। महोदय, इस समय मैं एक सुझाव के तौर पर आपको बतलाना चाहती हूं कि सात निश्चय के तहत जो मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना चल रही है या ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना चल रही है, दोनों में जलमीनार से जलापूर्ति की व्यवस्था करें ।

साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि विभागीय अधिकारी शहरी क्षेत्रों में देखते रहते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर टूटे नाले या फटे पाइप से शहरों में लाखों लीटर पानी बर्बाद होता रहता है । हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का सपना और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का सपना है कि जल संचय और जल जीवन हरियाली का ओर वे काफी सचेत हैं और उसके लिए काफी काम करते हैं । महोदय, लेकिन जो छोटे शहर पटना के बाद, जैसे मुजफ्फरपुर है उसकी तस्वीर को और भी बदलने की जरूरत है ।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या बताना चाहती हूं कि जीरो माईल चौक बोचहा में पड़ता है, वहां बाजार समिति के काफी कारोबारी आते हैं, वहां जल के जमाव की समस्या काफी रहती है और नाला की भी समस्या है । हमारे क्षेत्र में सात पंचायत जीरो माईल में पड़ता है वहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

इसीलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे ।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं अपनी बोचहा की महान जनता की तरफ से आपको साधुवाद देती हूं और सभी माननीय सदस्यों को सहृदय धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देती हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । बहुत-बहुत आभार ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी । आपका समय घट गया है ।

श्री कुमार सर्वजीत : कोई बात नहीं है, महोदय ।

सभापति महोदय, हम नगर विकास एवं आवास विभाग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हैं । खड़े क्यों हैं सभापति महोदय ? 72 अरब के बाद भी अगर बिहार को चलाने वाले मुखिया हाफ पैंट पहन कर अपनी जान बचाते हैं तो मुझे लगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के पक्ष में कटौती प्रस्ताव लाना चाहिये । इतने पैसे के बाद भी अगर बिहार का मुखिया डूब जाय तो जनता का क्या होगा, यह समझ से परे है, सभापति महोदय ।

सभापति महोदय, चूंकि समय कम है, ज्यादा क्षेत्र के बारे में ही हम बोलना चाहते हैं । सभापति महोदय, अभी हमारे एक सदस्य ने बोधगया के बारे में बात रखी थी, भगवान बुद्ध की धरती और विष्णु की धरती है और जो मंत्री हैं, ये हिन्दुत्व का नारा देने वाले लोग हैं । हिन्दुत्व का नारा देने वाले लोग पिंडदान करने के लिए कहाॅं जाते हैं, गया में जाते हैं । नारा बाहर में क्या लगाते हैं कि हम हिन्दू हैं और स्मार्ट सिटी की जब बात आती है तो हिन्दुत्व का नारा इनका कहाॅं चला जाता है ? मैं समझता हूं कि मंत्री जी अपने भाषण में यह बतायेंगे कि बिहार के इतने बड़े और प्रसिद्ध स्थल, राजगीर, बोधगया, जहाॅं से मुख्यमंत्री आते हैं, हमको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के जो भी माननीय मंत्री हैं, वे साजिश रचते हैं । आप देखे होंगे कि समय-समय पर, हर दो-चार महीने पर माननीय मुख्यमंत्री गया का, बोधगया का दौरा करते हैं और पिंडदान करने के लिए लाखो-करोड़ो लोग वहाॅं पर आते हैं, उनको इन्होंने स्मार्ट सिटी में नहीं रखा ।

महोदय, हमारे यहाॅं नगर पंचायत थी, रैन्की कम्पनी को काम मिला, संजय सरावगी जी नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि आरोप नहीं लगा सकते हैं, इसी सदन में हमने प्रश्न उठाया था और पुनः यह प्रश्न है आपके विभाग को, हमने प्रश्न में दिया है, 98 करोड़ का सिवरेज का काम मिला, माननीय मुख्यमंत्री गया में समीक्षा बैठक

कर रहे थे, हमने कहा कि 98 करोड़ रुपया रैन्की कम्पनी के द्वारा लूट लिया गया है । तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव जो इनके थे, उनको हमारे साथ बोधगया में जॉंच के लिए भेजा और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर उन्होंने पुनः 58 लाख रुपया एक मन्दिर की सड़क थी, उसके लिए दिया । जॉंच करानी चाहिए, यह जनता का पैसा है, 98 करोड़ रुपया रैन्की कम्पनी लेकर चली गयी ।

उसके बाद महोदय, यहॉं एक पानी का काम कर रहा है, जो हमलोग हर घर नल का जल पहुॅंचाते हैं, वह कम्पनी है - जिंदल ।

...क्रमशः..

टर्न-22/आजाद/आजाद:अंजली/06.03.2020

..... क्रमशः .....

श्री कुमार सर्वजीत : जिंदल का भी हमने सवाल उठाया था, जिंदल कम्पनी जो है हर घर-नल-जल पानी लगा रही है और उसमें हमने यह भी कहा, जब हमने प्रश्न किया और जवाब आया सभापति महोदय, मंत्री जी ने कहा कि हमने 5 हजार घरों को पानी पहुॅंचा दिया, जबकि 7 हजार घरों को पानी पहुंचाना था । यही आंकड़ा जब हमने नगर पंचायत से मांगा तो कहा कि पूरी की पूरी सिस्टम फेल है, बोरिंग इनकी नहीं चलती है, इसलिए जो है जिंदल कम्पनी का काम पूर्ण रूप से फेल्योर हो गया है और इस सदन में जब हमलोग बोलते हैं तो ये कहते हैं कि आप आरोप नहीं लगा सकते हैं । आरोप की जॉंच हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधान सचिव को भेजा कि आप इसकी जॉंच कर लीजिए, जॉंच करनी चाहिए । पटना में हमलोग जब हालात देखे, हमलोगों के घर में एक सामान नहीं बचा और पता नहीं इनको कौन इंजीनियर डिजाइन करते हैं । सभापति महोदय, हमलोगों के अरूण बाबू अभी नहीं हैं, ये अभी बोल रहे थे, हमलोग जिस कॉलोनी में रहते हैं, अरूण बाबू वहां के एम0एल0ए0 हैं । पी0सी0सी0 इनका विभाग सड़क बनाता है और सड़क बनाने के बाद जे0सी0बी0 मशीन लगाकर के बीच की सड़क को उखाड़ता है और उसके बाद उसमें सिवरेज बनाता है । कौन ऐसा इंजीनियर है, जो पी0सी0सी0 सड़क को जे0सी0बी0 मशीन लगाकर के बीच से उसको तोड़ता है और बीच से तोड़ने के बाद अगल-बगल पी0सी0सी0 जो पूरी चौड़ी सड़क है, वह पूरी सड़क को नहीं बनाता, वो सिर्फ बीच की सड़क को बनाता है । यह जाहिर है कि इनके पदाधिकारी या इनके जो भी लोग

हैं, माननीय मंत्री जी भी इसपर ध्यान नहीं देते हैं । आप जाकर के देखिए कि कॉलोनियों की क्या हालात है, बीच से मिट्टी उखाड़ लिया और सड़क उखड़ गई, मिट्टी उखड़ गई और दोनों साईड में आपका जितना मिट्टी बचा हुआ था, वह सब सड़क पर आ गया । सड़क चलने लायक हालात नहीं है । सभापति महोदय, पुनः जब बारिश आयेगा तो फिर पटना डूबेगा, हमको यह पूरा विश्वास है । अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है बोधगया, मुझे दुःख होता है कि आपके प्रधान सचिव इतने विद्वान जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वे भी नहीं सोचते हैं कि अगर बोधगया में फल्गू नदी का पानी उफान मारेगा तो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात मंदिर है वहां पर और मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ होती है कि बोधगया पर्यटक स्थल में एक भी ऐसा नाला का निर्माण नहीं हुआ है, जहां पर हम उसके नाले को पूरे शहर के पानी को निकाल सके । यह दुर्भाग्य है सरकार का कि आपके पास राजगीर है, वैशाली है, बोधगया है, बड़े पैमाने पर आपको यह राजस्व का फायदा पहुँचाता है । माननीय मुख्यमंत्री वहां पर गये, वहां पर बम-ब्लास्ट हो गया, ट्रैफिक प्लान आयी । हम पत्र लिखते-लिखते थक गये कि ऐसे 81 होटल हैं, जिनके पास कच्ची सड़क है, चलने के लिए टूरिस्टों को जगह नहीं है, जिला पदाधिकारी ने कम से कम 10 बार आपके विभाग को चिट्ठी लिखा कि महारानी रोड से कालचक्र मैदान जहां पर दलाईलामा पूजा करते थे, आप कम से कम उस सड़क को बना दीजिए और आपका जवाब आया, अभी हमने प्रश्न किया था, आपने कहा है कि पैसा उपलब्धतता नहीं है । भाई पैसा की उपलब्धतता नहीं है तो आपसे जितना पैसा मांगा है, उससे एक लाख गुना आपके बी0जे0पी0 के पार्टी फंड में पैसा पड़ा हुआ है, उसको ही लगा दीजिए । इतना पैसा क्या कीजियेगा आप, नवीन बाबू हैं, हमलोगों के साथ पढ़े हैं । नवीन बाबू, आपने गरीबों का इतना पैसा पार्टी फंड में रखे हैं, आप क्या कीजियेगा । मेरा कहना है, हम पर आरोप लगाते हैं सभापति महोदय कि आपने 15 साल में क्या किया, 15 साल लूटे हम और सारा पैसा चला गया भाजपा के पार्टी फंड में तो भाई कौन लूटा, हम लूटे ? हमारी पार्टी फंड की आप जॉच कर लीजिए कि हमारे पास कितना पैसा है ? आप सुन लीजिए और 15 साल में नवीन बाबू ....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सर्वजीत बाबू, आप इधर बोलिए, आपको वे लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हमने सीखा है, हमारे पिता जी इसी सदन में नन्दकिशोर जी के साथ, सभी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ एम0एल0ए0 रहे 1977 से । जंगलराज हमको कहते हैं और जो हमने दृश्य देखा, इस उम्र में नन्दकिशोर जी बांह चढ़ाकर के खड़े हो गये, हमको इतनी तकलीफ हुई, आप इस देश को, आप बिहार

के लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं ? आप हमारे जैसे नौजवानों को क्या बताना चाहते हैं और जंगल राज की उपाधि हमको देते हैं और आप बांह चढ़ाते हैं, जंगल राज हमारे बारे में कहते हैं तो आपकी ये गलत बयानबाजी नहीं है, जो सत्य है। उसको बोलना कोई अपराध नहीं है और आपको तो माननीय मंत्री जी काम से कोई मतलब है नहीं, हम पहली बार ऐसा मंत्री देखे टप-टप-टप, बिना वजह अरे कुछ गरिमा होता है ना मंत्रिमंडल का, मंत्रियों का उस गरिमा का पालन करें । हम लोग सीखते हैं गरिमा का पालन करना, श्याम रजक जी हैं न, आपने श्याम रजक जी को कभी देखा है बोलते, राणा रणधीर जी को देखा है कभी बोलते, सीखिए । मैं कहता हूं कि संस्कार कोई ऊपर से लेकर नहीं आता, विजय बाबू संस्कार आपको इसी सदन में सीखना पड़ेगा ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य, आप अपनी काम की बात बोलिए, ये लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय, हम पी0एच0ई0डी की बात करते हैं । हमारे यहां जो गया जिला है पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं । जिलाधिकारी महोदय ने गया जिला के सभी माननीय सदस्यों से कहा कि आप सुखाड़ में इतना भीषण जल संकट उत्पन्न हुआ है, 15-15 चापाकल लिखकर दे दिए, जिलाधिकारी कब लिखवाएं, अगले मई में । महोदय, वह कब आने वाला है फिर यह मई आने वाला है, मंत्री जी को बताना चाहिए कि आपके जिलाधिकारी महोदय की भी बात आपके मंत्रालय में नहीं चलती है क्या, फिर क्यों अनुशंसा ली आपने, अनुशंसा नहीं लेना चाहिए था, यहां पर आपके पक्ष के भी मंत्री बैठे हैं । हम लोग एम0एल0ए0 कोटा का महोदय लिखते हैं अगर भूमि विवाद में कोई योजना कैंसिल हो जाती है तो हम लोगों को एक से डेढ़ साल लगता है उस योजना को कैंसिल कराने में । माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और उसमें संशोधन करना चाहिए । शहर में है हमको एन0ओ0सी0 लेने के लिए जूता घिस जाता है, शहर में माननीय मंत्री जी अगर नहीं बना सकते हैं, हमारे पास पैसा है, एम0एल0ए0 फंड होता है, हम उससे भी बना सकते हैं, उसका भी एन0ओ0सी0 लेने के लिए वही हालात है । बोधगया में भी हमने देखा, इतनी बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल महोदय, 500-500 घर..

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सर्वजीत जी, अब समाप्त कीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : अंतिम है सर । 500 घर हमारा बंगलादेश मंदिर के बगल में नहर है, पांच सौ वहां पर हमारे डोम जाति के मेश्तर लोग बसे हुए हैं , आज तक उनको एक बित्ता

जमीन मुहैया नहीं कराया गया और जब नदी का पानी आता है उस नहर में, पूरा का पूरा पांच सौ घर सड़क पर अपने बच्चों को लेकर रहता है । इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि वह बोधगया अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, उसमें हमने जो बड़ा सिवरेज के बारे में कहा, आप उसकी जांच कराइए ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी । आपका 7 मिनट टाइम है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, मुझे बोलने का मौका दिए, इसके लिए आपको और मैं अपने नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को और अपने क्षेत्र की जनता मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की महान जनता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, मैं नगर विकास एवं आवास विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ इन सभी लोगों का जीवन कैसे खुशहाल हो, इसके लिए काम कर रहे हैं और सरकार के लिए जरूरी है कि अपने नागरिकों के लिए समस्या का समाधान कैसे करें और करना चाहिए और कर भी रहे हैं । महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के कुशल वित्त प्रबंधन से और माननीय मंत्री नगर विकास श्री सुरेश कुमार शर्मा जी के कुशलता से राज्य आर्थिक विकास में नगरों की आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं में महती भूमिका निभा रही है । महोदय, राज्य सरकार अपने संसाधनों से राज्य के नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत एवं निरंतर प्रयत्नशील है । महोदय, हमलोग सुनते थे कि दिल्ली में या अन्य बड़े शहरों में मेट्रों ट्रेन कैसे चलता है, उसको राज्य के लोग और खासकर के हमलोग भी पहले देखने के लिए, उस पर सफर करने के लिए तरसते थे, लेकिन आज हमारे राज्य के लोग आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री के प्रखर नेतृत्व और बढ़ता बिहार के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पटना में कुल 31.39 कि0मी0 लम्बाई के दो कॉरीडोर का चयन किया गया है । इस कार्य के लिए 13365 करोड़ 77 लाख रुपया की अनुमानित लागत से पटना मेट्रो रेल परियोजना की भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी, 2019 को मिल गया ।

...... क्रमशः .....

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : क्रमशः ...... जो कार्य का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा हो गया है और डी0एम0आर0सी0 द्वारा कार्य प्रारंभ कर ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण कर, मिट्टी की जॉच की जा रही है । मेट्रो ट्रेन चालू हो जाने से पटनावासी सहित राज्य के कोने-कोने से आने वाले व्यक्तियों को काफी सुविधाएँ मिल जाएगी और बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा । महोदय, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना से राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है । महोदय, शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना के तहत सभी परिवारों को शौचालय बनाने का व्यवस्था किया जा रहा है । महोदय, इतना ही नहीं जल-जीवन-हरियाली अभियान से राज्य में जल संरक्षण के दृष्टिकोण से पोखर तलाब की उड़ाही और कुओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण करने का निर्माण लिया गया है । महोदय, राज्य में शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न जल संकट की समस्याओं से निदान पाने के लिए जल संचय एवं वृक्षारोपण योजना चलाने का संकल्प लिया गया है । महोदय, राज्य आवास बोर्ड के आम नागरिकों को बेहतर एवं किफायती आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है एवं राज्य के कोई भी व्यक्ति अपने घर के बिना नहीं रह सके, इसकी चिंता हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे नेता सुरेश शर्मा जी कर रहे हैं । महोदय, राज्य की जनता न्याय के साथ विकास का पूरा-पूरा लाभ उठा रही है । आज हमारे वरिष्ठ सदस्य कुशवाहा जी बोल रहे थे, सड़क के बारे में । सड़क के बारे में कई अन्य सदस्य बोलते हैं सड़क की स्थिति तो बिहार का यह हो गया है कि हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले है, मुजफ्फरपुर से पटना आने में सुबह से शाम हो जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर से पटना डेढ़ घंटा से पौने दो घंटा में लोग चले आते हैं । महोदय, सड़क का ही जाल नहीं बिछा है, आप पटना देख लीजिए चाहे मुजफ्फरपुर देख लीजिए, चाहे किसी भी शहर में देख लीजिए पुल पुलिया का भरमार हो गया है । महोदय, लोग जहां कल्पना नहीं करते थे वहां पुल बन रहा है । मैं मुजफ्फरपुर की बात करना चाहता हूँ । मैं उस जिले से आता हूँ और मुजफ्फरपुर शहर से माननीय मंत्री विधायक भी रहे हैं । इनकी कल्पना रही है स्मार्ट सिटी की जब ये विधायक नहीं थे उस समय से मुजफ्फरपुर कैसे सुंदर बने इसकी कल्पना करते थे ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : अब आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : आज स्मार्ट सिटी वहां अपना रंग दिखा रहा है । महोदय, जगह-जगह पर लाइट लगाया गया है । मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि बिहार में राज्य सरकार द्वारा

303.34 करोड़ रूपये की लागत से शहर में अन्तर्राज्जीय बस टर्मिनल का निर्माण करवा रही है, यह सबसे बड़ी बात है । महोदय, लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूँ । आज राज्य की जनता अपने आप को न्याय के साथ विकास महसूस कर रही है और इसका परिणाम 2020 में जब बिहार में चुनाव होगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी और हमारे नेता जो सदन में बैठे हैं माननीय नन्द किशोर यादव जी के नेतृत्व में पुनः 200 से ज्यादा सीट बिहार की जनता जिताकर पुनः सदन में भेजने का काम करेगी ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, हम एक सुझाव देना चाहेंगे मुजफ्फरपुर सहित यह मामला है मेयर और डिप्टी मेयर का हम अनुरोध करेंगे विभाग से कि मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर, नगर परिषद् और नगर पंचायत का चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मेयर, उप मेयर का डायरेक्ट चुनाव जनता के द्वारा हो ताकि जो भ्रष्टाचार पनप रहा है वह भ्रष्टाचार खतम हो । हम इन्हीं बातों के साथ पुनः आपको एक बार धन्यवाद देते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, आज नगर विकास और आवास विभाग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । राज्य के आर्थिक विकास में नगर की आधारभूत संरचना एवं सेवाओं की महती भूमिका होती है । गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था और समेकित रूप से राज्य की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन का कारक बनती है । साथ ही स्वस्थ मानव संसाधन के विकास में अभिवृद्धि करती है । इसीलिए इस विकास का एक विशेष महत्व है सारी दुनिया में हम देखते हैं ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : 5 ही मिनट टाइम है आपका बाकी समय ले चुके हैं ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : छोड़ दीजिए, रहने दिया जाय, समय उनको दे दिया जाय ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : आप ही के दल के लोग लिये हैं । बोलिये 5 मिनट में ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : रहने दिया जाय सर, धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : 5 मिनट में बोलिये न, आप बोल लीजिए । आप शुरू कीजिए न, शुरू करने में क्या दिक्कत है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : इधर का भी 5 मिनट समय दे दीजिए ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : चलिये, आपको इधर से भी समय मिलेगा, नाराज मत होइये, बोलिये आप ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सभापति महोदय, नाराज की वजह सिर्फ समय कम मिलना नहीं है । नाराजगी की वजह यह है कि पिछले दस साल से मैं सदस्य हूँ और समस्तीपुर शहरी क्षेत्र से हूँ, जहां से जननायक कर्पूरी ठाकुर प्रतिनिधित्व करते थे । ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से कई विकास का कार्य करने का कई विभिन्न विभागों के सहयोग से काम करने का मौका मिला है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मैं लगातार प्रयास करता रहा और शहरी क्षेत्र में हम काम नहीं कर पा रहे हैं । जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं उसको किसी भी तरह का विकास का काम करने का प्रावधान इस सरकार ने नहीं रखा है । पहले मुख्यमंत्री शहरी विकास एक योजना हुआ करता था जिसमें माननीय विधान सभा के जो सदस्य हुआ करते थे । वे अनुशंसा करते थे एक अच्छी राशि होती थी कौन नाला बनना है, कौन सड़क बनना है । इस तरह का काम करते थे तो हमको बोलने के लिए होता था कि मेरा भी योगदान शहर के विकास में है । आज एक रूपये का एक फीट भी नाली या किसी तरह से आपने विधायकों को या सांसद को इस सरकार ने नहीं रखा है । यह बहुत दुख की बात है । लाखों जनता हमको वोट देकर जिताती है और हम वहां पर कोई काम नहीं कर पाते हैं और किन्हीं बातों को हम विभाग के सामने सदन में प्रश्न के माध्यम से, याचिका के माध्यम से, सचिव से मिलकर, मंत्री से मिलकर बातों को करते हैं तो उन बातों को भी उस तरह से नहीं लिया जाता है । सदन में अगर प्रमुखता से अपनी समस्याओं को उठाते हैं तो विभाग को काग्नीजेंस लेना चाहिए, टेलीफोन पर संपर्क करना चाहिए कि आपने जो मुद्दे उठाये मैंने उसे ग्रहण किया और पता किया, इतनी सच्चाई है इतनी गलत बात है । हम तमाम मुद्दों की जॉच कर रहे हैं, तमाम समस्याओं को दूर किया जायेगा । इसलिए बोलने में कुछ रूचि नहीं रह जाता है कि हम जो समस्या यहां पर रखते हैं उसको गंभीरता से विभाग लेता हो, करता हो इसीलिए बोलने में बहुत ज्यादा रूचि नहीं रहता है । हम अपने क्षेत्र की कुछ समस्या जैसे बताते हैं । सरकार लगातार बताती है कि हम ये कर रहे हैं, 7100 करोड़ रूपये का बजट आ जाता है, लेकिन जब काम देखने को मिलता है- पूरे विश्व में आप देखेंगे तो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, भारत में भी देखेंगे तो बड़े पैमाने पर शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस तुलनात्मक दृष्टिकोण से बिहार में शहरीकरण बढ़ने का काम नहीं हो रहा है । आज भी शहर में रहनेवाले लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि वह नर्क में रह रहे हैं, हर जगह गंदगी है, कूड़े का अंबार है, ड्रेनेज सिस्टम, सिवरेज सिस्टम आदि, एक बरसात होता है तो सब फेल हो जाता है । अभी लोग बता रहे थे कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ। मुझे लगता है कि यह एक सजा थी कि 15 साल से सत्ता आपको दिया गया और 15 साल से पूरे बिहार में किस तरह से शहरी जनता पानी में डूब रही

थी । आप उसका निदान नहीं कर सके इसलिए सजा के रूप में आप ही को डूबाने का प्रयास किया गया, चेताया गया कि आप देखो कि किस तरह की समस्या जल जमाव से पैदा हो सकती है और किस तरह से नारकीय जीवन जीना पड़ सकता है । ऐसा पटना में पहली बार भले हुआ हो लेकिन पूरे बिहार के तमाम शहरों में जाइयेगा एक घंटा की बारिश में लोग डूबने लगते हैं, लोगों के घरों में घुटने भर पानी आ जाता है । इसीलिए मैं अपने क्षेत्र की एक-दो समस्या प्रमुखता से रखना चाहता हूँ कि जे0सी0बी0 मशीन की आवश्यकता होती है, जे0सी0बी0 मशीन हमारे यहां नहीं है । जो बॉबकट मशीन आता है उसकी संख्या नहीं के बराबर है । एक नाला मैन होता है जिससे नाली की सफाई होती है वह एकदम एक की संख्या में है । अब एक लाख की आबादी में आप इस तरह से विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं । डंपिंग यार्ड होता है, डंपिंग यार्ड हमारे यहां नहीं है । विभाग कहता है कि आप सर्किल रेट पर खरीदिये और सर्किल रेट पर जमीन मिलना संभव ही नहीं है । उसी तरह से विभाग जो प्रस्ताव यहां से भेजता है जो बोर्ड द्वारा पारित करके भेजा जाता है । वह सालों साल यहां पड़ा रह जाता है, पता नहीं हमारे अवधेश बाबू बता रहे थे शायद सत्ताधारी दल के हमलोग सदस्य नहीं हैं इस वजह से हमलोगों के तमाम वहां- जबकि वह योजना हमलोग नहीं भेजते है, वह योजना तो बोर्ड वहां से भेजता है और बोर्ड ने वहां योजना बनाकर के भेजा कितने सालों से लंबित है ।

क्रमशः

टर्न-24/06-03-2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : हम बता देना चाहते हैं कि जैसे भोला टॉकिज से पंजाबी कॉलोनी का एक ताजपुर तक जाने वाली सड़क है जिसकी योजना लंबित है । तिरहुत ऐकेडमी काशीपुर बेलदारा की तरफ एक नाला है, वह लम्बे समय से लंबित है, मगरदही चौक से पी.एण्ड.टी कॉलोनी महादेव चौक जाता है, एक नाला वो बोर्ड ने यहाँ भेजा है वह लंबित है । हमारे इन्कम टैक्स से दरिया बेलार तक जाता है वह योजना लंबित है । इस तरह कई ऐसे गंभीर है, डिमान्ड जो हमारे यहां लंबे समय से लंबित है और हम देखते हैं कि साफ सफाई के मामले में हमारे घर के सामने एक-एक हफ्ता कचरा पड़ा रहता है । पंजाबी कॉलोनी में जिधर देखो उधर कचरा पड़ा रहता है, एक-एक सप्ताह पड़ा रहता है । ये तमाम समस्या मैंने विभाग के सामने रखी है। वरीय अधिकारी आते हैं समीक्षा करने के लिए और कहते हैं कि हम वहाँ भेजेंगे और हम पूरी समस्याओं का निदान करेंगे, लेकिन किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकल पाता है ।

फिर आज इस सर्वोच्च सदन में इस बात को बोल रहे हैं कि क्या कार्यवाही होती है, दूसरी तरफ हम बताना चाहते हैं कि नगर परिषद् ने या कोई भी जो प्रतिनिधि जीतते हैं बहुत कम भत्ता दिया जाता है, लगातार वो लोग प्रदर्शन करते हैं । हम लोगों ने भी आवेदन दिया है । 1500 रूपये में दिनभर वो नाला सफाई करवाते रहते हैं, शौचालय की सफाई करवाते रहते हैं । चाय का भी पैसा उनको नहीं मिलता है, कम-से-कम नगर परिषद् में जो जीतते हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि या नगर का प्रतिनिधि, उनको दस हजार रूपये मिलने चाहिए । कोई नहीं है, जो भी मुखिया है सरपंच है, समिति है, वार्ड मेम्बर है, पंच है एक सम्मानजनक उन लोगों को भत्ता मिलना चाहिए । राशि की समस्या ऐसी है कि अगर आप पटना जाइए या पूरे बिहार में आप कहीं भी पुल नहीं बना पा रहे हैं । लोग दो-दो घंटे, चार-चार घंटे शहर में फंसते हैं, हर शहर में पुल बनना चाहिए । हमारे समस्तीपुर शहर में आर.ओ.बी. रेल ओवर ब्रिज 15 साल में हमारे मंत्री नंद किशोर जी भी बैठे हुए हैं । 15 साल में एक पुल नहीं बन सका । आप समझ सकते हैं कि जनरली शहर में पुल क्या-क्या समस्या पैदा कर सकता है ? चाहे दरभंगा हो, डलची चराय हो, या समस्तीपुर जिसकी वजह से भोला टाकीज, गोमती है एक ही पुल है जिससे पूरे 10 दरभंगा, मधुबनी के लोग जाते हैं । एक पुल है वहाँ पर वैकल्पिक पुल बनना चाहिए, बड़ा पुल बनना चाहिए ताकि शहर में यातायात सुलभ हो सके । सफाई कर्मचारी जो 10 साल से वहां काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं उनको हटाने की घोषणा सरकार ने कर दी । वो गरीब दलित परिवार के लोग ज्यादातर होते हैं जो साफ-सफाई, नाली वैगरह-वैगरह का काम करते हैं । इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि उन गरीब लोगों के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है । दस साल से वो काम कर रहे हैं उनको रहने दिया जाए । यदि हमारे यहाँ इनका 10-20 योजना विभाग चला रहा है । लेकिन समस्तीपुर में शायद इनका कोई कार्य समाप्त नहीं हो रहा है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : एक मिनट में समाप्त करिये ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : इसलिए हम चाहेंगे कि इस पर भी काम किया जाए । हम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से भी कहना चाहेंगे कि आपका बड़े पैमाने पर काम चल रहा है । लेकिन टेक्निकल स्टॉफ की आपके यहां भारी कमी है । कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे टेक्निकल लोगों को आप बहाल करने की कोशिश करें । मिस्त्री वैगरह को बहाल करने की कोशिश की जाए । पंचायत स्तर पर कोई ऑर्थोराइज स्तर पर दिया जाए तो देख सके । योजना और विकास विभाग से संबंधित जो मामले हैं, हम लोग उसकी अनुशंसा करते हैं । 6-6 महीने तक पेंडिंग रहता हैं । 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए । क्योंकि 500-700 फीट बनाने में उसका कितना इस्टीमेट हुआ है

। इसलिए 15 दिन के अंदर योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए । एक सुझाव मेरा योजना विभाग से है कि सी.सी.टी.वी कैमरा जो शहर में या तमाम मुख्यालयों पर मुख्य चौराहों पर आवश्यक होता है । जो विभाग सरकार या गृह विभाग करना चाहती है हम चाहते हैं कि एम.एल.ए को या विधान पार्षद् को अधिगृहित कर दिया जाए । योजना में शामिल कर दिया जाए तो हम लोग तमाम विधि व्यवस्था के लिए अपराध को नियंत्रण करने के लिए यह बहुत आवश्यक होता है इसलिए हम चाहेंगे कि योजना विकास विभाग में इस बार की अनुशंसा में हम लोग सी.सी.टी.वी कैमरों में लिख सकें । इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सरकार जो 15 साल से खत्म नहीं कर सकी है और आने वाले कुछ दिनों में कर पाती है या नहीं कर पाती है इससे हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं । हर वक्त अपनी समस्याओं को रखना मेरी जिम्मेदारी है, निदान करना इसकी जिम्मेदारी है इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी, 2 मिनट समय रहेगा आपका ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि आज गागर में सागर भरना ही पड़ेगा । महोदय, आज कई वर्षों के पूर्व जो सभी निकाय हैं उसको माना जाता था वो सिर्फ साफ-सफाई करने का एक बॉडी है, लेकिन हमारी सरकार ने शहरी विकास के विभिन्न जो डॉइमेंसन है उसमें काम करने का प्रयास किया है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शहरी, गली योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना हर घर में जो हमारे गरीब भाई है, उनको भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से 12 हजार जो उसके शौचालय के निर्माण में अनुदान देना था इस तरह के कई सवाल जो शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों के थे उसको हमारी सरकार ने दूर करने का प्रयास किया । महोदय मैं सिर्फ 3-4 चीजें जो सुझाव के तौर पर नगर विकास विभाग के लिए मुझे जो आवश्यक लगा है मैं उसको रखना चाहता हूँ कि कटिहार, आरा, मधुपुरा ऐसे हमारे नगर-निगम क्षेत्र हैं जहाँ जल-जमाव के कारण एक बड़ी समस्या वर्षा काल में आ रही है और उसके कारण शहर की नारकीय स्थिति जो बन जाती है । जो स्ट्रॉंग वाटर ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसको नगर विकास विभाग प्रमुखता से राशि दे और लागू करें जिससे कि शहरों की समस्या का समाधान हो सके । महोदय, मैं दो-तीन और चीजें आपके सामने कहना चाहता हूँ कि नगर-निगम में जो सफाईकर्मी हैं उसके लिए एक स्पष्ट सेवा नियमावली बनना चाहिए जिससे कि उनका नियमतिकरण और उनकी जो सुविधाएँ हैं, वे बरकरार रहे, खासकर के मेरे कटिहार नगर-निगम क्षेत्र में वर्षा के समय में जल की जो समस्या है उसको तात्कालिक क्योंकि स्ट्रॉंग वाटर

ड्रेनेंज सिस्टम में काफी एक लम्बा काल लगेगा । लेकिन तत्काल अभी से ही जो हमारा महात्मा गांधी पथ है और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पथ है उसमें जो जल जमाव है उसको दूर करने का निश्चित रूप से प्रयास करें और अंत में....

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : समाप्त कीजिए, आपका इतना ही समय है, संजय सरावगी । जवाब होगा आप ही की सरकार का । बोलने दीजिये...

श्री तारकिशोर प्रसाद : अंत में सिर्फ हमारे नेता है उन्होंने बजट भाषण में एक शेर कहा था उसको कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि-

''जिन्दगी अक्सर उन्हीं को चुनौती देती है,
जिनकी औकात होती है कुछ करने की ।''

तो हमारी सरकार में कुछ करने की ताकत है इसलिए विपक्षी दल भी अपेक्षा करते हैं नहीं तो लगातार इन्होंने भी 15 साल राज किया और हमारी सरकार ने भी 15 साल राज किया लेकिन इतने विभिन्न डिफरेन्ट डॉयमैन्सन में हमारी सरकार ने नगर के विकास में काम किया वह अपने आप में ऐतिहासिक है, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में और माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो विपक्ष के मित्र बता रहे थे । अध्यक्ष महोदय, मैं उनके लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ-

''लोग टूट जाते हैं, घर बनाने में
तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ, जलाने में ।''

ये 15 साल तक पूरी बस्तियाँ जलायें, बिहार को लूटे और नगर विकास विभाग में एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था । अध्यक्ष महोदय, मैं भी विधायक के पहले पार्षद् नगर निगम का हुआ करता था । साल में एक लाख का काम नहीं हुआ करता था हमारे वार्ड में अध्यक्ष महोदय और आज वे बोल रहे थे कि एक भी काम नहीं हुआ । 10,780 केवल गली-नली जो है अभी 4 साल में कम्पलीट हुई है । अध्यक्ष महोदय, हम स्मार्ट सिटी बना रहे है, हम ड्रेनेज और सीवरेज की बात कर रहे हैं, हम कूड़ा विस्तारण के साथ-साथ, कूड़ा से जैविक खाद बना रहे हैं । हम नगर को आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं । यह हमारा काम हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की ओर आता हूँ और ज्यादा बात नहीं करते हुए समय का अभाव है हमारे यहाँ हराई डीगी गंगा सागर बहुत लम्बा तालाब है उसका डी.पी.आर. बना हुआ है सौंद्र्यीकरण के लिए उसको स्वीकृत किया जाए । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ अमृत योजना से पेयजल आपूर्ति का, पेयजल का काम चल रहा है । अभी तक 110 कि.मी. पाईप लाइन का

डी.पी.आर. बन के आया हुआ है पेयजल का वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है । सरकार कहती है कि जून में हम घर-घर तक पानी पहुँचा देंगे । तो वो 110 कि.मी. पाईप लाइन का डी.पी.आर बनकर आया हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कर दें । 6 महत्वपूर्ण नालों के लिए मैंने विभाग को लिखा हुआ है । जो आगे आने वाले समय में जल-जमाव के अनुदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे । उन 6 नालों का निर्माण हो जाय, यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ । हमारे नगर-निगम क्षेत्र में एक सम्प हाउस है वो बंद है वो सम्प हाउस कम से कम बन जाए । यह मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ । एक अंतिम बात अध्यक्ष महोदय, नगर निकायों में इतनी सारी राशि पड़ी है, अत: मंत्री जी से आग्रह होगा कि पदाधिकारियों को मुख्यालय से जरा नीचे भेजिये । मैं केवल उदाहरण स्वरूप अपने दरभंगा नगर निगम के बारे में कहना चाहता हूँ । मुख्यमंत्री नली, गली योजना का 20 करोड़ रुपया रखा हुआ है।

क्रमशः

टर्न-25/कृष्ण:संगीता/06.03.2020

श्री संजय सरावगी (क्रमश:) : जो कूड़ा निस्तारण का है, उसका 17-18 करोड़ रूपया दरभंगा नगर निगम में रखा हुआ है । अधिकाशं नगर निकायों में राशि पड़ी हुई है, खर्च नहीं हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यालय के पदाधिकारियों को नगर निकायों में भेजें, वहां राशि खर्च नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, यह चिंता करें ।

अंत में महोदय, महापौर, नगर परिषद अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव आम जनता से होना चाहिए और यह सरकार की घोषणा भी है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह भी करूंगा कि आज सदन में घोषणा करे कि यह जो खेल चल रहा है पार्षदों की खरीद बिक्री का, उस पर लगाम लगावें और महापौर और नगर परिषद के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष कर चुनाव डायरेक्ट आम जनता के वोट से करावें । यही मैं आग्रह ओर निवेदन करते हुये, मुझे आपने बोलने का समय दिया और अंतिम बात मुख्यमंत्री नाली गली योजना और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में नगर निकाय में जो काम हो रहे हैं पैसा केन्द्र का और पत्थर पर नाम माननीय विधायकों का नहीं लिखा जाता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी माननीय विधायक का नाम जरूर हो, यह मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, माननीय

उप मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में नगरों का चहुमुखी विकास हो रहा है, पहले सिनेमा का रीन्यूवल कराने का काम नगर विकास हुआ करता था, नगर विकास मंत्री का 15 साल में केवल सिनेमा हॉल का रीन्यूवल कराते थे ये लोग और आज हमलोग विकास कर रहे हैं, इनलोगों को सुहा नहीं रहा है, कटौती प्रस्ताव लाते हैं । एक तरफ कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ कटौती प्रस्ताव लाते हैं । इनको तो बढ़ोत्तरी प्रस्ताव लाना चाहिए । पूरे बिहार को 15 साल में इनलोगों ने बेचने का काम किया । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद, जय बिहार ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व उत्तम प्रबंधन के कारण राज्य की आर्थिक विकास में शहर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । राज्य सरकार अपने संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के नगरीय समस्याओं के निराकरण के लिये सतत एवं निरंतर प्रयत्नशील हैं । बिहार का शहरीकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। विगत वर्षों में शहरों को सुन्दर बनाने में तथा नागरिकों को नागरिक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा कई बहुयामी कदम उठाये गये हैं । नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत कार्यरत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों के सुंदर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा विशेष प्रयत्न किया जा रहा है । राज्य सरकार के महत्वकांक्षी एवं आम लोगों की सुविधा के आलोक में संचालित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में से 3 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है:-

1. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना : राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित प्रत्येक परिवार को शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना लागू है। इस योजनान्तर्गत स्थानीय नगर निकाय, बुडको एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर निकायों में प्रत्येक परिवार को नि:शुल्क नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना : राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित परिवारों को पक्की नाली-गली से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री शहरी नाली

गली पक्कीकरण निश्चय योजना लागू है । योजना ओं के प्रथम चरण में कच्ची नाली, गलियों के पक्कीकरण की योजना को लिया जा रहा है तथा द्वितीय चरण में पूर्व से निर्मित नाली गली जीर्णोद्धार की योजना लिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : इसके तहत नगर निकाय क्षेत्र में स्थिति सभी शौचालय विहीन घरों का शौचालय की व्यवस्था के लिये योजना की मंजूरी प्रदान की गयी है एवं यह योजना राज्य सरकार के शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय में भी शामिल है ।
4. जल संरक्षण : राज्य के घटते भू-जल स्तर एवं जल संकट को ध्यान में रखते हुये नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तत्कालीन एवं दीर्घकालीन योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । तत्कालीन समाधान हेतु सभी नगर निगम को प्रत्येक दो वार्ड पर एक-एक स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर वैसे वार्ड जहां ट्यूब वेल के रूप में वाटर सोर्स उपलब्ध है परन्तु पाईप लाईन नहीं बिछाया जा चुका है तो वैसे वार्डों में तत्काल सामुदायिक स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ।
5. दीर्घकालीन समाधान हेतु कृत कार्रवाई : राज्य के सभी शहरी निकायों में तालाब, पोखरों की उड़ाही एवं वृक्षारोपण कार्य योजना, ग्राउंड वाटर रीचार्ज हेतु वाटर सोर्सेज के नजदीक सोख्ता का निर्माण, पार्क, खेल का मैदान एवं अन्य खुले सार्वजनिक स्थानों पर ग्राउंड वाटर रीचार्ज हेतु सोख्ता निर्माण रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने का बिहार बिल्डिंग बायलॉज में प्रावधान किया गया है । राज्य योजना के अंतर्गत वाटर आऊट फॉल नाला निर्माण राज्य के शहरी क्षेत्र में छोटे नालियों का निर्माण, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना से हो रहा है । परन्तु आऊट फॉल ड्रेन का निर्माण नगर निकायों में आधारभूत संचरना के अभाव में निश्चय योजना से पूर्ण नहीं हो पा रहा है । फलस्वरूप नगर निकायों में आऊट फॉल ड्रेन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । इस क्रम में सहरसा, सासाराम, फुलवारीशरीफ, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी एवं छपरा शहरों में जल-जमाव की समस्या के निदान हेतु स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत की गयी है, जिसका कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 42 नगर निकायों में बड़े आऊट फॉल नाला निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है ।
6. नागरिकों की सुविधा : सम्राट अशोक भवन निर्माण : राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं आदि हेतु बहुदेशीय नगर भवन के रूप में सभी नगर निकायों

में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके अंतर्गत कुल कार्यरत 142 नगर निकाय में अब तक 96 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है । शेष नगर निकायों में योजना के स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है ।

7. स्ट्रीट लाईट : राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के उपक्रम ESSL के साथ राज्य सरकार का एम0ओ0यू0 हस्तांतरित किया गया है । तदोपरांत ESSL सभी नगर निकायों के बीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट हस्तांतरित करते हुये ESSL द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वे के अनुसार सभी नगर निकायों में कुल 5,70,000 स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किया जाना है, जिसमें से अबतक 3,22,466 स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किया जा चुका है । अधिष्ठापित के कार्य दिसंबर,2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

8. शवदाह गृह : कई नगर निकायों में विद्युत शवदाह गृह का जिर्णोद्धार, कंवेशन शवदाह गृह निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है । नगर पंचायत रिविलगंज में चार pyre का कंवेन्शनल शवदाह गृह निर्माण योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है । सभी जिला पदाधिकायियों से संबंधित नगर निकायों में शवदाह गृह निर्माण हेतु भूमि की विवरणी के साथ प्रस्ताव मांगा गया है।

क्रमश :

क्रमशः

टर्न-26/अंजनी-अभिनीत/06.03.2020

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री (क्रमशः) : प्रस्ताव प्राप्त होने पर निश्चित शवदाहगृह, अतिरिक्त शवदाहगृह की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(iv) बस स्टैंड - राज्य के 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिसमें से 24 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बस स्टैंड का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त पटना में अंतर्राज्यीय बस ट्रमिनल (आई0एस0बी0टी0) निर्माण कार्य जून, 2020 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

(v) जल-जीवन-हरियाली अभियान - राज्य में जल संरक्षण के दृष्टिकोण से जल-जीवन-हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पोखर, तालाब की उड़ाही, जीर्णोद्धार कुओं की उड़ाही/जीर्णोद्धार, सोख्ता निर्माण तथा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित कार्य

कराये जा रहे हैं। इस अभियान के तहत अबतक कुल 122 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा 497 योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है। उक्त के अतिरिक्त राज्य के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न जल संकट की समस्या के स्थायी निदान हेतु जल संचय कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र के तालाबों की उड़ाहीकरण एवं वृक्षारोपण की योजना स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में नगर निगम, दरभंगा के 09 तालाबों तथा मुजफ्फरपुर के 03 तालाबों के उड़ाहीकरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. हरित स्थल/पार्क - हरित स्थल/पार्क का विकास, फुटपाथ का निर्माण आदि कार्य अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के तहत भी किया जाना है। इसके तहत कुल 27 नगर निकायों में 64.94 करोड़ की पार्क निर्माण योजना स्वीकृत है।

(ख) केन्द्र प्रायेाजित योजना–

1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन(SWM) - स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत स्वच्छता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के सभी कार्यरत नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 को सभी शहरी निकायों में लागू कराया गया है तथा राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

राज्य का निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2019 का निर्माण किया गया है, जिसके तहत शहरों में निर्माण के दौरान निकलने वाले अपशिष्टों का प्रबंधन एवं निपटारा तथा दण्ड की प्रक्रिया को समाहित किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्रत्येक घर से सूखा एवं गिला कचरा को अलग-अलग कराया जा रहा है। इसके लिए सभी वार्डों में प्रत्येक घरों को नीला एवं हरा कूड़ेदान वितरित किया जा रहा है।

संग्रहित कचरों को अलग-अलग कर कम्पोस्ट पीट के माध्यम से खाद तैयार कराया जा रहा है।

सबके लिए आवास (शहरी) HFA योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में दी गयी है। इस योजना के तहत चार घटकों में शहरी क्षेत्र के आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। HFA योजना के चार घटक हैं।

(i) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण:- इस घटक के अंतर्गत राज्य के सभी 142 नगर निकायों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें 2,95,284 घरों

का निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 1,26,388 आवासीय इकाईयों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आवास का निर्माण लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाना है। इसके लिए 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रूपया) भारत सरकार एवं 50,000.00 (पचास हजार रूपया) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। योजना की मिशन अवधि 2015-22 है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक केन्द्रांश की राशि 125546.78 लाख (एक हजार दो सौ पचपन करोड़ छियालीस लाख अठहत्तर हजार रू0) एवं इसके अनुपातिक राज्यांश की राशि 36711.54 लाख (तीन सौ सरसठ करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार रू0) संबंधित नगर निकायों/लाभुकों को विमुक्त कर दिया गया है।

(ii) स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास- इस घटक के अंतर्गत स्लम वासियों को औपचारिक शहरी व्यवस्था में लाते हुए उनको पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए स्लमों के अंतर्गत भूमि की उपयोग क्षमता बढ़ाना है। स्लम पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी का चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार से 1,00,000 रू0 (एक लाख रू0) प्रति आवास की दर से अनुदान अनुमान्य होगा।

(iii) ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी- इस घटक के तहत पात्र शहरी गरीबों (EWS/LIG) द्वारा आवास के निर्माण हेतु लिये गये 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।

(iv) भागीदारी किफायती आवास (AHP)- इस घटक का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भागीदारी से बनाये जा रहे पक्का आवास हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किफायती दर पर EWS वर्ग के लिए आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार अपनी एजेंसियों अथवा उद्योग सहित निजी क्षेत्र के साथ भागीदारों के माध्यम से किफायती आवास परियोजनाओं की योजना तैयार कर सकती है। ऐसी परियोजनाओं में 1.50 लाख की दर से केन्द्रीय सहायता सभी EWS आवासों के लिए उपलब्ध होगी।

DAY-NULM- ''दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना राज्य के सभी नगर निकायों में भी लागू किया गया है। योजना के अधीन कौशल प्रशिक्षण घटक (EST & P) के अंतर्गत शहरी गरीब युवक/युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। Shelter for Urban Homeless के तहत 48 आश्रय स्थल विभिन्न नगर निकायों में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसमें से 35 का संचालन किया जा रहा है तथा 13 जगहों पर Homeless Shelter निर्माणाधीन है। इसके लिए राशि भी विमुक्त कर दी गई है। पूर्व निर्मित 41 रैन बसेरा में से 39 का संचालन किया जा रहा है एवं 2

निर्माणाधीन है। रैन बसेरा के सुचारू रूप से संचालन हेतु उसे स्वयं सहायता समूहों के संगठन Area Level Organization (ALO) से जोड़ा गया है। फुटपाथ दुकानदारों के हितों की देख-रेख हेतु बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 के तहत सभी नगर निकाय में Town Vending Committee (TVC) का गठन किया जा चुका है। नगर निकायों से प्राप्त Vending Zone निर्माण के प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कर दी गई है। सभी नगर निकायों में Town Level Federation (TLF) का गठन किया जा चुका है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना- यह योजना राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी 12 नगर निगमों (पटना, आरा, गया, बिहारशरीफ, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं छपरा), 14 नगर परिषदों (बक्सर, दानापुर, सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद, डेहरी, जमालपुर, किशनगंज, सहरसा, हाजीपुर, सिवान, बगहा, बेतिया एवं मोतिहारी) एवं नगर पंचायत, बोध गया में कार्यान्वित है ।

(इस अवसर पर भाकपा-माले के सदस्यगण अपनी सीट से बोलते हुए सदन के वेल में आ गये और इसके बाद सदन का बहिर्गमन किये)

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए स्वीकृति राशि का 50 परसेंट केन्द्र सरकार, 30 परसेंट राज्य सरकार द्वारा एवं शहरी के लिए 20 परसेंट नगर निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए स्वीकृत राशि का एक तिहाई राशि केन्द्र सरकार द्वारा, 20 परसेंट राशि संबंधित निकाय द्वारा एवं शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(क्रमशः)

टर्न-27/राजेश-राहुल/6.3.20

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री, क्रमशः AMRUT योजना के अधीन राज्य के 21 नगर निकायों (हाजीपुर, बक्सर, छपरा, जहानाबाद, बगहा, मोतिहारी, सिवान, औरंगाबाद, पूर्णिया, सासाराम, कटिहार, बेगूसराय, किशनगंज, बिहारशरीफ, आरा, दरभंगा, जमालपुर, सहरसा, बेतिया, डेहरी एवं मुंगेर) में आवासित सभी परिवारों को पेय जलापूर्ति हेतु

कुल राशि 223748.419 (बाईस करोड़ सैंतीस लाख अड़तालिस हजार चार सौ उन्नीस) लाख लागत व्यय पर 36 जलापूर्ति योजना कार्यान्वित है । इससे 579704 (पांच लाख उन्नासी हजार सात सौ चार) घरों में पेय जलापूर्ति हेतु नल का कनेक्शन दिया जायेगा ।

AMRUT योजनान्तर्गत जल-जमाव निकासी हेतु 3 शहरों मुजफ्फरपुर, पटना (बेउर मोड़ से मिठापुर) एवं भागलपुर के लिए कुल 24002.63 लाख (दो सौ चालीस करोड़ दो लाख तिरसठ हजार रू0) लागत व्यय पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना कार्यान्वित है । AMRUT योजनांतर्गत 21 शहरों के लिए कुल राशि रू0 3627.35 लाख (छत्तीस करोड़ सताईस लाख पैंतीस हजार रू0) लागत व्यय पर 29 पार्क विकास योजना कार्यान्वित है ।

AMRUT के अधीन स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की राशि 36993.64 (छत्तीस लाख निन्यानवे हजार तीन सौ चौसठ रूपया) एवं राज्यांश की राशि 22507.78 (बाईस लाख पचास हजार सात सौ अठहतर रू0) अर्थात् कुल राशि 59501.42 (उन्सठ लाख पचास हजार एक सौ बयालीस रू0) कार्यान्वित एजेंसी/नगर निकायों को विमुक्त किया जा चुका है ।

AMRUT योजनान्तर्गत कार्यान्वित सभी योजना को 31 मार्च, 2020 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित है ।

स्मार्ट सिटी योजना- इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहारशरीफ का प्रस्ताव स्वीकृत है । इसके तहत प्रत्येक शहर को पांच वित्तीय वर्षों में कुल 1000.00 (एक हजार) करोड़ राशि आवंटित की जायेगी । इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी 50:50 अनुपात में है । भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहारशरीफ शहर का स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु SPV का गठन कर लिया गया है । भागलपुर के लिए 382.00 करोड़, मुजफ्फरपुर के लिए 112.50 करोड़, पटना के लिए 380.00 करोड़ एवं बिहारशरीफ के लिए 110.00 करोड़ आवंटित की जा चुकी है ।

ADB संपोषित योजना- भागलपुर फेज-I, भागलपुर फेज-II, गया फेज-I एवं गया फेज-II ADB संपोषित जलापूर्ति योजना स्वीकृत है । उक्त योजना क्रमशः 493.00 (चार सौ तिरानवे करोड़ रू0), 253.57 करोड़ (दो सौ तिरेपन करोड़ संतावन लाख रू0), 376.21 करोड़ (चौंसठ करोड़ एकानवे लाख रू0) मात्र की लागत पर स्वीकृत है । गया सिवरेज योजना की स्वीकृति 370.67 करोड़ पर दी गई है ।

नमामि गंगे कार्यक्रम- इस कार्यक्रम के अंतर्गत NMCG द्वारा सिवरेज नेटवर्क एवं एस0टी0पी0 की 15 योजनायें, इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन एवं एस.टी.पी. की 15

योजनाएं, River Front Development की 1 योजना एवं घाट सौंदर्यीकरण की 2 योजनायें कुल 33 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसकी कुल राशि (5684.36 करोड़) है । इनमें से 22 योजनाओं (4397.24 करोड़) का कार्य प्रगति पर है एवं शेष 11 योजनाओं (1287.12 करोड़) हेतु निविदा से संबधित कार्य किया जा रहा है । स्वीकृत 33 योजनाओं में से 12 योजनाएं पटना शहर का है, जिसकी कुल राशि (3574.42 करोड़) है, इनमें से सभी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । इन योजनाओं के पूर्ण होने से गंगा में निस्तारित होने वाले गंदे पानी एवं सिवरेज से मुक्ति मिलेगी जिससे गंगा का पानी निर्मल होगा ।

पटना मेट्रो रेल परियोजना- पटना मेट्रो रेल परियोजना 13365.77 करोड़ (तेरह हजार तीन सौ पैंसठ करोड़ सतहत्तर लाख रू0) की अनुमानित लागत से पटना मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2019 को प्रदान की गयी है । यह परियोजना भारत सरकार के मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के तहत Equity Sharing Model के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है । इसके लिए SPV (Special Purpose Vehicle) पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 का गठन किया गया है ।

केन्द्र राज्य एवं पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 के बीच योजना के क्रियान्वयन हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया गया है । उल्लेखनीय है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के कुल लागत का 20-20 प्रतिशत हिस्सा Equity........

अध्यक्ष: अब केवल मूल जो हेडिंग्स है, जो योजनाएं हैं, उसका जिक्र करते हुए, आपका सबसे महत्वपूर्ण अंश अंत में है ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार की उपलब्धि- अधिसूचित मास्टर प्लान, 2031 के क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या- 392, दिनांक-11.09.2014 के आलोक में पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है । पटना मास्टर प्लान, 2031 का क्षेत्रफल 1167 वर्ग कि0मी0 है, जिसमें 7 शहरी क्षेत्र जिसमें (पटना, नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारी नगर परिषद, मनेर नगर पंचायत, नौबतपुर नगर पंचायत एवं फतुहा नगर पंचायत) तथा 575 राजस्व ग्राम है । इसके अंतर्गत 13 सी0डी0 ब्लॉक (बिहटा, दानापुर, खगौल, धनरूआ, दनियांवा, फतुहा, खुशरूपुर, मनेर, मसौढ़ी, नौवतपुर, पटना ग्रामीण, फुलवारी, पुनपुन एवं सम्पतचक है) है ।

अध्यक्ष: अब, बस एक मिनट में खत्म करना है । यह सब आपका प्रोसेडिंग्स का पार्ट बन जायेगा, केवल अंत वाला जो है, कश्ती चलाने वालों वह बता दीजिए ।

(माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः अतएव, नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए द्वितीय वर्ष 2020-21 के लिए व्यय वहन हेतु कुल 721371.54 लाख (बहत्तर अरब तेरह करोड़ एकहत्तर लाख चौवन हजार रू0) का उपबंधा मांग संख्या-48 के अंतर्गत प्रस्तुत है । जिसकी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है । इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 379571.54 लाख (सैंतीस अरब पनचान्वे करोड़ एकहत्तर लाख चौवन हजार रूपये) तथा स्कीम व्यय के लिए 341800.00 लाख (चौंतीस अरब अठारह करोड़ रू0) का प्रस्ताव है ।

मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी प्रदान की जाय ।

''कश्ती चलाने वालों ने जब पतवार दी हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें ।
फिर भी दिखाया है हमने और फिर दिखा देंगे सबको,
इन हालातों में भी आता है दरिया पार करने हमें ।''

महोदय, अब मैं आग्रह करुंगा माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी से कि वे अपना कटौती प्रस्ताव को वापस करने की कृपा करें ।

टर्न-28/सत्येन्द्र-मुकुल/06.03.2020

अध्यक्षः सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। अब मैं कटौती प्रस्ताव को लेता हूॅं। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूॅं।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

'' नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 72,13,71,54,000/-(बहत्तर अरब तेरह करोड़ इकहत्तर लाख चौवन हजार)रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
मांग स्वीकृत हुई।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 06 मार्च, 2020 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 31 है। अगर सदन की सहमति हो तो इसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, हर्ष एवं उल्लास का पर्व होली आसन्न है साथ ही आज बिहार सहित पूरा देश ही नहीं सम्पूर्ण विश्व कोरोना वायरस के आतंक से पीड़ित है सामूहिक मिलन से लेकर आम दिनचर्या में भी अनेक प्रकार की सतर्कता बरतने का परामर्श एडवाइजरी एवं नयाचार प्रोटोकोल विभिन्न सरकारों द्वारा जारी किये गये हैं इन सब के प्रति आपको आगाह करते हुए आप सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्पूर्ण बिहारवासियों को मैं सदन की ओर से इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ । मेरी यह कामना है यह त्योहार समस्त बिहारवासियों के जीवन में खुशहाली लाये एवं मानवता को इस रोग के आतंक से मुक्ति दिलाये ।

इसी खैर अंदेशी के साथ सभा की बैठक सोमवार दिनांक 16 मार्च, 2020 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य के आर्थिक विकास में शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार अपने संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत् एवं निरन्तर प्रयत्नशील है। बिहार में शहरीकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। विगत वर्षों में शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई बहुआयामी कदम उठाये गये है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन **12 नगर निगम, 49 नगर परिषद एवं 81 नगर पंचायत** कार्यरत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभाग के द्वारा विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एवं आम लोगों की सुविधाओं के आलोक में संचालित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में से **"तीन निश्चय" माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी** के कुशल नेतृत्व में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वयन की जा रही है। ये योजना निम्नवत है :—

1. <u>मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना</u> :— राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित प्रत्येक परिवार को शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने हेतु **मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना** लागू है। इस योजनान्तर्गत स्थानीय नगर निकाय, बुडको एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर निकायों में प्रत्येक परिवार को निःशुल्क नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. <u>मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना</u> :— राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित परिवारों को पक्की नाली–गली से जोड़ने हेतु **मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना** लागू है। योजना के प्रथम चरण में कच्ची नाली–गलियों के पक्कीकरण की योजनाओं को लिया जा रहा है तथा द्वितीय चरण में पूर्व से निर्मित नाली–गली के जीर्णोद्धार की योजनायें लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. <u>शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)</u> :— स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत नगर निकाय क्षेत्र में स्थित सभी शौचालय विहीन घरों में शौचालय की व्यवस्था के लिए योजना की मंजुरी प्रदान की गई है। यह योजना राज्य सरकार के **शौचालय निर्माण घर का सम्मान** निश्चय में भी शामिल है।

- **जल संरक्षण (Water Preservation)** :– राज्य में घटते भू–जल स्तर एवं जल संकट को ध्यान में रखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तत्कालीक एवं दीर्घकालिक योजनाओं का कार्यान्चयन किया जा रहा है। तात्कालिक सामाधान हेतु सभी नगर निकायों में प्रत्येक 02 वार्ड पर 01–01 Stainless Steel Water Tanker, वैसे वार्ड जहाँ ट्यूबवेल के रूप में Water Source उपलब्ध है, परन्तु पाईप लाईन नहीं बिछाया जा सका है, तो वैसे वार्डों में तत्काल सामुदायिक Stand Post के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
- दीर्घकालिक सामाधान हेतु राज्य के सभी शहरी निकायों से तालाबों/पोखरों के उड़ाही एवं वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना, Ground Water Recharge हेतु Water Sources के नजदीक सोखता के निर्माण, पार्क, खेल के मैदान एवं अन्य खुले सार्वजनिक स्थानों पर भी Ground Water Recharge हेतु सोख्ता निर्माण, Rain Water Harvesting System को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु Bihar Building Bye-laws में प्रावधान किया गया है।

राज्य योजना के अन्तर्गत Storm Water Drainage/Out Fall नाला निर्माण :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में छोटे नालियों का निर्माण मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना से हो रहा है परन्तु बड़े Out Fall Drain का निर्माण नगर निकायों में आधारभूत संरचना के अभाव में निश्चय योजना से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप नगर निकायों को Out Fall Drain का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इस क्रम में सहरसा, सासाराम, फुलवारीशरीफ, सुपौल, दरभंगा, मुधबनी एवं छपरा शहरों में जल जमाव के समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना स्वीकृत की गयी है, जिसका कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 42 नगर निकायों में बड़े Out Fall नाला निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है।

नागरिक सुविधा के अन्तर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आयोजन आदि हेतु बहुउद्देशीय नगर भवन के रूप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके अन्तर्गत कुल कार्यरत 142 नगर निकायों में से अबतक 96 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। शेष नगर निकायों में योजना के स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

<u>स्ट्रीट लाईट</u> :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के उपक्रम EESL के साथ राज्य सरकार का MOU हस्ताक्षरित किया गया है। तदोपरांत EESL एवं सभी नगर निकायों के बीच Service Level Agreement हस्ताक्षरित करते हुए EESL द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सर्वे के अनुसार सभी नगर निकायों में कुल 5,70,000 (पाँच लाख सत्तर हजार) स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किया जाना है, जिसमें से अबतक 3,22,466 (तीन लाख बाईस हजार चार सौ छयासठ) स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किया जा चुका है। अधिष्ठापन का कार्य **दिसम्बर, 2020** तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

<u>शवदाह गृहः</u>– कई नगर निकायों में विद्युत शवदाह गृहों का जीर्णोद्धार तथा Conventional शवदाह गृह निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। नगर पंचायत, रिविलगंज में 04 Pyre का Conventional शवदाह गृह निर्माण योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। सभी जिला पदाधिकारियों से जिले से संबंधित नगर निकायों में शवदाह गृह निर्माण हेतु भूमि की विवरणी के साथ प्रस्ताव माँगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर अतिरिक्त शवदाह गृहों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

<u>बस स्टैंड</u> :– राज्य के 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिसमें से 24 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बस स्टैंड का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त पटना में अंर्तराज्यीय बस ट्रर्मिनल (ISBT) निर्माण कार्य जून, 2020 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

<u>जल–जीवन–हरियाली अभियान</u> :– राज्य में जल संरक्षण के दृष्टिकोण से जल–जीवन–हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पोखर/तालाब की उड़ाही/जीर्णोद्धार, कुओं की उड़ाही/जीर्णोद्धार, सोख्ता निर्माण तथा Roof Top Rain Water Harvesting से संबंधित कार्य कराये जा रहे है। इस अभियान के तहत अबतक कुल 122 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है तथा 497 योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है। उक्त के अतिरिक्त राज्य के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न जल संकट की समस्या के स्थायी निदान हेतु जल संचय कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र के तालाबों की उड़ाहीकरण एवं वृक्षारोपण की योजना स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में नगर निगम, दरभंगा के 09 तालाबों तथा मुजफ्फरपुर के 03 तालाबों के उड़ाहीकरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

<u>हरित स्थल/पार्क</u> :– हरित स्थल/पार्क का विकास, फुटपाथ का निर्माण आदि कार्य अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के तहत भी किया जाना है। इसके तहत कुल 27 नगर निकायों में **64.94** करोड़ की पार्क निर्माण योजना स्वीकृत है।

<u>केन्द्र प्रायोजित योजना</u> :–

1 <u>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)</u> :– स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत स्वच्छता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के सभी कार्यरत नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

- ❖ **बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018** को सभी शहरी निकायों में लागू कराया गया है तथा राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
- ❖ राज्य के **निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2019** का निर्माण किया गया है, जिसके तहत शहरों में निर्माण के दौरान निकलने वाले अपशिष्टों का प्रबंधन एवं निपटारा तथा दण्ड की प्रक्रिया को समाहित किया गया है।
- ❖ **ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016** के अन्तर्गत प्रत्येक घर से सूखा एवं गिला कचरा को अलग कराया जा रहा है। इसके लिए सभी वार्डो में प्रत्येक घरों को निला एवं हरा कुड़ेदान वितरित किया जा रहा है। संग्रहित कचरों को अलग–अलग कर कम्पोस्ट पीट के माध्यम से खाद तैयार कराया जा रहा है।

2 <u>**सबके लिए आवास (शहरी) HFA**</u> :– इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जून 2015 में दी गयी है। इस योजना के तहत चार घटकों में शहरी क्षेत्र के आवास विहीन परिवारों को कम से कम **30** वर्गमीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। HFA योजना के चार घटक है:–

(i) **लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण** :– इस घटक के अंतर्गत राज्य के सभी 142 नगर निकायों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें **2,95,284** घरों का निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से **1,26,388** आवासीय इकाईयों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आवास का निर्माण लाभूकों द्वारा स्वयं किया जाना है। इसके लिए **1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रू0)** भारत सरकार एवं **50,000.00 (पचास हजार रू0)** राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। योजना की मिशन अवधि 2015–22 है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक केन्द्रांश की राशि **125546. 78 लाख (एक हजार दो सौ पचपन करोड़ छियालीस लाख अठहत्तर हजार रू०)** एवं इसके अनुपातिक राज्यांश की राशि **36711.54 लाख (तीन सौ सरसठ करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार रू०)** संबंधित नगर निकायो/लाभुकों को विमुंक्त कर दिया गया है।

(ii) **स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास**–इस घटक के अन्तर्गत स्लम वासियों को औपचारिक शहरी व्यवस्था में लाते हुए उनको पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए स्लमों के अन्तर्गत भूमि की उपयोग क्षमता बढ़ाना है। स्लम पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी का चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार से **1,00,000/– (एक लाख रू0)** प्रति आवास की दर से अनुदान अनुमान्य होगा।

(iii) **ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी**– इस घटक के तहत पात्र शहरी गरीबों (EWS/LIG) द्वारा आवास के निर्माण हेतु लिये गये **6.00** लाख तक के गृह ऋण पर ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।

(iv) **भागीदारी में किफायती आवास (AHP)** –इस घटक का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भागीदारी से बनाये जा रहे पक्का आवास हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किफायती दर पर **EWS** वर्ग के लिए आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार अपनी एजेंसियों अथवा उद्योग सहित निजी क्षेत्र के साथ भागीदारों के माध्यम से किफायती आवास परियोजनाओं की योजना तैयार कर सकती है। ऐसी परियोजनाओं में **1.50** लाख की दर से केन्द्रीय सहायता सभी EWS आवासों के लिए उपलब्ध होगी।

3 **<u>DAY-NULM</u> :–** "दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना राज्य के सभी नगर निकायों में भी लागू किया गया है। योजना के अधीन कौशल प्रशिक्षण घटक (EST&P) के अन्तर्गत शहरी गरीब युवक/युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। Shelter for Urban Homeless के तहत **48** आश्रय स्थल (Homeless Shelter) विभिन्न नगर निकायों में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसमे से **35** का संचालन किया जा रहा है तथा **13** जगहों पर Homeless Shelter निर्माणाधीन है। इसके लिए राशि भी विमुक्त कर दी गई है। पूर्व निर्मित **41** रैन बसेरा में से **39** का संचालन किया जा रहा है एवं **02** निर्माणाधीन है। रैन बसेरा के सुचारू रूप से संचालन हेतु उसे स्वयं सहायता समूहों के संगठन Area Level Organization (ALO) से जोड़ा गया है। फुटपाथ दुकानदारों के हितो की देख–रेख हेतु **"बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017"** के तहत सभी नगर निकाय में Town Vending Committee (TVC) का गठन किया जा चुका है। नगर निकायों से प्राप्त Vending Zone निर्माण के प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कर दी गई है। सभी नगर निकायों में Town Level Federation (TLF) का गठन किया जा चुका है।

4 <u>अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना</u> :– यह योजना राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी 12 नगर निगमों (पटना, आरा, गया, बिहारशरीफ, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं छपरा), 14 नगर परिषदों (बक्सर, दानापुर, सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद, डेहरी, जमालपुर, किशनगंज, सहरसा, हाजीपुर, सिवान, बगहा, बेतिया एवं मोतिहारी) एवं नगर पंचायत, बोधगया में कार्यान्वित है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए स्वीकृत राशि का 50% केन्द्र सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं 20% संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए स्वीकृत राशि का एक तिहाई राशि केन्द्र सरकार द्वारा, 20% राशि संबंधित नगर निकाय द्वारा एवं शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

AMRUT योजना के अधीन राज्य के 21 नगर निकायों (हाजीपुर, बक्सर, छपरा, जहानबाद, बगहा, मोतिहारी सिवान, औरंगाबाद, पूर्णिया, सासाराम, कटिहार, बेगूसराय, किशनगंज, बिहारशरीफ, आरा, दरभंगा, जमालपुर, सहरसा, बेतिया, डेहरी एवं मुंगेर) में आवासित सभी परिवारों को पेयजलापूर्ति हेतु कुल राशि **223748.419 (बाईस करोड सैतीस लाख अड़तालिस हजार चार सौ उन्नीस)** लाख लागत व्यय पर 36 जलापूर्ति योजना कार्यान्वित है। इससे **579704 (पाँच लाख उन्नासी हजार सात सौ चार)** घरों में पेयजलापूर्ति हेतु नल का कनेक्शन दिया जाएगा।

AMRUT योजनान्तगर्गत जल जमाव निकासी हेतु 03 शहरों मुजफ्फरपुर, पटना (बेउर मोड़ से मिठापुर) एवं भागलपुर के लिए कुल **24002.63 लाख (दो सौ चालीस करोड़ दो लाख तिरसठ हजार रू०)** लागत व्यय पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना कार्यान्वित है। AMRUT योजनान्तर्गत 21 शहरों के लिए कुल राशि रू0 **3627.35 लाख (छतीस करोड़ सताईस लाख पैतीस हजार रू०)** लागत व्यय पर 29 पार्क विकास योजना कार्यान्वित है।

AMRUT के अधीन स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु केन्द्रांश की राशि **36993.64 (छतीस लाख निनावे हजार तीन सौ चौसठ रू0)** एवं राज्यांश की राशि **22507.78 (बाईस लाख पचास हजार सात सौ अठतर रू0)** अर्थात कुल राशि **59501. 42 (उन्नसठ लाख पचास हजार एक सौ बयालीस रू0)** कार्यान्वित एजेंसी/नगर निकायों को विमुक्त किया जा चुका है।

AMRUT योजनान्तर्गत कार्यान्वित सभी योजना को **31 मार्च, 2020** तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित है।

5 **<u>स्मार्ट सिटी योजना</u>** :– इस योजना के अन्तर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहारशरीफ का प्रस्ताव स्वीकृत है। इसके तहत प्रत्येक शहर को पाँच वित्तीय वर्षों में कुल **1000.00 (एक हजार) करोड़** राशि आवंटित की जायेगी। इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी **50:50** अनुपात में है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु SPV का गठन कर लिया गया है। भागलपुर के लिए **382.00** करोड़, मुजफ्फरपुर के लिए **112.50** करोड़, पटना के लिए **380.00** करोड़ एवं बिहारशरीफ के लिए **110.00** करोड़ आवंटित की जा चुकी है।

6 **<u>ADB संपोषित योजना</u>** :– भागलपुर फेज–I, भागलपुर फेज–II, गया फेज–I एवं गया फेज–II ADB संपोषित जलापूर्ति योजना स्वीकृत है। उक्त योजना क्रमशः **493.00 करोड़ (चार सौ तिरानवे करोड़ रू०)** मात्र, **253.57 करोड़ (दो सौ तिरेपन करोड़ संतावन लाख रू०)** मात्र, **376.21 करोड़ (तीन सौ छिहत्तर करोड़ एकीस लाख रू०)** मात्र एवं **64.91 करोड़ (चौंसठ करोड़ एकानवे लाख रू०)** मात्र की लागत पर स्वीकृत है। गया सिवरेज योजना की स्वीकृति **370.67** करोड़ पर दी गई है।

7 **<u>नमामि गंगे कार्यक्रम</u>** :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **NMCG** द्वारा सिवरेज नेटवर्क एवं एस०टी०पी० की **15** योजनायें, इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन एवं एस.टी.पी. की **15** योजनायें, River Front Development की **01** योजना एवं घाट सौंदर्यीकरण की **02** योजनायें कुल **33** योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसकी कुल राशि **(5684.36 करोड़)** है। इनमें से 22 योजनाओं **(4397.24 करोड़)** का कार्य प्रगति पर है एवं शेष **11** योजनाओं **(1287.12 करोड़)** हेतु निविदा से संबंधित कार्य किया जा रहा है। स्वीकृत **33** योजनाओं में से **12** योजनाएँ पटना शहर का है, जिसकी कुल राशि **(3574.42 करोड़)** है, इनमें से सभी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से गंगा में निस्तारित होने वाले गंदे पानी एवं सिवरेज से मुक्ति मिलेगी जिससे गंगा का पानी निर्मल होगा।

8 <u>पटना मेट्रो रेल परियोजना : –</u>

पटना मेट्रो रेल परियोजना **13365.77** करोड़ **(तेरह हजार तीन सौ पैंसठ करोड़ सतहत्तर** लाख रू०) की अनुमानित लागत से पटना मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक–**13** फरवरी, **2019** को प्रदान की गयी है। यह परियोजना भारत सरकार के मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के तहत Equity Sharing Model के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए SPV (Special Purpose vehicle) पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० का गठन किया गया है।

➢ केन्द्र, राज्य एवं पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० के बीच योजना के क्रियान्वयन हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। उल्लेखनीय है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के कुल लागत का 20–20 प्रतिशत हिस्सा equity के रूप में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा शेष 60 प्रतिशत राशि Soft Loan के रूप में वाह्य लैटरल/मल्टी लैटरल वित्तीय संस्थाओं जायका (JICA) द्वारा किया जायेगा। इस हेतु भारत सरकार के Department of Economic Affairs से अनुरोध किया गया है। जमीन की लागत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का खर्च राज्य सरकार द्वारा अकेले वहन किया जाना है। प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पटना में दो कोरिडोर का चयन किया गया है। जिनकी कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है।

➢ ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर, जो दानापुर से प्रारंभ होकर जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए मीठापुर तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 16.94 कि०मी० है।

➢ नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर, जो पटना रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर आकाशवाणी, गॉधी मैदान अशोक राजपथ, मोइनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्रनगर स्टेशन, कुम्हरार, जीरो माइल होते हुए न्यू I.S.B.T तक जाती है।

➢ कुम्हरार के पुरातात्विक स्थल होने के कारण कॉरिडोर दो के इस Alignment को राजेन्द्रनगर से भूतनाथ, मलाही पकड़ी बाईपास, खेमनीचक, जीरो माइल होते हुए न्यू I.S.B.T तक बदलाव किया जाना प्रस्तावित है।

➢ योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 50.00 करोड़ रू0 एवं राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल 63.00 करोड़ उपलब्ध करायी जा चुकी है।

➢ योजना के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) को Nomination Basis पर कार्य आवंटित किया गया है, इस हेतु DMRC के साथ दिनांक–25.09.2019 को 482.87 करोड़ के शुल्क पर एकरारनामा किया गया है। DMRC द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण कर मिट्टी की जाँच की जा रही है।

➢ एकरारनामा के अनुसार DMRC को परामर्शी शुल्क के रूप में Mobilization अग्रिम लगभग 27.00 करोड़ राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष के अगले दो तिमाही में लगभग 50.00 करोड़ दिया जाना है। इसके अलावे योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य पर होने वाले व्यय के लिए DMRC द्वारा समय–समय पर माँग की गई राशि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जानी है। इसी संदर्भ में 100.00 करोड़ अतिरिक्त उद्व्यय के रूप में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त किया गया है।

<u>नगरीय प्रशासन</u> :–

- नगर निकायों में बेहतर प्रशासन तथा नागरिक सुविधाओं में वृद्धि तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए निम्नांकित पद सृजित किये गये हैं :–

  (i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी – 137

  (ii) नगर प्रबंधक – 227

- नगर निकायों में आधारभूत संरचनाओं के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन का गठन किया गया है, जिसके तहत अतिरिक्त पदों के सृजन सहित बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों का विहार शहरी आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड (बुडको) में पूर्ण रूप से विलयन किया जा चुका है।

- बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में विभिन्न कोटि के अभियंताओं के सृजित 893 पदों के विरूद्ध नियुक्ति एवं सेवाओं के अधिप्राप्ति, कार्यो के निष्पादन, पर्यवेक्षण में सुगमता के उद्देश्य से सभी पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित किया गया है।

- नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत अभियंताओं/कर्मचारियों के स्वीकृत पद रिक्त रहने के कारण कार्यों के सुगमतापूर्वक निष्पादन में उत्पन्न कठिनाईयों के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।

- सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के रिक्त 255 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित है।

- नगर निकायों के बेहतर प्रशासन हेतु कुल 108 कार्यपालक पदाधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचना के आलोक में उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कुल–108 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है एवं नियमानुसार उनके पदस्थापन की कार्रवाई की जा चुकी है। शेष पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु विभागीय अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गयी है।

- नगर प्रबंधक के कुल स्वीकृत 227 पदों के विरूद्ध रिक्त 163 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अधियाचना परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को प्रेषित किया गया है।

- नगर निकाय सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्वायत्त स्वशासी निकाय एवं व्यवस्थित शहरीकरण के केन्द्र हैं। नगर निकायों के प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं क्षेत्रीय विकास हेतु नगर निकायों में पदों का सृजन निम्नवत् किया गया है:–
    - **कुल–82 नगर पंचायत में विभिन्न प्रकार के कुल–1754 पदों का सृजन**
    - **कुल–49 नगर परिषद् में विभिन्न प्रकार के कुल–2764 पदों का सृजन**
    - **कुल–11 नगर निगम में विभिन्न प्रकार के कुल–2663 पदों का सृजन**
    - **पटना नगर निगम में विभिन्न प्रकार के कुल–695 पदों का सृजन**
    - **नगरपालिका प्रशासन निदेशालय (मुख्यालय) में विभिन्न प्रकार के कुल–57 पदों का सृजन**
    - **नगरपालिका प्रशासन निदेशालय में समूह 'क' एवं 'ख' के पदों एवं पदों की संवर्गीय स्थिति सहित प्रोन्नति का पद भी निर्धारित किया गया है।**

पटना शहर को जल–जमाव से मुक्त रखने हेतू किये जा रहे कार्य :– पटना शहर में विगत वर्ष, 2019 में जल–जमाव के आलोक में राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा समर्पित सुझाव के आलोक में अगामी मौनसून, 2020 जल–जमाव के निराकरण हेतु बुडको द्वारा निम्न कार्रवाई की जा रही है :–

➢ पटना, दानापुर एवं खगौल नगर निकायों के ड्रेनेज सिस्टेम को दुरूस्त करने हेतु परामर्शी का चयन किया जा रहा हैं परामर्शी द्वारा तीनों नगर निकायों में पूर्व से अवस्थित ड्रेनेज सिस्टम का अध्यन करते हुए तीनों नगर निकायों हेतु ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा एवं जल–जमाव की समस्या नहीं हो इस हेतु Short Term, Mid Term एवं Long Term तीनों स्तर पर सामाधान हेतु आवश्यक संरचनाओं का प्रावधान करते हुए डी०पी०आर० का निर्माण किया जायेगा।

➢ वर्त्तमान में अवस्थित सभी 39 ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन के असैनिक संरचनाओं की मरम्मति हेतु विभाग से 985.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। सभी 39 ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन के सभी मोटर, पम्प, ट्रॉन्सफॉर्मर, स्वीचपैनल की व्यापक मरम्मति के साथ–साथ श्रम एवं सामग्री सहित 03 वर्षों के लिए सम्पोषण एवं संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

➢ भारी वर्षा के कारण ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन परिसर में जल–जमाव की समस्या नहीं हो इस हेतु ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन परिसर में पम्प हाउस के दरवाजा पर उच्चतम जल स्तर तक ढ़लान तैयार किया जा रहा है, ताकि बाहर से पानी नहीं घुसे। साथ ही साथ सभी

ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन भवनों की व्यापक मरम्मति एवं सभी ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन के साथ एक विश्राम कक्ष तथा एक शौचालय निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

➢ सैदपुर, रामपुर, संदलपुर, आर०एम०आर०आई०, बहादुरपुर टी०वी० टावर ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन के बगल में नया ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

➢ पटना एवं आस–पास के क्षेत्रों में जल–जमाव से बचाव के लिए 21 अन्य स्थलों (बाजार समिति (बकरी बाजार), शीतलामता मंदिर के पास, करमलीचक क्षेत्र में बिग हॉस्पिटल के पास करमलीचक प्रेम कुंज टोल प्लाजा से 600 मीटर पहले, नंदलाल छपरा चौक, जगनपुरा, दशरथा, कुम्हरार श्रीनगर कॉलोनी, बेउर–बतौड़ा, सबरीनगर (वार्ड नं०– 03), रूपसपुर, मौर्य विहार बेउर अखाड़ा, राजीव नगर नाला का प्रारंभिक स्थल, दीघा पुराना थाना, पर अरथाई DPS तथा पूर्वी रामकृष्ण नगर, कृष्णा निकेतन, जकरियापुर, दानापुर–खगौल क्षेत्र में पटना नगर के पश्चिम, घुड़दौड़–नेहरू पथ जंक्शन के पास (दानापुर), करोड़ीचक (फुलवारीशरीफ), इसोपुर ब्रह्म स्थान (फुलवारीशरीफ) पर आवश्यकतानुसार मोबाईल पम्प का उपयोग) पर जल निकासी की तात्कालिक योजना है।

<u>**बिहार राज्य आवास बोर्ड की परियोजनाएं एवं उपलब्धियाँ**</u> :– बिहार राज्य आवास बोर्ड, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के तत्वाधान में संचालित होती हैं। बोर्ड बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम 1982 एवं बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू–सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) नियमावली 1983 द्वारा विनियमित होती है। बिहार राज्य आवास बोर्ड राज्य के आम नागरिकों को बेहतर एवं किफायती आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करने के परिलक्षित उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

आवास बोर्ड के खाली भूखण्डों में किफायती आवासीय नीति के तहत Affordable House के निर्माण के लिए भी नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नियुक्त Transaction Advisor IFC द्वारा सर्वे कर परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

बोर्ड के निम्न सात परियोजना प्रस्तावित हैं:–

1. बरारी, भागलपुर आवासीय परियोजना के तहत 272 फ्लैंटों का निर्माण।
2. बहादुरपुर अवस्थित सेक्टर–5 में 10.10 एकड़ भूखण्ड पर 1596 आवासीय फ्लैंटों का निर्माण।
3. लोहियानगर अवस्थित एल सेक्टर–5 में 1.71 एकड़ भूखण्ड एवं हनुमाननगर अवस्थित 0.55 एकड़ भूखण्ड पर Commercial Complex का निर्माण।
4. बहादुरपुर में पुरानी योजनाओं के स्थान पर 74.41 एकड़ भूखंड पर 8454 फ्लैंटों एवं वाणिज्यिक संरचनाओं का निर्माण।

5. दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर में पुरानी योजनाओं के स्थान पर 21.75 एकड़ भूखण्ड पर 1496 फ्लैटों एवं वाणिज्यिक संरचनाओं का निर्माण।
6. कटारी एवं मुस्तफाबाद, गया में पुरानी योजनाओं के स्थान पर 125 एकड़ भूखंड पर 12696 फ्लैंटों एवं वाणिज्यिक संरचनाओं का निर्माण।
7. लोहियानगर (कंकड़बाग) अवस्थित सेक्टर– S, T एवं U में बने पुराने रेंटल फ्लैट्स, वीकर, स्लम तथा जनता फ्लैट्स के स्थान पर लगभग 32.35 एकड़ भूमि में लगभग 2488 फ्लैटों और वाणिज्यिक संरचनाओं का पुनर्निमाण।

चहारदिवारी निर्माण कार्य

बिहार राज्य आवास बोर्ड के अन्तर्गत अनावंटित पड़े खाली भूखण्डों के संरक्षण हेतु चहारदिवारी निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, तथा इसके निमित्त प्राप्त प्राक्कलनों के आलोक में निविदा प्रकाशित की जा चुकी है।

नगर तथा क्षेत्रीय निदेशन संगठन (TCPO) की उपलब्धियाँ :– नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन द्वारा मुख्यतः राज्य के शहरी क्षेत्रों एवं शहरीकरण की क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास हेतु Geographic Information System (GIS) आधारित मास्टर प्लान एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी का कार्य, बिहार भवन उपविधि, 2014 के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य, आयोजना प्राधिकारों तथा बिहार भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित किया जा रहा है।

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार की उपलब्धि :–

अधिसूचित मास्टर प्लान, 2031 को क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या–392, दिनांक–11.09.2014 के आलोक में पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है। पटना मास्टर प्लान, 2031 का क्षेत्रफल 1167 वर्ग कि०मी० है, जिसमें 7 शहरी क्षेत्र जिसमें (पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारी नगर परिषद, मनेर नगर पंचायत, नौबतपुर नगर पंचायत एवं फतुहा नगर पंचायत) तथा 575 राजस्व ग्राम है। इसके अन्तर्गत 13 सी०डी० ब्लॉक (बिहटा, दानापुर खगौल, धनरूआ, दनियाँवा, फतुहा, खुशरूपुर, मनेर, मसौढ़ी, नौबतपुर, पटना ग्रामीण, फुलवारी, पुनपुन एवं सम्पतचक) है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में नगर विकास एवं आवास विभाग शहरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कृतसंकल्पित है।

अतएव नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के व्यय वहन हेतु कुल **721371.54** लाख (बहत्तर अरब तेरह करोड़ एकहत्तर लाख चौवन हजार रू०) का उपबंध माँग संख्या– 48 के अंतर्गत प्रस्तुत है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए **379571.54** लाख (सैंतीस अरब पनचानवे करोड़ एकहत्तर लाख चौवन हजार रुपये) तथा स्कीम व्यय के लिए **341800.00** लाख (चौंतीस अरब अठारह करोड़ रू०) का प्रस्ताव है।

मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी प्रदान की जाय।